RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 279
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 अगस्त, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

भारत में रोहिंग्या घुसपैठ कई गुना बढ़ गई है

राष्ट्रीय-10

शाह का दावा, केरल को चेताया था, मुख्यमंत्री ने किया इनकार

वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद बुधवार को राहत और बचाव कार्य जारी रहा।

●भारी भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 200 पार पहुंची

कुमार चेल्लपन। नई दिल्ली/कोच्चि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केरल में भारी बारिश की अग्रिम चेतावनी राज्य सरकार को वायनाड में घातक भूस्खलन से कम से कम एक सप्ताह पहले जारी की गई थी, जिसने मौत और विनाश के भारी निशान छोड़े हैं।

दूसरी ओर केरल सरकार ने आरोप लगाया कि मौसम विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियां वायनाड जिले में हुई बारिश और भूस्खलन के बारे में प्रारंभिक चेतावनी जारी करने में बुरी तरह विफल रहीं। शाह ने संसद को नवीनतम जानकारी देते हुए कहा, 18 जुलाई को अनुमान लगाया गया था कि केरल के पश्चिमी तट पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। 25 जुलाई को पूर्वानुमान था कि भारी बारिश होगी। 23 जुलाई को ही एनडीआरएफ की आठ टीमों को इस क्षेत्र में भेजा गया था। केंद्र ने किसी भी आपदा की स्थिति में केरल सरकार की सहायता के लिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की आठ टीमें भेजी थीं।

गृह मंत्री ने कहा, जब वायनाड में भूस्खलन हुआ, तो एनडीआरएफ टीमों को कलेक्टर से हरी झंडी मिल गई और राहत अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। शाह ने कहा कि लगभग छह साल पहले, आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। मंगलवार को हुए भारी भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बुधवार शाम तक 200 का आंकड़ा पार कर जाने के बावजूद, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अमित शाह (शेष पेज 9)

कोचिंग सेंटरों को नरेला और रोहिणी में स्थानांतरित करेंगे

●तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के बाद दिल्ली सरकार बना रही योजना

राजेश कुमार। नई दिल्ली

नई दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हाल ही में तीन छात्रों की डूबने से हुई मौत के बाद धरना दे रहे छात्रों से बातचीत करता एक पुलिसकर्मी। फोटोः रंजन डिमरी

पुराने राजिंदर नगर इलाके में राऊज आईएएस अध्ययन केंद्र के बेसमेंट में डूबने से तीन आईएएस उम्मीदवारों की दुखद मौत के बाद दिल्ली सरकार नरेला और रोहिणी में कोचिंग सेंटरों को स्थानांतरित करने और इसे एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कोचिंग सेंटरों के नियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से सुनियोजित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की कार्ययोजना तैयार करेगी। राउज कोचिंग सेंटर के पास नागरिक अधिकारियों और 'कोचिंग माफिया' के खिलाफ लगातार चौथे दिन आईएएस अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने बुधवार को तीन छात्रों की मौत के मामले में नगर निकाय की विफलता को स्वीकार करते हुए कहा कि इसमें गंभीर संरचनात्मक मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

पुराने राजिंदर नगर में यूपीएससी कोचिंग हब में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, वरिष्ठ नागरिक निकाय अधिकारी ने कहा कि घटना के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है और एजेंसी को अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने वाले छात्रों ने थॉमस के साथ बैठक के बाद बुधवार सुबह इसे समाप्त कर दिया। सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को कोचिंग केंद्रों में वसूले जाने वाले अत्यधिक किराये और कर चोरी के लिए अनिवार्य नकद लेनदेन पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि एक पोर्टल स्थापित किया जाए, जिसमें शहर के सभी कोचिंग संस्थानों और नामांकित छात्रों के आधार आधारित लॉग-इन क्रेडेंशियल हों। इससे एक पारदर्शी डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी जो सरकार को समय-समय पर नीतिगत ढांचे को आकार देने में मदद करेगी।

समिति में कोचिंग संस्थानों के पांच से छह प्रतिनिधि, छात्र और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति सभी मापदंडों को पूरा करते हुए एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विनियमन, (शेष पेज 9)

ईरान में हमास नेता हनिएह की हत्या, इजराइल पर शक

पीटीआई। बेरूत

ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद हमास नेता इस्माइल हनिएह की हत्या कर दी गई। ईरान और उग्रवादी समूह हमास ने बुधवार तड़के यह जानकारी दी। हमास ने अपने राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख की मौत के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वह हनिएह की हत्या की जांच कर रहा है। उसने यह नहीं बताया कि हत्या कैसे हुई और हनिएह को किसने मारा। फिलहाल किसी ने भी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसका शक इजराइल पर है, जिसने सात अक्टूबर को देश में हुए अप्रत्याशित हमले को लेकर हनिएह और हमास के विभिन्न कमांडरों को मारने का संकल्प लिया था। इजराइल ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमास ने बताया कि हनिएह समूह के अन्य अधिकारियों और हिजबुल्ला तथा सहयोगी समूहों के अन्य अधिकारियों के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने (शेष पेज 9)

पूजा खेडकर अब आईएएस अफसर नहीं

●यूपीएससी ने चयन रद्द किया, भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने पर लगाई रोक

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को एक प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की 2022 सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें आयोग की किसी भी भविष्य की परीक्षा में बैठने से रोक दिया। अनुमति से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित होकर नियमों का उल्लंघन किया था। इसमें कहा गया है कि सीएसई-2022 (सिविल सेवा परीक्षा-2022) के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें भविष्य की सभी यूपीएससी परीक्षाओं या चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। यूपीएससी ने खेडकर को 18 जुलाई को अपनी पहचान फर्जी बनाकर परीक्षा नियमों में प्रदान की गई अनुमेय सीमा से परे प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई तक नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए 30 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे तक की अनुमति दी।

एक बयान के अनुसार, यूपीएससी ने कहा कि उसने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को धोखाधड़ी के लिए एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। उसने अपनी फर्जी पहचान दिखाकर परीक्षा नियमों में दी गई स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास किए।

इसमें कहा गया है कि 34 वर्षीया को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई तक का समय दिया और स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर था। और समय में कोई और विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर समय सीमा तक कोई जवाब नहीं मिला तो यूपीएससी कार्रवाई करेगी। पैनल ने बयान में कहा, उन्हें समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं। पैनल ने कहा, यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की (शेष पेज 9)

यूपीएससी की अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन

नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत में मनोज सोनी के यूपीएससी के शीर्ष पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र ने बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। सूदन, जो वर्तमान में यूपीएससी के सदस्य हैं। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, राष्ट्रपति ने... यूपीएससी के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए यूपीएससी की सदस्य प्रीति सूदन की नियुक्ति को 1 अगस्त, 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल, 2025 तक, जो भी पहले हो, मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी, सूदन ने जुलाई 2020 तक तीन साल तक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस हो: नितिन गडकरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वापस लेने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में गडकरी ने नागपुर डिवीजन जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया, जिसने उन्हें बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)की वापसी से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों 18 प्रतिशत जीएसटी दर के अधीन हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा, इसी तरह, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी व्यवसाय के इस खंड के विकास में बाधक साबित हो रहा है जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा, उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित सत्यापन के साथ नियमों के अनुसार बोझिल हो जाता है।

जाति मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमले के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर बुधवार को सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्षी सदस्यों के बीच जुबानी जंग हुई, जिसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को लोकसभा में भाजपा सांसद ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिसकी 'जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना की बात करते हैं।' कांग्रेस ने ठाकुर और प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया पर साझा करके 'संसदीय विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन' को बढ़ावा दिया, विपक्षी सांसदों ने ठाकुर के भाषण को दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान बताया।

संसद में विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने कहा कि गांधी परिवार की जाति शहादत है लेकिन बीजेपी-आरएसएस इसे कभी नहीं समझेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी बेंच के विरोध पर अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सांसदों को आश्वासन दिया कि टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा। भाजपा ने जाति विवाद को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पूछने में क्या गलत है जब वह सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और यहां तक कि पत्रकारों सहित अन्य लोगों की जाति के बारे में पूछ सकते हैं।

हालांकि, उसी क्रम में, सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोलते समय गांधी की जाति के बारे में नहीं पूछा और आश्चर्य जताया कि विपक्ष के नेता ने इस पर आपत्ति क्यों जताई और इसे उनका अपमान बताया जबकि उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें कथित तौर पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणियों के अंश थे, जिन्हें सभापति ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। लोकसभा में कांग्रेस के दलित सांसद चन्नी ने स्पीकर ओम बिरला को एक नोटिस सौंपकर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रक्रिया के नियमों के नियम 222 के तहत विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी कहती रही है कि बीजेपी के लोगों के दिल में एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। राजद के मनोज झा ने कहा कि ठाकुर ने अपनी सामंती (शेष पेज 9)

नई दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में भाग लेने पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।

एससीआर व नजूल संपति विधेयक विधानसभा में पारित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के साथ ही उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति, 2024 विधेयक भी पारित हो गया। इन दोनों विधेयकों को योगी सरकार ने अध्यादेश लाने के बाद निर्धारित समयसीमा के अंदर विधानसभा में प्रस्तुत किया और इस पर सदन की मुहर लगवा दी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। (विस्तृत पेज 2)

प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में 15 की मौत

भाषा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं समेत विभिन्न आपदाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राहत आयुक्त ने बुधवार को यहां बताया कि मंगलवार शाम छह बजे से बुधवार को इसी अवधि तक 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें चंदौली में चार, बांदा और गौतमबुद्ध नगर में तीन-तीन, प्रयागराज में दो, प्रतापगढ़, गोंडा और इटावा में एक-एक व्यक्ति हुई। राहत आयुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक, बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे बिजली गिरने, डूबने और सांप काटने की वजह से यह मौतें हुईं। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बदायूं के कछला पुल पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

रिपोर्ट में बताया गया कि फिलहाल राज्य में केवल सात जिले (कुल 75 में से) अयोध्या, बलिया, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच और हरदोई बाढ़ प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है।

वहीं वाराणसी में हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार प्रभावित हुआ है। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से घाटों का सम्पर्क टूट गया है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर पानी भर जाने के कारण आरती स्थल में भी बदलाव किया गया है।मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर पानी बढ़ने से शव दाह के स्थान में भी परिवर्तन किया गया है।

लखनऊ में हुई तेज बरसात के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया समाचार पेज 3

भोले के भक्त

नई दिल्ली में बुधवार को सावन के महीने में शिवभक्त कांवड़िये पवित्र गंगाजल लेकर जाते हुए।

हमारी सरकार ने खोले आठ लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते: योगी

न्यू पेंशन स्कीम पर सीएम योगी ने विधानपरिषद में सपा-बसपा को लताड़ा, कहा, 2005 से 2017 तक नहीं खोले गए पेंशन खाते

● वर्तमान सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्यांश को बढ़ाकर किया 14 प्रतिशत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधान परिषद् में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर वक्तव्य दिया। एनपीएस पर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाता खोलने का कार्य किया गया।

उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी कर्मचारी के पेंशन खाते नहीं खोले गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 में जब ये बात हमारे सज्ञान में आई, तब हमने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें संबंधित विशेषज्ञों को भी रखा गया। कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा की गई। ये लगभग आठ लाख कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा था। तब ये बात सामने आई थी कि कर्मचारी की लास्ट पेमेंट जो ड्रॉ होगी उसका 50 प्रतिशत देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ाए। आंकलन में पता लगा कि अगर सरकार अैर कर्मचारी समय से पैसा जमा करें और कर्मचारी किसी स्कीम से अपना पैसा जोड़ता है तो रिटायरमेंट के बाद करीब 60 प्रतिशत तक पैसा पेंशन के रूप में उसे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया है। हमने सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले, 2005 से 2017 तक का पैसा जो कर्मचारियों के खाते में नहीं गया था, क्योंकि खाता ही नहीं था, उस पैसे को भी डालने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के वक्त जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा, इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। सीएम योगी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को प्राइवेट बैंकों में जमा करने की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और इसमें कार्रवाई भी की गई है, साथ ही धनराशि को वापस लाने का कार्य किया गया है। सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े।

लाल बिहारी यादव को उच्च सदन में नेता विरोधी दल बनने पर दी बधाई

इससे पहले मुख्यमंत्री ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनने पर बधाई दी और चुटकी लेते हुए कहा कि आशा करता हूं कि आप हमेशा नेता विरोधी दल बने रहें। उन्होंने कहा कि ये उच्च सदन है, यहां आने वाले माननीय सदस्यगण सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ स्थानीय निकाय, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कुछ स्नातक मतदाताओं व माननीय राज्यपाल जी के मनोनयन से यहां आते हैं। सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीठ से जो भी आवश्यक दिशा-निर्देश मिलते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है।

नेता सदन ने दी है सुरक्षा की गारंटी: सुरेश खन्ना

● परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर सपा सदस्य आए वेल में

● नजूल सम्पत्ति विधेयक-2024 प्रस्तुत होने पर विपक्ष बिफरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा

मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सदस्य विजमा यादव अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर वेल में पहुंच गयी। उनके बाद समाजवादी पार्टी के बाकी सदस्य भी वेल में पहुंच गए। सपा सदस्य विजमा यादव का कहना था कि उनके पति जवाहर यादव पंडित के हत्यारोपी उदयभान करवरिया की सजा माफ कर उसे रिहा किए जाने से उनकी और परिवार की सुरक्षा का खतरा बढ गया है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना था कि इस बावत कल ही सदन में नेता सदन और मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार सदस्य विजमा यादव और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेती है। उनकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर जो भी आवश्यक होगा किया जायेगा। सपा सदस्य का कहना था कि उनके पति के हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने के साथ ही उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गयी है जिससे उन्हे और परिवार को जान का खतरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हत्यारोपी की सजा माफ किए जाने पर सवाल उठाया। इस पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सजा माफ किये जाने का निर्णय राज्यपाल का है उस पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। संसदीय कार्यमंत्री के आश्वासन के बाद सपा के सदस्य वेल से अपने आसन पर वापस गए। आज ही विधानसभा में दूसरी शोरशराबे और हंगामें की स्थिति तब पैदा हुई जब उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति विधेयक-2024 प्रस्तुत किया गया। सपा के सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर सपा सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। शोरशराबे और हंगामें के बीच ही नजूल सम्पत्ति विधयेक ध्वतिमत से पारित हो गया। शोरशराबे के बीच ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 सहित कई विधयेकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

शिवपाल ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के मध्य बैठक कराने का उठाया मुद्दा

सपा के वरिष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सिंह ने जिलो में सलाहकार समितियों के गठन न होने और उनकी बैठके न होने का मामला उठाया। सपा के शिवपाल यादव ने भी जिलों में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक न बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए। जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिलें में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराए जाने के आज ही निर्देश निर्गत करायेंगे।

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जिला सलाहकार समितियों का गठन सुनिश्चित कराने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि जिलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जनप्रतिनिधियो के साथ बैठकें करें और उनके फोन भी रिसीव करें। पूर्व में भी मुख्य सचिव की ओर से इस आशय के निर्देश जारी किये जा चुके है। नियम 301 के तहत कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने सदन के सदस्यों का वार्षिक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का मामला उठाया। इस पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस बारे में वे उपमुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करायेंगे। इससे पूर्व प्रश्न प्रहर सपा के सदस्य डा संग्राम यादव ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए कहा कि सरकार बिजली विभाग के निजीकरण की तैयारी कर रही है। स्वयं ऊर्जा के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की बुरी स्थिति है। दस से पन्द्रह दिन लग जाते हैं फुंके हुए टांसफार्मर भी नहीं बदले जा रहे हैं। किसानों को चार घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रश्नकाल का समय समाप्त होने के कारण ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के लिखित जवाब पर सपा सदस्य पर कोई अनुपूरक नहीं किया। प्रश्न प्रहर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सपा के कई सदस्यों ने सवाल किए जिस पर गन्ना विकास मंत्री चैधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सत्तारूढ होने के बाद गन्ना किसानों का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सपा के सदस्य समरपाल सिंह का आरोप था कि सरकार गन्ना किसानों को तीन का भुगतान नहीं किया गया है। एक अनुपूरक के जवाब में कहा कि केन्द्र के शुगर एक्ट मे ंपरिवर्तन करने का राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है। आज ही सदन में दिवंगत पूर्व लोकसभाध्यक्ष मनोहर जोशी तथा प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डा अजीज कुरैशी सहित पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, डा अच्युतानंद तिवारी, शफीकुर्र रहमान वर्क, राम छबीला, मुख्तार अंसारी, छोटे लाल यादव, विनय शाक्य, बाबूलाल कुशवाहा सहित अन्य सदस्यों के निधन पर शोक जताया गया।

भाजपा नेताओं को राहुल गांधी से आजादी की लड़ाई का हिसाब पूछना चाहिए: अजय राय

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी से आजादी की लड़ाई का हिसाब पूछना चाहिए। 1947 तक जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी वह चांद पर कैसे पहुंच गया और मंगल पर जा रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया 5 सैन्य ताकतों में से एक बन गया इन सब का हिसाब पूछना चाहिए। साथ ही साथ खुद भी बताना चाहिए की आजादी की लड़ाई में आरएसएस और भाजपा के आकाओं ने देश के साथ गद्दारी क्यों की और पिछले 10 साल से देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने आजादी के लिए सिर्फ जेल नहीं काटी बल्कि देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान निछावर कर दी और शहीद हो गए। संघ और भाजपा के लोगों को राहुल गांधी के परिवार के बहते हुए रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब भी मांगना चाहिए और खून की जाति भी पूछनी चाहिए। राय ने कहा कि ऐसा लगता है आरएसएस और भाजपा में घटिया से घटिया बोलने तथा कीचड़ में नहाने की होड़ लगी है, यह शर्मनाक है। देश और प्रदेश की सत्ता में बैठे भाजपा के लोग अपनी मर्यादा खो रहे हैं जो देश की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।

यूपी में अपराधियों को पुलिस का तनिक भय नहीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाख दावे करें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है परन्तु हकीकत में तो यही लगता है कि अपराधियों को पुलिस का तनिक भी भय नहीं रह गया है। रोज ही दबंगों द्वारा भूमि पर कब्जे, अपहरण, लूट और महिला अपराध के मामलें सुर्खियां बटोरते हैं। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है जब स्वयं सत्ता से जुड़े लोग ही संरक्षण का लाभ उठाकर मनमानी करने पर उतारू हो रहे हैं।

अखिलेश जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव में हौसला बुलंद बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तीन महीने पहले उसके पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजधानी लखनऊ में दोस्तों ने अपने दोस्त की निर्ममता से हत्या कर दी। बाराबंकी में सिगरेट के विवाद में भाईयों ने लाइनमैन को मार डाला। हरदोई में घर में घुसकर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अखिलेश ने कहा कि लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज में खेत से घर आ रही युवती से रेप का प्रयास किया गया। उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। हरदोई के सांडी क्षेत्र में गोबर डालने घर से निकली किशोरी की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारो ने उसकी आंख भी फोड़ दी। लखनऊ में घर में काम करवाने के बहाने से बुलाकर 12 साल की बालिका से दुष्कर्म किया गया। कारखाने में महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। अखिलेश ने कहा ि कबरेली के नवाबगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया गया। बाद में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यों तो छिनौती और लूट की घटनाएं तो आए दिन की बातें हैं। व्यापारियों के साथ लूट की तमाम घटनाएं हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राजधानी में ही किसी न किसी महिला की चेन या पर्स नहीं लूटा जाता हो। आज कल तो साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। ठगी की घटनाएं कम नहीं हो रही है।

अखिलेश ने कहा कि स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जो यह कहते थे कि उनकी सरकार में अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, 24 कैरेट असत्य निकला। अपराधी पूरी तरह राज्य में निर्भीक होकर सक्रिय हैं। उन्हें किसी का डर नहीं रह गया है। वैसे जबसे भाजपा की सरकार आई है उसका प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भाजपा सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अब बहुत ही जल्द भाजपा का सत्ता से बाहर हो जाना तय है।

फतेहपुर व कुशीनगर के एसपी सहित 8 आईपीएस व 13 पीपीएस अफसरों के तबादले

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्य सरकार ने फतेहपुर और कुशीनगर के एसपी सहित आठ आईपीएस व 13 पीपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। पीपीएस अफसरों में 11 अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और दो डिप्टीएसपी स्तर के हैं। इस फेरबदल में अजय कुमार सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ का सेनानायक, एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा संतोष कुमार मिश्रा को एसपी कुशीनगर, एसपी अभिसूचना मुख्यालय अभिषेक यादव को एसपी रेलवे प्रयागराज, एसपी फतेहपुर उदय शंकर सिंह को एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, एसपी कुशीनगर धवल जायसवाल को एसपी फतेहपुर, शुभम पटेल पुलिस उपायुक्त, गायिजाबाद कमिश्नरेट को एसपी अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ, श्रद्धा नरेंद्र पांडेय पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़ और अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विवेक चंद्र यादव को अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट के पद पर नई तैनाती प्रदान की गई है। इसके अलावा जिन अपर पुलिस अधीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया गया है उनमें कुमार रणविजय सिंह को फिरोजाबाद से नगर, मुरादाबाद, अखिलेश भदौरिया को नगर मुरादाबाद से ग्रामीण फिरोजाबाद, शिवराम यादव को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट से पीटीएस मेरठ, श्रीपाल यादव को पीटीएस मेरठ से अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ, शशि शेखर सिंह को संतकबीर नगर से एटीएस, लखनऊ और सुशील कुमार सिंह प्रथम को बंदायू से संतकबीर नगर का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अजय कुमार तृतीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से कन्नौज, अशोक कुमार द्वितीय को अयोध्या से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, बलरामचारी दुबे को पीएसी सीतापुर से सुरक्षा, अयोध्या, अलका धर्मराज को पीएसी गाजियाबाद से क्षेत्रीय अभिसूचना मेरठ और दिनेश यादव को एटीएसी सीतापुर से उपसेनानायक 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के पद पर भेजा गया है।

अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस अफसरों को डीजीपी ने दी विदाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस अफसरों को डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस मुख्यालय में समारोह आयोजित कर विदाई दी। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, रूचिता चौधरी पुलिस अधीक्षक महिला एवं सुरक्षा संगठन व अष्टभुजा प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को डीजीपी ने मोमेन्टो भेंट किया। सेवाकाल के दौरान किए गए कार्यो की सराहना करते हुए उन्होंने उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

सुनील कुमार गुप्ता वर्ष 1993 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। वर्ष 2009 में पुलिस उपमहानिरीक्षक और 2013 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष वर्ष 2018 में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद, पुलिस महानिदेशक उप्र के जनरल स्टाफ आफिसर एवं अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार के पदों पर नियुक्त रहे। वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय के पद पर नियुक्त थे।

रूचिता चौधरी वर्ष 1994 में प्रान्तीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं। वर्ष 2006 में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुईं। वर्ष 2021 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का कैडर हासिल हुआ। वर्तमान में वह पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090), लखनऊ के पद पर नियुक्त थीं। अष्टभुजा प्रसाद सिंह वर्ष 1999 में प्रान्तीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। वर्ष 2013 में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष 2019 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का कैडर हासिल हुआ। वर्तमान में वह पुलिस अधीक्षक, रेलवे प्रयागराज के पद पर नुयिक्त थे।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नजूल संपत्ति विधेयक जनविरोधी: आराधना मिश्रा

● कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने कहा, इस कानून के बहाने भाजपा सरकार कर रही गरीबों का आशियाना छीनने की साजिश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता में आराधना मिश्रा 'मोना' ने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए। जिसमें प्रमुख रूप से नजूल संपत्ति प्रबंधन विधेयक 2024 में जनहित में संशोधन करने और घरेलू कूड़ा निस्तारण में सुधार का मुद्दा उठाया और इसे धरातल पर लागू करने की बात कही।

मोना ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में लाए गए नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को जनविरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता के दिए जनादेश की संख्या का तानाशाही दुरुपयोग बताया है। मोना ने कहा की सरकार इस कानून में संशोधन करें यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने का कानून है, और जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बनाये आशियाने को उजाड़ने वाला है, प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है, इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होगा। मोना ने कहा कि सरकार ने कानून में यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि नजूल की भूमि पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल बनें हैं तो उसके लिए इस कानून से छूट दी जायेगी और गरीब आदमी के घर को इस कानून से उजाड़ दिया जायेगा यह भेदभाव कैसे, संविधान समान अधिकार कानून के समान रूप से लागू करने की बात करता है, जिन लोगों ने अपने नजूल जमीन को फ्री होल्ड करा लिया है, या जो लोग पैसा जमा कर चुके और अभी फ्री होल्ड नहीं हो पाया उनके लिए विधेयक में सरकार ने स्पष्ट नहीं किया, इस कानून को संशोधन लाने और प्रदेश के करोड़ों लोगों के हित में परिवर्तन कर सुधार करने की जरूरत है, भाजपा सरकार विधानसभा के अंदर अपनी संख्या के बल पर इस तानाशाही विधेयक को लाकर जनता के जनादेश का दुरुपयोग कर रही है।

मोना ने जनहित से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे घरेलू कूड़ा निस्तारण में अव्यवस्था और भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही लापरवाही के मुद्दे को उठाया और भाजपा सरकार की नाकामी से पर्यावरण के नुकसान की बात कही। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण आज के समय का बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, सरकार द्वारा निस्तारण संबंधी संयंत्र की बातें हवा हवाई हैं, आज कूड़ा निस्तारण के में लापरवाही से प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से कूड़ा निस्तारण में बातें तो हो रही है, कूड़ा संयंत्रों की संख्या गिनाई जा रही लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम पदार्थ हैं जिनके रिसाइकल में लापरवाही हो रही है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा की प्रदेश की सरकार की लापरवाही से सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, सरकार इस पर सिर्फ बातें न करे इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

एससीआर व नजूल संपति विधेयक विधानसभा में पारित

● नजूल संपति विधेयक के तहत नजूल भूमि को संरक्षित कर इसका सार्वजनिक उपयोग करेगी सरकार

लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, और बाराबंकी के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के साथ ही उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति, 2024 विधेयक भी पारित हो गया। इन दोनों विधेयकों को योगी सरकार ने अध्यादेश लाने के बाद निर्धारित समयसीमा के अंदर विधानसभा में प्रस्तुत किया और इस पर सदन की मुहर लगवा दी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। विधेयक के पारित होने के बाद लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, और बाराबंकी को मिलकर एससीआर का गठन किया जाएगा, जिससे इन जिलों का उचित, व्यवस्थित और त्वरित विकास हो सकेगा। वहीं नजूल संपति विधेयक 2024 के तहत सरकार ने नजूल भूमि को संरक्षित करते हुए इन भूमियों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में घोषित करने के बजाय इसका उपयोग केवल सार्वजनिक उपयोगिता के लिए किए जाने का निश्चय किया है। दोनों ही विधेयकों को विधानसभा में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन विधेयक-2024 के माध्यम से राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके गठन के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्यय भार प्रस्तावित नहीं है। इसके तहत सभी 6 जिलों के 27 हजार 860 वर्ग मीटर एरिया को समेटकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इससे इन सभी जिलों में तेज विकास किया जा सकेगा और यहां रहने वाले लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की सकेंगी। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं, जनसुविधाओं का समूचे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास होगा। योजना गत क्षेत्रीय विकास से आवासन, अवसंरचना, यातायात, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी। वहीं, उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति विधेयक, 2024 के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में प्रतिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन, निरस्त हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है, तो ऐसे जमा किए जाने की तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) की ब्याज दर पर कैलकुलेट करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, के पट्टों को सरकार या तो ऐसी शर्तों पर जैसा सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है जारी रख सकती है या ऐसे पट्टों का निर्धारण कर सकती है।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

सूच्य हो कि मैंने अपने बेटे सोनू पुत्र शत्रोहन लाल को उसका चाल-चलन ठीक न होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।अब से उसके किसी भी कृत्य व लेन-देन से मेरा व मेरे परिवार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा। अर्मिता देवी पत्नी शत्रोहन लाल निवासी-ग्राम-बरोसा,थाना-हरगांव, जिला-सीतापुर

सूचना

सूचना-यूनिट नं. 3571-OLY-M/B1-0603, 3571-OLY-M/B1-0703, 3571-OLY-M/B2-0304 व 3571-OLY-M/B2-0204 जो योजना 3571 ओलम्पस लेक व्यू अपार्टमेंट, लखनऊ के लिए अंसल प्रापर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा जारी किए गए थे, हमारे कार्यालय 113/58-ए, स्वरुप नगर, कानपुर-208002 से खो गए है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इन प्रपत्रों का प्रयोग असंवैधानिक होगा। कमल किशोर पाण्डे, 7/45, कृष्णानगर, जी.टी. रोड, कानपुर-07

सूचना

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल आदित्य बिरला हाऊसिंग फाइनेंस लि० अपने एक ग्राहक मेसर्स स्पाइस फैक्टरी 2.0 को ऋण सुविधा प्रदान करना चाहता है जिसमें एक दोमंजिला भवन संख्या 595/KN-1302, मूखंड संख्या 2 व 3 के अवशेष भाग क्षेत्रफल 2710 वर्गफुट, जो खसरा संख्या 1302 का अंश है, स्थित औरंगाबाद खालसा, वार्ड राजा बिजली पासी, लखनऊ की स्वामिनी श्रीमती जायिति सिन्हा द्वारा प्रतिभूति के रूप में बंधक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त श्रीमती जायिति सिन्हा ने मूल रूप से मूखंड संख्या 2 व 3 कुल क्षेत्रफल 6440 वर्गफुट को श्री शफ्फुद्दीन खान से एक विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2008 क्रम संख्या 9489 के माध्यम से खरीदा था जिस मूल विक्रय पत्र के अंतिम दो पृष्ठ अभिकथित रूप से कहीं खो गये हैं। श्रीमती जायिति सिन्हा द्वारा मूखंडों के कुल क्षेत्रफल में से 1203 वर्गफुट भाग श्री शिव कुमार भदौरिया को विक्रय पत्र दिनांकित 25.10.2011 क्रम संख्या 15553, 1120 वर्गफुट आग श्री अनुराग प्रजापति को विक्रय पत्र दिनांकित 15.02.2013 क्रम संख्या 2670 व 1200 वर्गफुट भाग श्री मोहम्मद अली को विक्रय पत्र दिनांकित 24.03.2013 क्रम संख्या 6904 के माध्यम से पूर्व में विक्रय कर दिया है तथा अब वे अवशेष क्षेत्रफल 2710 वर्गफुट मय भवन की स्वामिनी हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को इस प्रस्तावित ऋण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपने पक्ष में विधिक साक्ष्य के साथ मुझसे 7 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। उक्त अवधि में कोई विधिक व पोषणीय आपत्ति न प्राप्त होने पर मेरे उपरोक्त मुवक्किल द्वारा उक्त ऋण प्रदान कर उक्त संपति को बंधक किया जायेगा तथा उक्त संपत्ति पर मेरे मुवक्किल का प्रथम प्रभार होगा। **तरूण प्रकाश श्रीवास्तव, एडवोकेट,** रूम नं0 110-111, सिटी होटल, बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ-226001, मो0- 9335914262

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
मण्डलीय कार्यालय लखनऊः न्यू बिल्डिंग, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोनः 0522-2286272, 2287283, फैक्सः 0522-2288033, ई-मेलः zolucknow@indianbank.co.in

मांग सूचना
सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस

जबकि, **इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्न ऋणियों को मांग सूचना भेजी गई थी। चूंकि डाक द्वारा भेजी गये उक्त नोटिस को प्राप्तकर्ता के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। अतः इस प्रकाशन के माध्यम से ऋणियों को नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर दर्शायी गयी राशि का भुगतान करने की मांग की जाती है अन्यथा सरफेसी एक्ट की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 व 9 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत बैंक चल/अचल सम्पत्ति का कब्जा लेकर बिक

आफत बनकर गिरी बारिश

विधानसभा में घुसा पानी, नगर निगम हुआ जलमग्न

● विधानसभा के ग्राउण्ड फ्लोर व बेसमेंट में पानी भरने से दूसरे गेट से निकले मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जलभराव में गाड़ी फंसने पर निजामाबाद आजमगढ़ से सपा विधायक आलम बदी को स्कूटर से घर जाना पड़ा

लखनऊ में बुधवार को बारिश आफत बन कर गिरी। जिसके चलते लोगों का जन-जीवन प्रभावित हुआ। विधानसभा के ग्राउण्ड फ्लोर व बेसमेंट में पानी भरने से चल रहे विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुरक्षाकर्मियों ने दूसरे गेट से बाहर निकाला। वहीं जलभराव के चलते निजामाबाद-आजमगढ़ सीट से विधायक आलमबदी को स्कूटर से लौटना पड़ा। बारिश के कहर बन कर गिरने की वजह से जहां दोपहर को हजरतगंज चौराहा पूरी तरह से जलमग्न रहा। नगर निगम की छत के लीक होने से कार्यालय में भी पानी तैरता हुआ दिखाई दिया। स्थिति यह रही कि राजधानी के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी के घुसने के साथ ही सड़कें घंसी नजर आई।

लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। वहीं लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की गई थी। बारिश का कहर इतना था कि लखनऊ में विधानसभा में जलभराव देखने को मिला। विधानसभा से बारिश के पानी को निकालने के लिए लोग बाल्टी का प्रयोग करते नजर आये। पूरा विधानसभा जलभराव से जलमग्न हो गया। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में पूरे कमरों में पानी भर गया। कई सामान भी बारिश के पानी में भीग गए। बारिश के पानी से यहां काम करने वाले कर्मचारी भी काफी परेशान दिखाई दिए। वहां मौजूद कर्मचारियों से जब पूछा गया कि आपने कभी ऐसा मंजर देखा है तो उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जब विधानसभा में पानी भरा तब सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। गेट नंबर 7 के सामने पानी भरा होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेट नंबर एक की तरफ से बाहर निकले। इसके अलावा जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा है, उसके मुख्यालय की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई है। वहीं कार्यालय में भी पानी तैरता नजर आया। लखनऊ के दारुलशफा में भी पानी भर गया है। यहां विधायकों को निवास आवंटित किए जाते हैं। यहां भी घुटने तक पानी भरा नजर आया। यहां विधायक अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठकर आवास पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश ने हजरतगंज चौराहे को तालाब बना डाला। यहां कई फीट पानी भरने से वाहनों का जाम लग गया। बारिश के कारण नगर निगम के लाख दावे खोखले साबित हो गए। निगम की लापरवाही की वजह से शहर के लोग परेशानियों में घिर गए। सीवर की सफाई न होने से जलनिकासी न हो पाई। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी बारिश के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। कुछ ऐसा ही नजारा हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन की जर्जर बिल्डिंग में देखने को मिला। बारिश का पानी यहां भी घुस गया।

कई इलाकों में पानी भरा: बुधवार दोपहर तेज बारिश ने शहरवासियों का जीना मुहाल कर दिया। कमोवेश स्थिति यह रही कि राजधानी के सभी इलाके पानी में सराबोर नजर आये। पार्क रोड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पूरा इलाका पानी से लबालब भरा रहा। इंदिरानगर, अलीगंज, महानगर, गोमतीनगर, ऐशबाग, चारबाग, अमीनाबाद, लालकुआं, आलमबाग जैसे इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया। जिसके चलते आम जनमानस का जनजीवन प्रभावित रहा।

डीसीपी ट्रैफिक ने संभाली व्यवस्था

बारिश के चलते हजरतगंज में सड़कों पर पानी लगने की वजह से लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज ने पानी में भींगते हुए ट्रैफिक संभाला।

सर्वोदयनगर के पास घंसी सड़क: सर्वोदय नगर के पा तेज बारिश के चलते सड़क धंस गयी। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके पीछे बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया है। कुछ दिनों पूर्व ही वहां पर बिजली विभाग की तरफ से अंडरग्राउण्ड केबिल डाली गयी थी। इस बीच तेज बारिश के चलते वहां पर खड्डु बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुँचे पीडब्ल्यूडी के एई बीके पाण्डेय, सुनील कुमार और सुपरवाइजर रामफल ने मौके पर पहुँच कर सड़क ठीक कराने का काम शुरू कराया। हालांकि विभाग की तरफ से बिजली विभाग को नोटिस जारी करने की बात कही गयी है।

शिवपाल ने ली चुटकी

बारिश के बाद यूपी विधानसभा में पानी भरने पर शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। सपा नेता ने लिखा- बजट की सबसे अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश विधानसभा को है, एक मूसलाधार बारिश में यह हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे है।

स्टार्ट अप की दुनिया बहुत अच्छी: राज्यपाल

● राज्यपाल ने राजभवन में इनोवेशन हब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्टार्ट अप प्रदर्शनी का किया अवलोकन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को राजभवन में इन्नोवेशन हब डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्टार्ट अप प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उनके प्रस्तुतीकरण को देखा। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन के गांधी सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के युवा इन्नोवेटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप की दुनिया बहुत अच्छी है। इसका उद्देश्य समाज की समस्याओं को जानना, तकनीक के माध्यम से उसका उचित समाधान प्रस्तुत करना, स्वच्छता तथा आय सृजन आदि है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास बुद्धि और कौशल है जिसे सही दिशा में लगाया गया है। शक्ति, बुद्धि और कौशल से आगे बढ़ते रहिए। इस क्रम में राज्यपाल ने नए स्टार्ट अप हेतु कई सुझाव भी दिए। उन्होंने गंदे पानी को शुद्ध करने, नाई की दुकान में इकट्ठा होने वाले बाल की उपयोगिता आदि के संदर्भ में नए स्टार्टअप बनाए जाने के सुझाव दिए।

राज्यपाल ने कहा कि स्टार्ट अप के माध्यम से अनुपयोगी चीजों को उपयोगी बनाये, इसके लिए राजभवन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होने कहा कि स्टार्ट अप को बढ़ावा दिए जाने हेतु सरकार की संचालित योजनाओं का भी लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप समाजोपयोगी, प्रदूषण रहित, आय सृजक आदि उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाएं स्टार्ट अप के प्रोडक्ट को खरीद कर उसे प्रमोट करें । इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने कहा कि स्टार्ट अप की वजह से आगे आने वाले वर्षों में देश विकसित हो सकेगा। राजभवन में स्टार्ट अप प्रदर्शनी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, तथा ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई। इन प्रमुख स्टार्ट अप में स्कूल विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक और ड्रोन का प्रशिक्षण हेतु फ्यूचर गुरुकुल एजुकेटेड प्राइवेट लिमिटेड, सोलर स्मार्ट बिन, महिला सुरक्षा के लिए पिंक शक्ति एप, हस्त निर्मित उत्पादों हेतु हस्तकला प्रमाणिक, विद्यार्थियों के डिजिटल हेल्थ कार्ड हेतु स्टुफिट का स्कूल ऐप प्रोग्राम, आत्मनिर्भर आधुनिक गौशाला, बिजेंद्र गोशाला, स्कूल कंपनी, बैंक के यूनिफॉर्म हेतु टेक्स 3 डी इन्नोवेशन, अनुपयोगी पानी से बिजली तैयार करने हेतु स्टार्ट अप, रेंजर इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, खामोश जुबान की नई आवाज हेतु साइनिफाई, महिला सुरक्षा हेतु शक्ति एप, फ्रेटबॉक्स, अल्युमिनियम आयन बैटरी हेतु आर्यो ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, सोलर पैनल, हीटर आदि के इस्तेमाल से हंस तारा ईंट, वसुंधरा बायो फाइबर्स तथा कचरा एकत्रीकरण हेतु कचरा सेठ आदि स्टार्टअप का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सात महीने में 146 दिन वकील हड़ताल पर

● हाईकोर्ट ने लॉयर्स एसोसिएशन से मांगा जवाब

विधि संवाददाता। लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि हरदोई के सवायजपुर तहसील की लॉयर्स एसोसिएशन लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित कर रही है। इस वर्ष इस तहसील में अब तक 146 दिन न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। जस्टिस संगीता चंद्रा एवम जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए सम्बंधित एसडीएम, सवायजपुर हरदोई से जवाब मांगा है। साथ ही द ग्रेट लॉयर्स एसोसिएशन, हरदोई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। पीठ ने उक्त लॉयर्स एसोसिएशन से भी जवाबी हलफ़नामा तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

कोई कार्यवाही नहीं होने व जानमाल की धमकी देने से विक्षिप्त दुराचार की पीड़िता द्वारा तेजाब पीकर आत्महत्या करने के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी प्रदीप कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया है। एडीजे रोहित सिंह ने इसे सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। सरकारी वकील केके सिंह के मुताबिक 23 अक्तूबर 2019 को इस मामले की रिपोर्ट मृतका की मां ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। पीड़िता ने डरकर अपना मकान भी बदल लिया था। लेकिन वहां भी उसे जानमाल की धमकी दी जाती थी।

दहेज हत्या में आरोपी पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

विधि संवाददाता। लखनऊ

दहेज हत्या के एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी पति बब्लू को सत्र अदालत ने सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे नरेंद्र कुमार, तृतीय ने इस पर 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक एक मार्च 2011 को लक्ष्मी की शादी बब्लू से हुई थी। शादी में साढ़े तीन लाख खर्च हुए थे। बावजूद इसके ससुराल वाले और दहेज के लिए लक्ष्मी को प्रताड़ित करते थे। वो अपाचे मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपए की मांग करते थे। दो जुलाई 2014 को राजकुमार को मालूम हुआ कि उनकी बेटी लक्ष्मी की मौत हो गई है। उसके ससुराल वाले उसे अपने मूल निवास कमलापुर, जनपद सीतापुर ले गए हैं। राजकुमार उसी रात कमलापुर पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि पति व ससुराल वालों ने बिना किसी को बताए उनकी बेटी का चुपचाप दाह संस्कार कर दिया है। ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। तीन जुलाई को राजकुमार ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ लखनऊ के चौक थाने में तहरीर दी। लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। 25 अगस्त 2014 को इस मामले की एफआईआर अदालत के आदेश से दर्ज हुई। अदालत ने यह आदेश राजकुमार की अर्जी पर दिया था। विचारण के पश्चात अदालत ने अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

लुटेरे को सात वर्ष की सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

लूट के दौरान घायल करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त दिलदार उर्फ दिलावर को सत्र अदालत ने सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे सोमप्रभा मिश्रा ने इस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

15 जनवरी 2011 को इस वारदात की रिपोर्ट मो. इरफान आलम ने थाना तालकटोरा में दर्ज कराई थी। सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी के मुताबिक रात 10 बजे इरफान कलेक्शन का 53 हजार रुपए लेकर निशातगंज से अपने घर राजाजीपुरम जा रहा था। उसने जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, तो अभियुक्त ने आवाज लगाई। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। अभियुक्त ने पास आकर रिवाल्वर निकाल लिया और कहा कि जितने पैसे लाए हो, मुझे दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा। इरफान ने मना किया तो मारपीट करने लगा और पैसे निकाल लिए। इस पर इरफान ने शोर मचाया। पास ही पार्क में बैठा उसका भाई आसिफ और अन्य लोग दौड़कर आए तो अभियुक्त ने इरफान पर फायर कर दिया और भागने लगा। इरफान इस हमले में बाल बाल बच गया। फिर लोगों ने दौड़ाकर अभियुक्त को पकड़ लिया और उसे थाने ले गए।

ताज होटल पुल के नीचे जलभराव में हुड़दंग के आरोप में दो धरे

लखनऊ। बारिश के चलते ताज होटल के समीप पुल के नीचे से लेकर सिरोज कैफे तक हुड़दंगियों का सड़क पर कब्जा रहा। आते-जाते वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही दो पहिया वाहन चालकों से बदतमीजी करने के आरोप में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गये युवकों के नाम क्रमश: पवन यादव व सुनील कुमार है। जबकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है।

सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक के आवास व होटल पर विजिलेंस का छापा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की जांच कर रहे सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने बुधवार को सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ के प्रधान प्रबंधक (वित्त एवं शुगर सेल) दिनेश चन्द्र गुप्ता के गोमती नगर स्थित आवास और उनके होटल पर छापेमारी की। इस दौरान टीम को निवेश संबंधी कागजात, ज्वैलरी और करोड़ों रुपए मूल्य के दो फार्म हाउस और खेती योग्य भूमि के कागजात मिले हैं। उल्लेखनीय है कि शासन के आदेश पर विजिलेंस ने गत 25 जुलाई को अधिष्ठान के लखनऊ सेक्टर थाने में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिनेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान न्यायालय से आरोपी के आवास, प्रतिष्ठान (होटल) एवं बैंक लॉकर पर सर्च की कार्रवाई के लिए वारंट हासिल किया। सर्च वारंट के आधार पर बुधवार को विजिलेंस ने आरोपी दिनेश चंद्र गुप्ता के गोमती नगर में विजयंत खंड स्थित आवास, गोमती नगर में विभव खंड स्थित एक मकान में संचालित होटल तथा बैंक लॉकर की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन कर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार उनके आवास से म्युचुअल फंड, शेयर, एलआईसी, किसान विकास पत्र, एनएससी, एफडी व बैंक बैलेंस में लगभग 73 लाख रुपये निवेश से संबंधित कागजात प्राप्त हुए। आवास से तलाशी के दौरान मिली ज्वैलरी का वैल्यूअर से मूल्यांकन कराने पर इसकी कीमत लगभग 10 लाख पाई गई। इसी तरह घर के साजो-सामान की कीमत लगभग 20 लाख मूल्यांकित की गई।

प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट के होंगे यूजी व पीजी, पांचवे सेमेस्टर में मुख्य विषय का चुनाव कर सकेंगे छात्र

● रिसर्चर इन रेजिडेंस, प्रोफेसर आफ प्रेक्टिस जैसे कई मुद्दों को मिली हरी झंडी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा। जबकि पांचवे सेमेस्टर में छात्र अपने मुख्य विषय का चुनाव कर सकेंगे। बुधवार को विवि में सम्पन्न हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इसे अनुमोदन दे दिया गया। विवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यूजी के सिलेबस में संसोधन किया गया। इसमें मुख्य विषय में वैकल्पिक पेपर्स/ विकल्प/ इंटर्नशिप/ टर्म पेपर/ माइनर प्रोजेक्ट/ डिसर्टेशन सहित राष्ट्र गौरव को अनिवार्य कर दिया गया। वहीं एक व दो वर्ष का परास्नातक कोर्स के आर्डिनेंस पर मुहर लगी। छात्रों को यूजी के सेमेस्टर 3, 5, और 7 और पीजी के सेमेस्टर 3 में प्रवेश की अनुमति दी गयी। बैठक में कॉलेज से कॉलेज या कॉलेज से विश्वविद्यालय परिसर में स्थानांतरण की अनुमति दी गयी। नैक ए डबल+ और ऊपर के ग्रेड वाले उच्च शिक्षण संस्थान से विश्वविद्यालय के बाहर के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी गयी। इसके लिए विश्वविद्यालय के बाहर के उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रों को एनईपी 2020 के अनुरूप 4-वर्षीय यूजी प्रोग्राम में पंजीकृत होना चाहिए। सभी छात्रों के क्रेडिट अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर अपलोड किए जाने चाहिए। सेमेस्टर 7 में प्रवेश के लिए छात्रों को सेमेस्टर 6 तक सीजीपीए 7.5 और ऊपर होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रवेश कक्ष को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान खाली सीटों का विज्ञापन देना होगा। प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय प्रवेश कक्ष द्वारा तय की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संकाय को एलयू में कम से कम एक सेमेस्टर के लिए होस्ट किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय आवास और संबंधित ग्रांट प्रदान करेगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत असाधारण उपलब्धियों और अनुभव वाले पेशेवरों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत स्नातक में वीबीए और परास्नातक में राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाज कार्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, और एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनैन्स, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स, एमबीए इंटरनेशनल बिजनस और इसके लिए बोर्ड आफ ऑनलाइन प्रोग्राम के सृजन का निर्णय लिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध महाविद्यालय (ऐडेड) के ऐसे शिक्षक जो बिना पीएचडी के नियुक्त हुए हैं, उनको पीएचडी में सुपर न्यूमेरिक सीट पर प्रवेश होगा। साथ ही योग में सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन होगा।

स्थापना दिवस पर दिलाई सुरक्षा की शपथ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सड़क यातायात दुर्घटना हमारे देश में मृत्यु और विकलांगता के सबसे आम कारणों में से एक है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में 4.1 लाख सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई। दुर्भाग्य से, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 18-45 वर्ष है, जो कुल दुर्घटना मौतों का लगभग 70 प्रतिशत है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ने बुधवार को सुरक्षा की शपथ दिलाई।

एपेक्स ट्रामा सेंटर के छठें स्थापना दिवस पर एसजीपीजीआई एमएस के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमान ने कई स्कूलों के बच्चों को शपथ दिलाते हुए कहा कि जो हमारे देश का भविष्य और पथप्रदर्शक हैं। स्कूली बच्चों के माध्यम से सुरक्षा की यह शपथ उनके परिवार और समाज में सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी। विशेष अतिथि सलमान ताज पाटिल, डीसीपी ट्रैफिक- लखनऊ ने 4-ई की भूमिका पर जोर दिया और ये हैं इंजीनियरिंग- बेहतर सड़क निर्माण पर जोर देना, शिक्षा- आम जनता को सड़क यातायात सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना, प्रवर्तन- यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो जुर्माना लगाकर और आपातकाल- जहां कोई दुर्घटना होने पर कदम उठाए जाते हैं और क्षति नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। विचार-विमर्श के दौरान डीसीपी सलमानताज ने जोर दिया कि केवल पुलिस द्वारा प्रवर्तन ही भयावह स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-लखनऊ पीठ ने सड़कों और राजमार्गों के समुचित निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) की भूमिका पर जोर दिया और साथ ही विकासशील देशों में इस महामारी से लड़ने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करने के लिए नगर निगम के योगदान पर जोर दिया। माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने इन प्रभागों की जवाबदेही और आम जनता के बीच सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन पर भी जोर दिया।

फेफड़ों के कैंसर के लगभग 70 फीसद मामले पुरुषों के: डॉ. वेद प्रकाश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

फेफड़ों का कैंसर भारत में सबसे आम कैंसरों में से एक है। भारतवर्ष में अनुमानित रूप से लगभग 67,000 नए मामले हर साल सामने आते है। भारतीयों में पुरूषों में फेफड़े का कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो सभी कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 9.3 फीसद है। भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 7.6 पुरूष एवं 2.1 महिलायें फेफड़े के कैंसर से ग्रसित है। बुधवार को यह जानकारी किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभाग प्रमुख डॉ. वेद प्रकाश ने दी है।

विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि फेफड़े के कैंसर के लिए धूम्रपान एक प्रमुख कारक है, जो भारत में फेफड़ों के कैंसर के लगभग 85 फीसद मामलों में योगदान देता है। अन्य महत्वपूर्ण कारकों में खाना पकाने के ईंधन से इनडोर वायु प्रदूषण, व्यावसायिक जोखिम (जैसे, एस्बेस्टस), और बाहरी वायु प्रदूषण शामिल हैं। भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर काफी ज्यादा होता है। फेफड़ों के कैंसर के लगभग 70 फीसद मामले पुरुषों में होते हैं। भारत में फेफड़ों के कैंसर की 5 साल की जीवित रहने की दर 5-10 फीसद है जो कि विश्व की तुलना में काफी कम है। डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (एनएससीएलसी) सबसे आम प्रकार है, जो लगभग 80-85 फीसद मामलों में होता है, जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर (एससीएलसी) शेष 15-20 फीसद मामलों में होता है।

फेफड़े के कैंसर के कारण

फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण, लगभग 85 फीसद मामलों के लिए जिम्मेदार है। सिगरेट के धुएं में कार्सिनोजेन्स होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। रेडॉन, एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेडियोधर्मी गैस है जो कि कुछ औद्योगिक उद्यमों में इस्तेमाल होता है और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। आनुवांशिक कारण भी फेफडे के कैंसर के लिए जिम्मेदार है।

फेफड़े के कैंसर के लक्षण

लगातार खांसी रहना, खांसी में खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गला बैठना, वजन घटना, भूख न लगना, थकान, बार-बार संक्रमण होना, चेहरे या गर्दन में सूजन, हड्डी में दर्द, सिरदर्द, इत्यादि लक्षण फेफडे के कैंसर के रोगियों को हो सकते है।

फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम

धूम्रपान छोड़ें, व्यावसायिक खतरों से बचें, वायु प्रदूषण को कम कर, फलों और सब्जियों से भरपूर आहार फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इन खाद्य पदार्थों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट और अन्य पोषक तत्व फेफड़ों के समग्र स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं।

जीबीएम में शिक्षकों की सेवानिवृत आयु 65 वर्ष करने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की बुधवार को सम्पन्न हुई आमसभा की बैठक में शिक्षकों की सेवानिवृत आयु को 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष करने की मांग की गयी। साथ ही 103 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की गयी। बैठक में मांग की गयी कि शिक्षकों को राज्य के अन्य अधिकारियों तथा अन्य राज्यों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरह ग्रेजुएटी की सुविधा प्रदान की जाए। महामंत्री डॉ. अनित्य गौरव ने बैठक के बारे में बताया कि राज्य के अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तरह शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की गयी है। यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से इन्क्रीमेंट देने के साथ ही बैठठ में सरकार से 28 मार्च 2005 के विज्ञापन के बाद के विज्ञापनों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की गयी।

उमस भरी गर्मी और खेती-किसानी के मौसम में जारी रखें पर्याप्त बिजली आपूर्ति: मुख्यमंत्री

● सभी मंत्रिगण जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए एक समय नियत करें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में विद्युत आपूर्ति, खाद आपूर्ति, नहरों में पानी और निराश्रित गोवंश को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उमस भरी गर्मी और खेती-किसानी के मौसम में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाए। कहीं भी अनावश्यक कटौती न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि टोल फ्री नंबर 1912 एक्टिव रखने के साथ ही उपभोक्ता की आने वाली कॉल पर प्रतिक्रिया जरूर दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के मंत्री के पास हर डिस्कॉम के हर दिन की स्थिति का पूरा विवरण होना चाहिए। मांग और आपूर्ति पर माननीय मंत्री द्वारा स्वयं नजर रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मंत्रिगण जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए एक समय नियत करें। जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें उनकी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को समझें और यथोचित निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि भूमिगत बिजली केबल डालने से पहले स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक करके रणनीति तय करें। कब, कहाँ, कैसे केबल डालनी है, मिलकर तय करें। आमजन की सुविधा का पूरा ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फीडर के अनुसार विभाग से जुड़े कर्मियों को इंचार्ज बनाएं और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। साथ ही जिन क्षेत्रों में आवश्यक हेतु विद्युत कटौती करनी पड़ रही है, वहां पर दिन में अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सिर्फ टिब्यूएल के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है, वहां के कृषि फीडर को रोस्टर के अनुसार 12 घंटे विद्युत की आपूर्ति अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने विद्युत प्लांट के क्षमता विस्तार और नए विद्युत प्लांट की स्थापना के कार्य में तेजी लाएं। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय विद्युत कटौती न हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा ऐसा मैकेनिज्म विकसित करें कि डिस्कॉम, जोनल, जनपद और फिर स्टार की जवाबदेही तय की जा सके। सीएम योगी ने कहा की बिजली चोरी के मामलों में पहले की अपेक्षा काफी अंकुश लगा है, इसको और बेहतर करते हुए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। नहरों में पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मानसून सीजन में प्रदेश के 31 जनपदों में सामान्य से ज्यादा, वहीं 43 जनपदों में औसत से कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के एक जनपद में अभी तक न के बराबर बारिश हुई है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसी योजना बनाएं कि प्रदेश में बारिश हो या न हो, लेकिन हर खेत को पानी मिले। सीएम योगी ने कहा कि जिन जनपदों में राजकीय नलकूप खराब हैं, उनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 जनपदों में नहरें 80 प्रतिशत के ऊपर टेल फीड हो चुकी हैं, अवशेष जिलों में भी बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। खाद आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के लगभग हर जनपद में 20-25 दिन की खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि खाद से जुड़ी समितियों के पास भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक किसान को उसकी जरूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए। निराश्रित गोवंश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में वृहद संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। बैठक में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, एके शर्मा, दिनेश खटीक, बलदेव सिंह औलख, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर आदि की उपस्थिति रही।

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो प्रदेश में सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति: ऊर्जा मंत्री

● ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली विद्युत् समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त अपूर्ति देकर पूरी की जाए। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21.30 घण्टे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 3 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है और इसी दौरान सुबह 9 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 2 घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में 2 घण्टे की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यूपीपीसीएल में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही प्रदान किए गए देय व पेंशन प्रपत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं अन्य ऊर्जा निगमों में कार्मिकों के हितों को देखते हुए एक नई शुरूआत की गई है। इसके तहत सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य लाभों से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र सेवानिवृत्ति के दिन ही सौंप दिए जाते हैं। इससे उन्हें पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े।

इसी के तहत बुधवार को उप्र पावर कारपोरेशन एवं अन्य ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 18 सेवानिवृत्त कामिकों को पेंशन प्रपत्र भेंट करते हुए उनका अभिनन्दन किया। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार द्वारा विभागों में त्वरित गति से कार्यों के निष्पादन हेतु किए जा रहे प्रयासों का अब सामान्य नागरिकों के साथ ही विभागीय कार्मिकों को भी लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. गोयल ने कहाकि पहले ऊर्जा निगमों में सेवानिवृत्त के बाद भी कार्मिक पेंशन प्राप्ति के लिए परेशान होते थे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस समस्या को पहचानकर इस पर गंभीरता से कम किया गया है, जिससे इसे समाप्त करने में सफलता मिली है। सेवानिवृत्ति के दिन ही कार्मिक को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों के पेपर प्राप्त हो जाते है। पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था सख्ती से लागू की गई है। पेंशन अदालतें चालू की गई है जो प्रत्येक तीन महीने पर लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के साथ इम्पलाइज वेलफेयर नीति भी चलनी चाहिए, जिससे विभाग के किसी भी कर्मचारी को अपने सही कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े। सेवानिवृत्त कार्मिकों ने अपने सम्बोधन में सरकार, प्रबन्धन विशेषकर अध्यक्ष को इसके लिए साधूवाद दिया। कार्मिकों ने कहाकि पूरी नौकरी के दौरान सेवानिवृत्ति पर सम्पूर्ण प्रपत्र मिलता हुआ पहली बार देखा जा रहा है।

मुख्य सचिव ने किया सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त हुए 33 कार्मिकों को सम्मानित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के 33 कार्मिकों को सेवानिवृत्त होने के अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवानिवृत्त सचिवालय कार्मिकों को सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन, उपादान, राशिकारण, अवकाश नकदीकरण व जीपीएफ) से सम्बन्धित आदेशों का भी वितरण किया।

मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त कार्मिकों को आगामी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सेवानिवृत्त होने के दिन ही सभी प्रकार के पेंशन व सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त होना, इस बात का सबूत है कि कार्मिक ने एक सफल व बेदाग सेवा पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में आना सौभाग्य की बात है। इस सेवा के माध्यम से समाज के बारे में सोचने व कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी वह समाज के लिए अपनी रुचि के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अपने अनुभवों का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए करें।

प्रदेश के 7 नये मेडिकल कॉलेजों को मिला लेटर ऑफ परमीशन, इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई

● नये मेडिकल कॉलेजों की अपील पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया लेटर ऑफ परमीशन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को सुदृढ़ करने के प्रयास में जुटी योगी सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के 7 नये मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र (वर्ष 2024-25) से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 13 नये मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की थी, जिसके बाद के सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन जारी कर दिया है। वहीं बचे हुए 6 मेडिकल कॉलेज की ओर से एनएमसी में दोबार अपील की जाएगी, विभाग की मानें तो है इन्हें भी जल्द लेटर ऑफ परमीशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने की अनुमति भी प्राप्त हुई है। इनमें सरकारी, प्राइवेट और पीपीपी मॉडल पर संचालित मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके बाद प्रदेश का मेडिकल शिक्षा विभाग इस शैक्षणिक सत्र में 10 हजार 500 एमबीबीएस सीटों पर काउंसिलिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन जारी किया गया है। इन सातों मेडिकल कॉलेज में 600 एमबीबीएस सीटों पर काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आगरा और मेरठ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को क्रमश: 72 और 50 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि की गई है। इसके बाद आगरा मेडिकल कॉलेज में 200 और मेरठ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हो गई हैं।

निजी और पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी सीटें: डीजीएमई किंजल सिंह के अनुसार पीपीपी मोड में संचालित शामली, महाराजगंज और संभल के मेडिकल कॉलेजों में भी क्रमश: 150, 150 और 50 एमबीबीएस सीटों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन प्राप्त हुआ है। वहीं निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा इस शैक्षणिक सत्र के लिए 50 एमबीबीएस सीटों के लिए एलओपी जारी की गई है।

राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध कराने का पर्व है काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष

● 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर फहरेगा राष्ट्रध्वज तिरंगा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर कथानक ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। आगामी 9 अगस्त को शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे, वहीं स्वाधीनता दिवस तक हर घर तिरंगा फहरा कर अमर शहीदों को नमन भी किया जाएगा।

बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन देश के स्वाधीनता समर की अमर कहानी है। यह राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध कराने वाला पर्व है। अगले वर्ष 2025 में जबकि इस घटना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो यह अपने अमर नायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का एक सुअवसर है। उन्होंने कहा इस वर्ष 9 अगस्त को काकोरी में मुख्य समारोह के आयोजन के बाद प्रदेश के प्रत्येक शहीद स्मारक पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। 9 अगस्त को स्कूलों में प्रभात फेरी निकल जाए। स्कूलों ,कॉलेजों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में डिबेट का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाए । यह पेंटिंग स्थानीय या क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित हो। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन के अवसर पर प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के माध्यम से राष्ट्र गीत के धुन बजाया जाए। इससे पूर्व शहीद स्मारकों के आस-पास स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। विभिन्न अस्पतालों में फलों का वितरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन के अवसर पर हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा लगाए जाए। यह एक जनांदोलन के रूप में हो। एक पोर्टल तैयार किया जाए, जिस पर लोग अपने घरों पर तिरंगा लगने के बाद सेल्फी लेकर उसे अपलोड करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में गौरव गाथा स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र चिंतन विचार ,शहीदों को नमन, पर्यावरण संरक्षण एक जीवन शैली, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास, समर्पण एवं राष्ट्र की सेवा इत्यादि विषयों पर काकोरी ट्रेन एक्शन पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

अयोध्या मॉडल सोलर सिटी घोषित, शुरू हुई 40 मेगावॉट की सौर परियोजना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अयोध्या के विकास में जुटी योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा के जरिए 40 मेगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने के साथ ही अयोध्या शहर अब मॉडल सोलर सिटी के रूप में घोषित हो गई है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति के अंतर्गत सोलर सिटी को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10 फीसदी की कमी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्राप्त की जा सके। इस लिहाज से अयोध्या शहर ने दोगुनी क्षमता का विकास कर लिया है। दरअसल, अयोध्या शहर की अनुमानित मांग 198 मेगावाट है, इसके 10 प्रतिशत यानी लगभग 20 मेगावॉट के सापेक्ष सोलर पॉवर प्लांट की क्षमता 40 मेगावॉट हो चुकी है। इस सोलर प्लांट की स्थापना एवं कमिशनिंग का काम निर्धारित समयावधि में पूरा किया गया है। प्लांट को सरयू नदी के पास ग्राम माझा रामपुर हलवारा और ग्राम माझा सरायरासी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। बता दें कि इस सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 165.10 एकड़ सरकारी भूमि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 1 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 साल के लिए लीज पर उपलब्ध कराई गई है। यहीं पर 40 मेगावॉट क्षमता की सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। इस प्रोजेक्ट से उत्पादित होने वाली ऊर्जा को कॉस्ट प्लस के आधार पर निर्धारित टैरिफ पर यूपीपीसीएल द्वारा 25 साल तक खरीदी जाएगी। 40 मेगावॉट क्षमता की सौर पॉवर परियाजना स्थापित होने के परिणामस्वरूप अयोध्या शहर मॉडल सोलर सिटी घोषित की गई है।

बीकेयू के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और यूनियन के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मुख्य सचिव को दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान हितैषी कई निर्णय लिए गए हैं और भविष्य में भी आवश्यकतानुसार उनके हित में कल्याणकारी निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों को किसानों की विभिन्न समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का परीक्षण कर जल्द से जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

राहुल की जाति पूछने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने फूंका अनुराग ठाकुर का पुतला

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए कथित अमर्यादित बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में कांग्रेसजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ठाकुर का पुतला फूंका गया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण के दौरान जननायक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछने सम्बन्धी अमर्यादित बयान पर कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश है। राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जा रही है उससे देश का जनमानस कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहा है जिसका उदाहरण देश में कुछ दिनों पूर्व हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राहुल गांधी जी द्वारा जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है, और अनुराग ठाकुर का यह बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। पर अब देश की जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों को भलि भांति पूर्वक समझ चुकी है और आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कांग्रेसजनों ने आज जिला/शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, अमित श्रीवास्तव त्यागी एवं डॉ. शहजाद आलम के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपा के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया तथा पूर्व मंत्री का पुतला फूंका। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसजनों को बलपूर्वक रोका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।

रेलवे कर्मचारियों समेत चार आरोपियों को सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

रेलवे के सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एनईआर, गोरखपुर के तत्कालीन रिकार्ड लिफ्टर भरत यादव व लेखा अनुभाग के तत्कालीन सीनियर अटेंडेंट अनिल कुमार मंडल को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ इन पर क्रमश: 40 व 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने इस मामले में राकेश कुमार मिश्र उर्फ लड्डू बाबा को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस पर पांच लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। वहीं एक अन्य आरोपी राजेश कुमार सिंह को तीन वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। 31 अक्तूबर 2012 को सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया था। आरोप था कि रेलवे को ठगी/ धोखा देने के आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ाने हेतु आरोपियों ने एनईआर रेलवे, गोरखपुर के मूल चेक को स्कैन करके रेलवे का जाली चेक बनाया। ऐसे जाली चेकों को एसबीआई मुख्य शाखा, गोरखपुर में जमा किया और रेलवे को आर्थिक क्षति पहुंचाई।

ईओडब्लू ने वित्तीय निगम के पूर्व सहायक प्रबंधक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया

● लाखों रुपए गबन के मुकदमे में थी तलाश, रेड कार्नर नोटिस भी हुआ था जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लाखों रुपए गबन करने वाली फर्म के साथ आपराधिक साजिश में शामिल रहने के आरोपी अनिल कुमार खन्ना, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक, (टेक्निकल) उप्र वित्तीय निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा को स्वीटजरलैंड से लौटते ही ईओडब्लू ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। खन्ना के खिलाफ ईओडब्लू ने रेड कार्नर नोटिस भी जारी करवा रखा था।

दुर्गा वायर एण्ड फिलामेन्ट प्रा.लि., ग्रेटर नोएडा, गोतमबुद्ध नगर के प्रमोटरों द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक षडयन्त्र कर उप्र वित्तीय निगम, क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा से 37,05,000 रुपए शॉट टर्म लोन लेने तथा उक्त फर्म के प्रोराइटर पंकज खन्ना तथा उप्र वित्तीय निगम के तत्कालीन सहायक प्रबन्धक अनिल कुमार खन्ना के साथ दुरभिसंधि कर गबन किए जाने के सम्बन्ध मे थाना सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना उप्र शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2000 को ईओडब्लू को हस्तान्तरित की गई।

उक्त अभियोग से सम्बन्धित आरोपी वांछित अभियुक्त अनिल कुमार खन्ना निवासी एम-21, साकेत मन्दिर मार्ग, दिल्ली की गिरफ्तारी के लिए 21.6.2017 को उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। 29.7.2024 को अभियुक्त अनिल कुमार खन्ना उपरोक्त को इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर ज्यूरिक (स्विटजरलैण्ड) से भारत आने पर रोका गया।

प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बढ़ते शहरीकरण के साथ ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे ध्यान में रखते हुए कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शहरों से प्रतिदिन निकलने वाले हजारों टन कूड़े को प्रॉसेस करके न केवल सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि वेस्ट टू वंडर योजना के तहत पार्कों का भी निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में विस्तार से जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि कूड़ा प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा प्रदेश के नगरों की एयर क्वालिटी भी देश के तमाम शहरों से बहुत अच्छी है। प्रदेश में प्रतिदिन 20 हजार टन सॉलिड वेस्ट निकलता है, हालांकि अभी फिलहाल 15 हजार टन सॉलिड वेस्ट को प्रॉसेस किया जाता है। बताया कि सरकार इस क्षमता को तकरीबन दोगुना करते हुए 12 हजार टन प्रतिदिन का इजाफा करने जा रही है। प्रदेश में फिलहाल 933 एमआरएफ सेंटर हैं, जिनमें से 711 कार्यरत हैं, जहां सॉलिड वेस्ट को प्रॉसेस करने का कार्य हो रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिड वेस्ट को प्रॉसेस करते हुए इनसे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में न्यू हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय की रोड को अबर्न वेस्ट को प्रॉसेस करके बनाया गया है। कूड़े को प्रतिदिन घरों से उठाकर एमआरएफ सेंटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एयर प्रेशर से प्रॉसेस किया जाता है। प्रॉसेस्ड मैटेरियल का तीन प्रकार से उपयोग होता है। इसमें प्राइवेट वेंडर्स को प्लास्टिक का री-यूजेबल मैटेरियल देना, सड़कें बनाना और वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने में उपयोग शामिल है।

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिले अहम सुराग क्राइम टीम ने की छानबीन तेज

मोहनलालगंज। शराब दुकानों से कैश लेकर लौट रहे मैनेजर से ढ़ाई लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे हैं। लिहाजा क्राइम टीम पूछताछ के जरिए जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी शीघ्र ही मामले के खुलासे का दावा कर रहे हैं। उन्नाव के कब्बा खेड़ा तिराहा निवासी पंकज जायसवाल शराब दुकानों पर मैनेजर है। पंकज के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 10 बजे वह सिसेंडी और भागू खेड़ा समेत अन्य शराब की दुकानों से ढ़ाई लाख रुपए कैश लेकर बाइक से पीजीआई की ओर जा रहे थे। तभी रायबरेली हाईवे पर पीछे से आए कार सवार तीन बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया। फिर रुपयों से भरा उनका बैग और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सिसेंडी और भागू खेड़ा से लेकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को खुलासे की राह बना रहे सुराग हाथ लगे हैं। एडीसीपी साउथ शशांक सिंह ने बताया सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। अभी भी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस की क्राइम टीम लगातार छानबीन और पूछताछ में जुटी हुई हैं। जांच तेजी से नतीजे की ओर बढ़ रही है। जल्द ही वारदात का अनावरण किया जाएगा।

अमेठी सबडिवीजन में गड़बड़ियों का खुलासा, शिकायत दबाने में जुटे अफसर

संवाददाता। मोहनलालगंज

अमेठी सबडिवीजन में गड़बड़ियों की शिकायतें बढ़ रही हैं। लेकिन खुलासों के बावजूद डिवीजन के अफसर इन पर काबू नही कर पा रहे हैं। यहां तक कि शिकायतों पर कार्रवाई के बजाए उन्हें ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा गड़बड़ियों को अंजाम दे रहे कर्मचारियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है।

मोहनलालगंज के अमेठी सबडिवीजन में इन दिनों सब कुछ ठीक नही है। कर्मचारियों की मनमानी से लेकर फील्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सलेमपुर की सुमन चौरसिया के बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के लिए उनका परिवार साल भर से अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। पीड़ित परिवार ने कनेक्शन की पीडी के लिए घूस मांगे जाने की शिकायत सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई। तब जाकर जोन के अफसरों के निर्देश पर एक्सइएन एसके अग्रवाल मामले की जांच करने पहुंचे। एक्सइएन ने बताया बकाया बिल का निर्धारण कर पीडी की कार्रवाई की गई है। हालांकि घूस मांगे जाने के आरोप को अधिकारी बेबुनियाद बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि साल भर तक पीडी आवेदन को लटकाने की वजह क्या निकलकर आई और उसके लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई। यही नही अमेठी सबडिवीजन में एक कर्मचारी ने अधिकारियों की अनुमति के बिना ही उपभोक्ता के परिसर से मीटर उखाड़ लिया। एसडीओ ने छापा मारा तो कर्मचारी की करतूत खुलकर सामने आ गई। पूछताछ में स्टोर मीटर रीडिंग के खेल का पता चला। मामले की भनक लगते ही कर्मचारी ने फिर से उपभोक्ता के परिसर पर मीटर लगा दिया। हालांकि एसडीओ ने चेकिंग रिपोर्ट भरकर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे मामले की जानकारी एक्सइएन को भी दी गई। लेकिन दस दिन बाद भी मामले में ठोस कार्रवाई नही हो सकी है। हालांकि एसडीओ ने बताया जल्द ही मामले में उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरनपुर सबस्टेशन में उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए लाइन दुरुस्त रखने के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन शिकायत के बावजूद जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं।

अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाया जाए विशेष अभियानः जिलाधिकारी

संवाददाता। सोनभद्र

शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में ओवर लोडिंग व अवैध परिवहन पर रोक लगायें जानें को लेकर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बुधवार को सलखन व इंको प्वाइंट के पास वाहनों की जॉच किया। मौके पर बिना माइन टैग व बिना नम्बर प्लेट व परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट नहीं पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस तरह से संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये, इसमें किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये, इस मौके पर 02 वाहन ओवरलोडिंग करते हुए भी पकड़े गये, जिसे चालान करके पुलिस की अभिरक्षा हेतु सम्बन्धित थानों को सुपुर्द कर दिया गया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने ट्रकों पर लगे नम्बर प्लेटों को देखा नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में नहीं पाये गये, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ज्येष्ठ खान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि टैम्पर्ट नम्बर बिना लगे प्लेटों का प्रयोग न किये जाये और नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में रहें, इसकी विशेष जॉच की जाये, अगर इस तरह की कोई वाहन पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसके लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जाये, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन करते हुए वाहनों का संचालन न होने पायें, जिलाधिकारी के निर्देशन में 14 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें से 12 वाहनों का आनलाईन चालान हुआ।

आनलाईन चालान किये गये, वाहनों में से 07 वाहन स्वामियों ने आनलाईन चालान के माध्यम से 5 लाख 59 हजार 560 रूपये की धनराशि मौके पर ही जमा कर दिया, खनन विभाग द्वारा जुलाई माह में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देशन में अब तक 629 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रूपये की वसूली की है। 8 अवैध परिवहन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गयी। इस मौके पर ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।

एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय रिहंद में विद्यार्थी परिषद का हुआ गठन

बीजपुर, सोनभद्र। केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी रिहंद नगर के प्राचार्य लालसा शाह की अध्यक्षता में विद्यार्थी परिषद 2024 का गठन किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉ गुलाब शंकर सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को कर्तव्य और उनके जिम्मेदारियो के बारे में अवगत कराया। प्राचार्य श्री साह ने विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। स्कूल कैप्टन के रूप में ब्वायज में वाणिज्य वर्ग के बारहवीं के छात्र आदित्य शर्मा गर्ल्स स्कूल कैप्टन शिबू सेन बारहवीं विज्ञान वर्ग की छात्रा को बनाया गया। स्कूल वाइस कैप्टन के रूप में ब्वायज में आदर्श पाण्डेय और गर्ल्स वाइस कैप्टन अदिति सिंह को तथा स्पोर्टस कैप्टन ब्वायज सर्वेश पाण्डेय और कुमारी अंजली को बनाया गया। शिवाजी सदन के अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद ने हाउस कैप्टन के रूप में मधु जायसवाल और ब्वायज में कृश कुमार तिवारी को, टैगोर हाउस के अध्यक्ष अनुराग प्रकाश ने हाउस कैप्टन के रूप में त्रिशा पाण्डेय और ब्वायज में अर्जुन सिंह को अशोक सदन की अध्यक्षा पूजा दीवान ने हाउस कैप्टन के रूप में अनामिका विश्वकर्मा और ब्वायज में मेराज आलम को रमन सदन की अध्यक्षा श्वेता कटियार ने प्रीति पासवान और ब्वायज में प्रतीक सिंह को हाउस कैप्टन के रूप में मनोनित कर बैज एवम् पट्टिका पहनाकर उन्हें सम्मानित किया।

मुंशी प्रेमचंद का प्रयागराज से रहा है गहरा लगावः देवेंद्र सिंह

संवाददाता। प्रयागराज

हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयागराज के तत्वावधान में बुधवार को एकेडेमी के प्रशासनिक कक्ष में मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती के अवसर पर प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान के संदर्भ में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन के साथ हुआ। अध्यक्षता करते हुए सचिव देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रेमचंद का हिन्दुस्तानी एकेडेमी से विशेष जुड़ाव रहा है। प्रेमचंद एकेडेमी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एकेडेमी का प्रतिष्ठित पहला एकेडेमी सम्मान दिया गया। एकेडेमी ने इनकी कहानी का अनुवाद हड़ताल को प्रकाशित किया है। मुंशी प्रेमचंद का प्रयागराज से बहुत लगाव था।

प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उनके समय में थी। प्रेमचंद ने किसानों मजदूरों की समस्या को उठाया। मुख्य वक्ता एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक रविनंदन सिंह ने कहा कि मुंशी प्रेमचन्द आदर्शवादी उपन्यासकार रहे हैं किन्तु बाद में यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की है। ऐसे उपन्यासों की शुरुआत सेवासदन 1918 से होती है। सामाजिक अत्याचार से पीड़ित नारी जीवन से जुड़ी वेश्यावृत्ति की समस्या का विश्लेषण किया गया है। गोदान अपने युग और समाज की महागाथा है। विचार गोष्ठी में प्रो रामपाल गंगवार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ ने कहा प्रेमचंद अपने नारी पात्रों को कर्म भाक्ति और साहस से संयुक्त करते हैं। स्त्री के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सवाल प्रेमचंद के साहित्य में देखे जा सकते है। प्रेमचंद कितने प्रगतिशील थे उसका उदाहरण है कि उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। विचार गोष्ठी में प्रो सरोज सिंह हिन्दी विभाग सीएमपी डिग्री कालेज ने कहा कि प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में सामाजिक कुरीतियों ग्रामीण जीवन की समस्याओं मजदूर किसान नेता उपदेशक राजा रंक सभी का यथार्थ चित्रण किया है।

आम जनता को सुलभता से मिले योजनाओं का लाभः बीडीओ

सकलडीहा, चन्दौली। मुख्य विकास अधिकारी सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव के निर्देश पर बीडीओ के सिंह ने बुधवार को खंड विकास सभागार में सचिव सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। इस दौरान विकास कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया। बरसात के दिनों में गांवों में होने वाले जल भरॉव की समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया। शासन के मंशा के अनुरूप सरकार की जनकल्याण कारी योजना का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश है। इस क्रम में बीडीओ के सिंह और एडीओ पंचायत बजरंगी पांडेय ने सचिव, तकनिकी सहायक, रोजगार सेवक और एपीओ के साथ समीक्षा बैठक किया। मनरेगा के संदर्भ मे कराये गये कार्यो की जानकारी लिया। इसके साथ पीएम और सीएम आवास के प्रगति के बारे में जानकारी हासिल किया। सचिवों को निर्देशित किया कि संचारी अभियान के तहत गांवों में साफ सफाई के साथ जलभरॉव की समस्या को तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराये। इसके साथ ही टूटी हुई नाली की मरम्मत और कूड़ा निस्तारण का उचित प्रबंध करें। निर्विरोध निर्वाचित जिला महामंत्री पवन दूबे को बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित सचिवों ने बुके और माला पहनाकर स्वागत किया।

छात्र संसद के द्वारा बच्चों में होता है नेतृत्व क्षमता का विकासः शीतला प्रसाद

संवाददाता। प्रयागराज

छात्र संसद से बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। भविष्य में वह किसी भी क्षेत्र में रहें इससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। यह बातें बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर सदियापुर में आयोजित छात्र संसद कन्या भारती एवं शिशु भारती के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता चतुर्थ शीतला प्रसाद गौड़ शीतल ने कहीं। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सही मार्गदर्शन और कर्तव्य पालन से ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। कहा कि विद्या भारती के विद्यालय चरित्र निर्माण की पाठशाला है। यहां पर बच्चों का चहुमुखी विकास होता है।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य स्थाई अधिवक्ता चतुर्थ शीतला प्रसाद गौड़ शीतल ने शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में छात्र संसद से प्रधानमंत्री आदित्य शर्मा उप प्रधानमंत्री आर्यन जायसवाल कन्या भारती से प्रधानमंत्री दीक्षा मिश्रा उप प्रधानमंत्री आस्था मौर्या एवं शिशु भारती से अध्यक्ष सत्यम सिंह मंत्री प्रखर मालवीय सेनापति श्याम सुन्दर आदि ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने छात्र संसद कन्या भारती एवं शिशु भारती के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए विद्यालय और राष्ट्र हित में कार्य करते रहने और भविष्य में उच्चतम पद प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के कोषाध्यक्ष अजय खुराना ने की। इससे पहले मुख्य अतिथि अधिवक्ता परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शीतला प्रसाद गौड़ और अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जवलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इफको इम्पलाइज यूनियन के चुनाव की हुई घोषणा

प्रयागराज। इफको फूलपुर इकाई में इफको इम्पलाइज यूनियन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा चुनाव अधिकारी पी के पटेल ने बुधवार को कर दी। उन्होंने बताया कि नामांकन इकतीस जुलाई एवं एक अगस्त सुबह साढ़े ग्यारह बजे से अपराह्न साढ़े तीन बजे तक पुराने एच ब्लाक में होगा। नामांकन पत्रों की जांच एक अगस्त वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन एक अगस्त नाम वापसी दो अगस्त उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन एवं सूची का प्रकाशन का प्रकाशन दो अगस्त जबकि मतदान छह अगस्त सुबह साढ़े पांच बजे से अपराह्न साढ़े तीन बजे तक कैन्टीन हॉल में सम्पन्न होगा। मतगणना छह अगस्त सायं चार बजे से तथा चुनाव परिणाम छह अगस्त को जारी होंगे। इम्पलाइज यूनियन का चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री संयुक्त मंत्री संगठन संयुक्त मंत्री प्रचार कोषाध्यक्ष सहायक मंत्री कार्यकारी सदस्य पदों पर होगा। यह जानकारी स्वयम प्रकाश जनसम्पर्क अधिकारी इफको फूलपुर ने दी।

क्विक न्यूज

निदेशक, महाप्रबंधक व साइड इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज

सोनभद्र। ओबरा सी थर्मल पावर कार्पोरेशन के निर्माण संविदाकार दुसान कम्पनी का सह संविदाकार इंडवेल कंपनी के निदेशक के0 वाई0 चक्रवर्ती, महाप्रबंधक जी श्री निवास राव एंव साइड इंचार्ज बी0 पी0 ज्ञानेश्वर के बिरुद्ध अधिवक्ता विकाश शाक्य द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मे0 इन्डवेल कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 कम्पनी ओबरा तापीय परियोजना के सी प्लांट विस्तारीकरण मे दुसान कंपनी की निर्माण में सहायक कंपनी थी। इन्डवेल ने स्थानीय स्तर पर के0 एन0 इंस्ट्रूमेंट फर्म के प्रोपराइटर काशीनाथ प्रसाद से कार्य कराया। कार्य के सापेक्ष 8369117 रूपयें का हिसाब था। बकाया पैसा मांगने पर गाली गलौज और मारपीट करने पर उतर आये तथा बगैर भुगतान के सारा समान लेकर भागने लगे तब परियोजना ने काशीनाथ प्रसाद के याचना पर सामानों की निकासी पर रोक लगा दी परंतु बकाया धनराशि का संदय नहीं किया जा रहा था इस प्रकरण के पूर्व डीएलसी कार्यालय पिपरी तथा राबर्ट्सगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मामला चला परंतु कोई सफलता नहीं मिलने पर अधिवक्ता विकाश शाक्य ने काशीनाथ प्रसाद की ओर से याचिका सोनभद्र न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट दीक्षी चौधरी की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने आदेश ओबरा थाना को दिया है।

मच्छरदानी वितरण व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सोनभद्र। एनटीपीसी विंध्याचल सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को ग्राम बलियरी में मच्छरदानी वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के लोगों और महिलाओं को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों, जैसे डेंगू, मलेरिया आदि से बचाव करना था। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यपालक सीएसआर निखिल जायसवाल और उनकी टीम ने मच्छरदानियों का वितरण किया। निखिल जायसवाल ने ग्रामीणों को मच्छरों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी साथ ही सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया। स्थानीय वार्ड पार्षद अनुष्का यादव ने एनटीपीसी विंध्याचल सीएसआर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुये आभार प्रकट किया। लगभग 200 मच्छरदानियों का वितरण किया गया, कार्यक्रम से ग्रामीण समुदाय में एक सकारात्मक संदेश गया कि एनटीपीसी विंध्याचल न केवल ऊर्जा उत्पादन में बल्कि नैगम सामाजिक दायित्व मे भी अपना सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

डेंगू मलेरिया से बचाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन

सोनभद्र। हिंडाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आर पी सिंह के निर्देशन व हेड एच आर रेनुसागर शैलेश विक्रम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण विकाश विभाग रेनुसागर ने टेक्नीकल ट्रेनिंग सेंटर रेनुसागर में डेंगू मलेरिया के बचाव पर मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला मलेरिया अधिकारी धर्मेंद्र नारायण श्रीवास्तव ने लोगो को जागरूक करते हुये कहा कि डेंगू मलेरिया एवं वेक्टर जनित जैसी खतरनाक बीमारियों पर जनसहभागिता के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। समय-समय पर एन्टीलारवल का छिड़काव, फॉगिंग तथा सोर्स रिडक्शन के द्वारा मच्छर के घनत्व को कम किया जा सकता है। डेंगू के मच्छर घर के आसपास इकट्ठा हुए पानी में पनपते हैं। साप्ताहिक अंतराल पर साफसफाई एवं सोर्स रिडक्शन के द्वारा लार्वा समाप्त हो जाता है। घर के अंदर कूलर टूटे बर्तन फ्रिज की ट्रे गमले टायर निष्प्रयोज्य बर्तन ओवरहेड टैंक एवं छत पर इकट्ठा हुए पानी में मच्छर के लार्वा पनपते हैं। जिसे बहुत आसानी से पानी गिराकर एवं अंदर की सतह को साफकर डेंगू से बचा जा सकता है। डेंगू मलेरिया की जांच एवं उपचार समस्त सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त उपलब्ध है। इसका पूर्ण उपचार संभव है।

मुक्त विश्वविद्यालय में राजर्षि टंडन स्मृति व्याख्यान माला आज

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के जन्म दिवस पर एक अगस्त को अपराह्न तीन बजे सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्मृति व्याख्यान माला के 17वें पुष्प का आयोजन होगा। राजर्षि टंडन जन्म दिवस आयोजन समिति के समन्वयक प्रो एस कुमार ने बताया कि व्याख्यानमाला के मुख्य अतिथि आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ला पूर्व अध्यक्ष हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर भारत भारती के आराधक स्थित प्रज्ञ राजर्षि विषय पर व्याख्यान देंगे। सारस्वत अतिथि अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम करेंगे। आयोजन सचिव प्रो अजेंद्र कुमार मलिक ने बताया कि इस अवसर पर कुलपति एवं अन्य अतिथियों द्वारा अटल प्रेक्षागृह में राजर्षि टंडन पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा।

प्रयागराज मंडल को मिला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से प्रमाणपत्र

संवाददाता। प्रयागराज

मण्डल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बडोनी के नेतृत्व में प्रयागराज मण्डल भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जन के संकल्प में अपना योगदान पूरी क्षमता से दे रहा है। प्रयागराज मण्डल द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन के प्रयास के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023 24 में छह सौ किलो वाट क्षमता से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं। रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रयागराज मण्डल ने अपनी ऊर्जा खपत को निरंतर कम करते हुए वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। प्रयागराज मंडल अपने ऊर्जा दक्षता मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए समर्पित है।

इसी क्रम में बीस जून को प्रयागराज मण्डल द्वारा स्थापित उत्कृष्ट एवं स्वच्छ ऊर्जा निर्माण के लिए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित तीन कार्यालय भवनों पावर हाउस गंगा ब्लॉक एवं सरस्वती ब्लॉक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा प्रतिष्ठित शून्य प्लस और शून्य लेबल से प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से सम्मान प्राप्त करने वाली यह इमारतें उत्तर मध्य रेलवे का प्रथम रेलवे कार्यालय भवन हैं। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने बताया कि इस स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से प्रति वर्ष 2263469 रुपये की बचत एवं लगभग 288 टन कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

यह उपलब्धि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में रेलवे के प्रयासों का एक प्रमाण है। भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक मिशन का हिस्सा होने पर प्रयागराज मंडल गर्व है। यह ऊर्जा प्रमाणपत्र तीन वर्षों के लिए वैध हैं। इस उपलब्धि पर वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर कुँवर सिंह यादव ने कहा कि रेलवे में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन पर कार्य किया जा रहा है। इस ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से रेलवे की पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन मिला है। सोलर ऊर्जा उत्पादन सयंत्रों के नियमित सफाई और गुणवत्तापूर्ण रख रखाव से बेहतर उत्पादन क्षमता और उच्च ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रयागराज मण्डल में स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहतर प्रयासों से स्थापित 4465 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल में से 1030 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल रिन्यू एनर्जी द्वारा 2490 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल अजूर एनर्जी द्वारा एवं 945 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल स्वयं रेलवे द्वारा स्थापित किए गए हैं।

प्रयागराज मण्डल के प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज छिवकी नैनी कानपुर सेंट्रल टूंडला मानिकपुर इटावा दादरी फ़तेहपुर विंध्याचल शिकोहाबाद मिर्ज़ापुर एवं सूबेदारगंज स्टेशन पर सोलर पैनल कार्यरत हैं। यह जानकारी अमित कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज मण्डल उत्तर मध्य रेलवे ने दी।

जिलाधिकारी ने किया सैदपुर तहसील में स्थलीय निरीक्षण

गाजीपुर। जनपद की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने तहसील सैदपुर के विभिन्न कक्षो व पटलो का स्थलीय निरीक्षण किया तथा तहसील मे आये हुए व्यक्तियो से बात चीत कर तहसील मे कार्यरत कर्मचारी के व्यवहारो के बारे मे जानकरी ली। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी न्यायालय कक्ष, नायब तहसीलदार कक्ष, न्यायालय तसीलदार कक्ष, रजिस्ट्रार कानून-गो कक्ष, अभिलेखागार, संग्रह रिकार्ड रूम, कम्प्युटर कक्ष, आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पटलों पर कार्य संतोष जनक रहा एवं कुछ पटलो पर कमियां मिली तथा रजिस्टर के रख रखाव सही ढंग से नही होने पर हिदायत दी गयी। जिलाधिकारी ने सभी पटल सहायको को निर्देश दिया कि जितने भी शिकायती पत्र, बटवारे का वाद, धारा 24 व धारा 116 एवं फाईले लंबित है उसे यथाशीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही उन्होने परिसर की साफ-सफाई, परिसर मे पेयजल व्यवस्था व शौचालयों की साफ सफाई का निर्देश दिया।

राहुल गांधी की जाति के सवाल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, फूंका अनुराग ठाकुर का पुतला

संवाददाता। गाजीपुर

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आज कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) के विरुद्ध भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जाति सूचक अलोकतांत्रिक बातें लोकसभा में सदन के सत्र के दौरान कही गई, जिसका सभी विपक्षी सांसदों द्वारा कड़ी आपत्ति भी जताई गई थी, इसी के के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिला और शहर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में 31 जुलाई बुधवार दिन में लगभग 2 बजे दिन में, सरजू पांडे पार्क कचहरी में विरोध प्रदर्शन कर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया है।

इस अवसर पर पुलिस का विरोध झेलते हुए जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि कल 30 जुलाई को भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन ने जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे भाजपा सांसद द्वारा जातिसूचक अलोकतांत्रिक अपशब्द कहे जाने का हम लोग सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें, माफी मांगे नहीं तो ये प्रदर्शन और तीव्र होगा। शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा एआईसीसी सदस्य रविकांत राय ने संयुक्त रूप से कहा कि गरीबों के हित की बात एनडीए और भाजपा सरकार को पसंद नहीं आ रही है, हार से परेशान भाजपा के पूर्व मंत्री सदन में अनाप शनाप बोल रहे हैं जो गलत है, जिसका हम लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं।

पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ मार्कंडेय सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि जिस तरह से एक भाजपा सांसद द्वारा नेता प्रतिपक्ष का अपमान सदन में किया गया है, यह द्वेषपूर्ण और गलत बात है इसका हम लोग तब तक विरोध करेंगे जबतक सदन में पूर्व मंत्री माफी नहीं मांगेंगे, इस पर लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही करनी चाहिए। फिलहाल इस धारणा प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जनक कुशवाहा अजय कुमार श्रीवास्तव ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना सुमन चौबे राजेश गुप्ता विद्याधर पांडे आशुतोष गुप्ता चंद्रिका सिंह उषा चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे।

भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष का निधन

गाजीपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता दिलदारनगर के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत दिलदारनगर के पूर्व नामित सभासद हरिलेश जायसवाल उम्र 56 वर्ष निवासी दिलदारनगर का मंगलवार रात्रि दौरान चिकित्सा बीएचयू में निधन हो गया। वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इनके पिछे परिवार में पत्नी रीना देवी, दो पुत्र ईशान जायसवाल, सर्वेश जायसवाल तथा पुत्री साक्षी जायसवाल है। इनकी अंत्येष्टि बुधवार को वाराणसी मणिकर्णिका घाट हुई। मुखाग्नि बड़े बेटे ईशान जायसवाल ने दी। इस असामयिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी मे शोक व्याप्त है। निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हरिलेश जायसवाल भाजपा के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे।उनका असमय निधन पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति तथा परिजनो को इस असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

मीरजापुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बुधवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी, जमालपुर, मीरजापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार तथा डा0 मुकेश प्रसाद, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी के अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा प्रतिभाग कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया।

जिससे लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक किया गया। जिला सलाहकार, डा0 राजेश यादव द्वारा कार्यकम में प्रतिभाग किये ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं सचिव को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम एवं तम्बाकू मुक्त ग्राम के विषय में विस्तृत जानकारी दिये। जिससे लोग अपने आस पास होने वाले तम्बाकू से ग्रसित लोगो को इसका सेवन न करने की सलाह दे तथा इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बच सके, तथा तम्बाकू से ग्रसित व्यक्तियों को मण्डलीय जिला चिकित्सालय के कमरा न0 205-क्ष में तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति को आने की सुझाव दिये। जिला सलाहकार, डा0 राजेश यादव, माण्डवी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया।

इस आयोजन मे खण्ड विकास अधिकारी, मीरजापुर के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं सचिव, द्वारा कार्यकम को सफल बनाने में सम्पूर्ण योगदान रहा।

कार्यक्रम के अंत में अधीक्षक डा0 राजन, सी0एच0सी0 जमालपुर द्वारा सभी प्रतिभागियों को शपथ ग्रहण कराते हुये आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

विद्यालय में हुआ विद्यार्थी परिषद बैज अलंकरण समारोह का आयोजन

मीरजापुर। विद्यालय में विद्यार्थी परिषद बैज अलंकरण समारोह 'मानाभिषेक 2024' का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमान श्याम सुन्दर केशरी-अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मीरजापुर, विद्यालय के प्रबन्धक द्वय श्री विवेक बरनवाल, श्रीमती शिप्रा बरनवाल और प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर गणेश वन्दना व सरस्वती वन्दना के माध्यम से किया। प्रबन्धक महोदय और प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। तत्पश्चात् आये हुए अतिथियों का स्वागत बच्चों द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने अपने मुखारबिन्दु से किया। बच्चों नें प्रेरणात्मक एकांकी द्वारा कार्यक्रम को रोचक बनाते हुए तालियो से वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रधानाचार्य, हेड कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर महोदय ने कक्षा 1 ये 12 के चयनित मॉनीटर को बैज लगाकर उन्हे परिषद का सदस्य बनाया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबन्धक श्री विवेक बरनवाल जी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हे जीवन के हर पटल पर आगे आकर समाज का नेतृत्व करते हुए विद्यालय, परिवार और समाज का नाम रोशन करने की सलाह दी।

भारत-चीन संबंध

तनाव की स्थिति

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, लेकिन इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। उनका हालिया बयान भारत और चीन के बीच वर्तमान समय में जारी राजनयिक तनाव रेखांकित करता है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ था कि हमें चीन के खिलाफ काम करने के पहले दो बार सोचना चाहिए। विदेश मंत्री द्वारा वर्तमान समय में भारत-चीन संबंधों का आंकलन उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जो विभिन्न राजनयिक प्रयासों तथा उच्चस्तरीय संपर्क के बावजूद बनी हुई हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान का एक प्रमुख तत्व यह था कि उन्होंने चीन के साथ विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की 'मध्यस्थता' से साफ इनकार किया। विदेश मंत्री ने जोर दिया कि भारत चीन के साथ अपने मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हल करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रत्यक्ष प्रबंधन की दीर्घकालीन नीति का हिस्सा है। जयशंकर की टिप्पणी विदेश नीति में संप्रभुता व स्वायत्तता बनाए रखने के भारतीय दृष्टिकोण की परिचायक है। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर भारत चीन के साथ अपने मतभेद प्रत्यक्ष संवाद व बातचीत के माध्यम से हल करने के इरादे का संकेत दे रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इससे वह विदेशी प्रभाव को अस्वीकार करता है जिससे प्रक्रिया में बाधा आ सकती है तथा वह और जटिल हो सकती है।

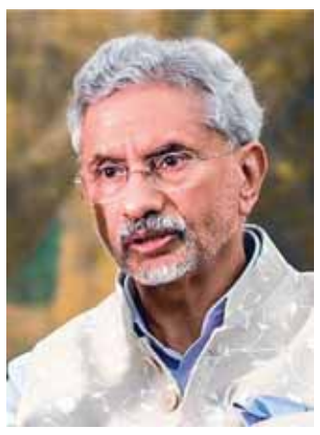

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में दिलचस्पी दिखाई, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को भारत आमंत्रित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया, पर इससे बर्फ नहीं पिघली और सीमाओं पर तनाव जारी रहा। भू-राजनीति की जटिलताओं में भारत अमेरिका के ज्यादा निकट आया है जो भारत का प्रयोग चीन का प्रभाव सीमित करने के लिए करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से चीन इससे बहुत चिंतित है। चीन की बेचैनी सीमा पर उसकी कार्रवाइयों से प्रकट होती है जो 1962 से 2017 में 'डोकलाम घटना' होने तक शांतिपूर्ण बनी रही। भारत-चीन संबंध जटिल और बहुआयामी हैं जिन पर ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक व रणनीतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा है। 1962 में अक्साईचिन क्षेत्र में सीमा विवाद के कारण भारत-चीन युद्ध हुआ था। मजेदार बात है कि सीमा विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़े हैं। चीन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। लेकिन हालिया वर्षों में सीमा पर टकराव तथा रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है। हालिया वर्षों में संबंधों में सहयोग व टकराव, दोनों शामिल रहे हैं। 2017 में हुई डोकलाम झड़प सीमा पर तनाव का प्रमुख उदाहरण है। यह टकराव डोकलाम पठार पर हुआ जो चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। 2020 में गलवान घाटी में झड़प से टकराव और बढ़ा। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारत और चीन लगातार राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए रहे। दोनों देशों ने परस्पर लाभ के दृष्टिकोण से मतभेदों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव की है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

विकसित भारत हेतु संतुलित बजट

2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को केन्द्रीय स्थान मिला है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, एसएमई को सहायता मिलेगी तथा निर्भरता घटाने के लिए खोज को गति मिलेगी।

के.एस. तोमर
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को बजट में केन्द्रीय स्थान मिला है। इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कृषि, विनिर्माण व तकनीक में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। बजट में घरेलू उत्पादन बढ़ाने, छोटे एवं मझोले उद्यमों-एसएमई की सहायता करने तथा खोज प्रोत्साहित करने पर जोर है। इन पहलों का उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना तथा जीवन्त व टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही बजट में मोदी के वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के संबंधों पर भी जोर दिया गया है। भारत की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आकर्षित करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से वैश्विक बाजार से संबंध मजबूत करने के साथ घरेलू क्षमतायें बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए महत्वपूर्ण है जिससे वह लगातार जटिल होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में चुनौतियों का सामना कर अवसरों का लाभ उठा सकेगा।

केन्द्रीय बजट देश के आर्थिक नियोजन में केन्द्रीय स्थान रखता है। इससे सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा भविष्य का दृष्टिकोण पेश करने में सहायता मिलती है। यह अगले पांच साल के लिए उल्लेखनीय सुधारों की नीव रखता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा, सामाजिक असमानताओं को संबोधित करेगा तथा भारत को वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। नवीनतम बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है और यह संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए घरेलू विकास तथा अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समाहित करता है।

2024-25 के केन्द्रीय बजट के प्रकाश में भाजपा-नीत केन्द्र सरकार को विपक्ष शासिल सरकारों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पैसा एकत्र करने व नीतिगत क्रियान्वयन में भेदभाव का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केन्द्रीय योजनाओं व पैसे के आबंटन में बजट फ्लैगशिप योजनाओं, जैसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना'-पीएमएवाई और 'आयुष्मान भारत' में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करता है। लेकिन विपक्षी राज्यों का तर्क है कि फंड में उनका आबंटन समानुपातिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं करता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने दावा किया है कि पीएमएवाई में काफी आबंटन के बावजूद पैसा जारी करने में विलंब से क्रियान्वयन में इसके प्रभावी प्रयोग में बाधा आती है।

केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया में जोर दिया गया है कि समतापूर्ण वितरण विभिन्न आयामों पर आधारित है, पर विपक्षी राज्यों का दृष्टिकोण है कि ये व्याख्यायें सतही हैं। आलोचकों का कहना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्षमता भेदभाव का प्रमाण है। विपक्ष शासित राज्यों ने विलंब के बारे में चिन्ता प्रकट की है जिससे योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं होता है। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन फंडों का प्रभावी प्रयोग हो तथा शिकायतों को संबोधित करने के लिए क्रियान्वयन पर गहरी नजर रखी जाए। राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि केन्द्रीय एजेंसियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना लगाती हैं जिनसे भेदभाव की भावना और मजबूत होती है। भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का आरोप है कि केन्द्रीय संसाधनों के प्रबंधन से सरकार इन जटिल राजनीतिक गतिशीलताओं का प्रबंधन आसानी से कर सकती है। भेदभाव के आरोपों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार को अनेक रणनीतियों का पयोग करना चाहिए जिनमें पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। उसे फंड आबंटन तथा खर्च की विस्तृत रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा असमान वितरण की शिकायतें दूर हो सकें।

सरकार को केन्द्रीय योजनाओं के सक्षम और प्रभावी क्रियान्वयन पर खासकर विपक्ष शासित राज्यों में जोर देना चाहिए ताकि समान विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो सके। केन्द्र को विपक्षी राज्य सरकारों के साथ नियमित चर्चा कर उनकी शिकायतों को दूर कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बातें सुनी गईं और उनको संबोधित किया गया। टिकाऊ वृद्धि के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। मोदी के नेतृत्व में भारत का केन्द्रीय बजट विकास के प्रति संतुलित रूपरेखा पेश करता है। इसमें घरेलू विकास तथा रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाया गया है। इसमें ढांचागत संरचना, स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है जो सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इसके साथ ही वैश्विक साझेदारी, रक्षा, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व मंच पर प्रमुख पक्ष के रूप में उभरना चाहता है। बजट का प्रमुख ध्यान समावेशी विकास पर है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। ढांचागत सुधार पर काफी आबंटन किया गया है जिसमें सड़कें, रेलवे और डिजिटल ढांचे शामिल हैं। बजट न केवल रोजगार सृजन का वादा करता है, बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती के लिए जमीनी आधार भी तैयार करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा व हरित तकनीक पर जोर इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो इसे टिकाऊ विकास की वैश्विक प्रवृत्तियों से जोड़ता है। लेकिन स्वास्थ्यरक्षा और शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर समुचित आबंटन खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी से सीखे सबकों के बाद जरूरी था। इसके साथ ही शिक्षा व खासकर डिजिटल व व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना जरूरी है। इससे युवा पीढ़ी ऐसे कौशलों से लैस होगी जो उसे भविष्य में रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगी। मानव पूंजी के विकास पर जोर देना दीर्घकालीन टिकाऊ विकास के लिए बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उसकी अनेक पहलों के विस्तार के रूप में सामने आती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का विस्तार शामिल है। यह प्रयास ग्रामीण जनसंख्या को औपचारिक अर्थव्यवस्था में समाहित करने, उनके आर्थिक अवसर बढ़ाने तथा क्षेत्रीय असमानतायें समाप्त करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं और हाशियाकृत समुदायों के प्रति लक्षित कल्याणकारी योजनाओं से सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है कि वह सामाजिक असमानताओं को संबोधित कर संसाधनों का ज्यादा समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना चाहती है।

भेदभाव वाले दृष्टिकोण का एक प्रमाण केन्द्रीय बजट में बिहार को बाढ़ समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आबंटन है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड को भी जुलाई-अगस्त, 2023 में लगभग 12,000 करोड़ व 4,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इन आंकड़ों का बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की इस आपदा में 550 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी तथा राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 650 करोड़ रुपये का आबंटन करना पड़ा। उसे केन्द्रीय वित्त मंत्री से उदार पैकेज की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने पंजाब पर भी ध्यान नहीं दिया जिसके 23 जिलों में से 21 भारी बरसात और बाढ़ से प्रभावित हुए थे और उसे 1,680 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

बिहार को विशेष व्यवहार के लिए चुना गया और वित्त मंत्री ने बाढ़ राहत के लिए उसे 11,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-संभावित राज्य है। उत्तर बिहार की 76 प्रतिशत जनसंख्या दशकों से लगातार बाढ़ का सामना कर रही है। इसलिए उसे विशेष पैकेज की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे राज्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनको ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण पूरे बजट में केन्द्रीय स्थान पर है। यह देश की आर्थिक व रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का रोडमैप पेश करता है। समग्र दृष्टिकोण, संतुलित घरेलू प्राथमिकतायें तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ही भारत निश्चित रूप से टिकाऊ व समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

निरंतरता व सहानुभूति से टीबी का उपचार

> "तपेदिक एक उपचार योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा है, इसलिए इन असमानताओं को सहानुभूति के साथ संबोधित करने वाली साझेदारियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।"

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

एक साल पहले 20 वर्षीय ताहिरा को यकीन हो गया था कि वह मरने वाली है। बुखार जो ठीक नहीं हो रहा था, लगातार खांसी, भूख न लगना और अत्यधिक कमजोरी ने उसे महीनों तक बिस्तर पर रहने पर मजबूर कर दिया था। उसका पति, जो एक रिक्शा चालक है, के पास न तो साधन थे और न ही उसे डॉक्टर के पास ले जाने का समय। जब उसका भाई कोलकाता में उससे मिलने आया और उसकी गिरती सेहत को देखा, तभी उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह ताहिरा को अपने साथ दिल्ली के सीमापुरी में उसके मायके ले आया।

यह फैसला उसकी जान बचाने के लिए था। लगभग इसी समय, एक गैर-लाभकारी संस्था, ह्यूमैना पीपल टू पीपल इंडिया, अपने प्रोजेक्ट लीड (लीवरेजिंग एजुके टिंग, एडवोके टिंग टू डिसरप्ट टीबी ट्रांसमिशन) के एक हिस्से के रूप में तपेदिक (टीबी) पर जानकारी और मार्गदर्शन दे रही थी। सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हुए, लीड ने चार शहरों, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और हैदराबाद में निम्न-श्रेणी की शहरी झुग्गियों में रहने वाले अक्सर उपेक्षित और उपेक्षित हाशिए के समुदायों, बेघर और प्रवासी आबादी पर ध्यान केंद्रित किया। दृढ़ता का फल मिलाजब लीड फील्ड ऑफिसर शांति ने ताहिरा से मुलाकात की, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले, उसे छाती का एक्स-रे कराने के लिए ले जाया गया।

जब ताहिरा में टीबी होने की संभावना दिखाई दी, तो थूक की माइक्रोस्कोपी की गई, जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया, तो कार्टिज-आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिके शन टेस्ट के माध्यम से डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आणविक परीक्षण और सरकारी जीटीबी अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध कराए गए लाइन प्रोब परख के माध्यम से दवा संवेदनशीलता परीक्षण के माध्यम से निदान की पुष्टि की गई। दवा संवेदनशीलता परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि टीबी बैक्टीरिया (बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस), जो किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, जिनसे उनका इलाज किया जाता है।

शांति को एहसास हुआ कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से नी-अक्षय, सरकार की एनटीईपी रियल-टाइम रोगी प्रबंधन वेब प्रणाली पर अपना पंजीकरण सक्षम किया, ताकि उसका कार्ड बनाया जा सके और उसका इलाज उसी दिन शुरू हो सके । एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में, शांति जानती थी कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और उपचार का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, अगले छह महीनों के लिए, शांति ताहिरा की छाया बन गई। उसने सतर्क नज़र रखी और ताहिरा को दवा के नियम से चिपके रहने या चूकने से बचाने के लिए 40 बार लगातार उसका इलाज किया। उसकी दृढ़ता का फल तब मिला जब कुछ महीने पहले ताहिरा का परीक्षण नकारात्मक आया और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। टेक्नो सीएटीटीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए जल्दी पता लगाना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब यह बीमारी तब फैलती है जब बीमारी वाले व्यक्ति हवा में बैक्टीरिया छोड़ते हैं, ज़्यादातर खांसने से। यहीं पर तकनीक एक भूमिका निभा सकती है। कफ अगेंस्ट टीबी (कैट) एक अभिनव अनुप्रयोग है जो वाधवानी एआई द्वारा विकसित फुफ्फुसीय टीबी की संभावना का आकलन करने के लिए एआई-संचालित खांसी-ध्वनि-आधारित स्क्रीनिंग टूल है, जिसके परिणामस्वरूप 10.8 प्रतिशत संभावित दर और 15.6 प्रतिशत की सकारात्मकता उपज हुई। कैट का उपयोग करने के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक स्पर्शोन्मुख मामलों का पता लगाना था, जो अन्यथा छूट जाते। जबकि प्रौद्योगिकी एक सक्षम उपकरण रही है, 600,000 से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टीबी (पीडब्ल्यूटीबी) से पीड़ित 3,182 लोगों की पहचान करने और दिल्ली में उनमें से 98त्न को उपचार के अनुपालन में सहायता करने की वास्तविक सफलता महिला फील्ड वर्करों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता और करुणा के कारण है। एक साल की परियोजना के अंत में परियोजना के निष्कर्ष बताते हैं कि महिला फील्ड अधिकारी अपनी सहानुभूति के कारण टीबी जागरूकता और स्क्रीनिंग में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई।

एक मानवीय स्पर्श कैसे एक मानवीय स्पर्श सभी अंतर ला सकता है, यह ताहिरा के मामले में देखा गया। शांति ने ताहिरा को उसके चुनौतीपूर्ण उपचार के दौरान सिर्फ़ काउंसलिंग के ज़रिए ही नहीं, बल्कि एक एनजीओ के साथ अपने संपर्कों के ज़रिए हर महीने भोजन राशन की खुराक देकर भी मदद की। इसके अलावा, उन्होंने उसे एनटीईपी की अक्षय पोषण योजना से भी जोड़ा, जो टीबी पीड़ितों को भोजन खरीदने के लिए हर महीने 500 रुपये देने की सरकारी योजना है। टीबी से ठीक हो चुकी महिलाओं को एक्टिविस्ट और फील्ड वर्कर के तौर पर तैनात करने से उन लोगों तक पहुँचने में भी मदद मिली है जो टीबी से पीड़ित हैं। वे जानती हैं कि टीबी के साथ जीने का क्या मतलब है और उन्हें किस तरह के सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के उनके दृढ़ संकल्प ने शुरुआती पहचान और उपचार को बढ़ावा दिया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सबसे ज़्यादा जोखिम में वे लोग हैं जो खराब हवादार और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं, कुपोषण और बीमारियों से पीड़ित हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी सीमित पहुंच है। प्रोजेक्ट लीड ने दिखाया है कि महिला फील्ड ऑफिसर अपनी समझ और संवेदनशीलता की वजह से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े लोगों को टीबी की जांच और उपचार के लिए राजी करने में ज़्यादा सफल होती हैं। टीबी शोधकर्ता डॉ. अनुराग भार्गव, डॉ. मधुकर पई और डॉ. माधवी भार्गव ने दोहराया कि टीबी एक इलाज योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन असमानताओं को पाटने के लिए अधिक साझेदारी में निवेश करना और भी जरूरी है।

आप की बात

मनु की दुहरी सफलता

पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 12 साल बाद निशानेबाजी स्पर्धा में दो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और हम भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। खेलों में मनु भाकर की सफलता ने सिद्ध किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। उन्होंने अपने हौसलों से हर मुश्किल काम को आसान किया है और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। ओलंपिक में एक बार फिर मनु ने हमें गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। ओलंपिक के 124 सालों के सफर में भारत ने अब तक 35 पदक ही हासिल किए हैं और इनमें मात्र 10 स्वर्ण पदक है। 10 में से 8 स्वर्ण पदक तो पुरुष हॉकी में जीते हैं और दो स्वर्ण पदक भाला फेंक और निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम है जिसमें भारत पदक जीतने से अब तक वंचित रहा है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक सात पदक जीते थे। अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत पदक तालिका में दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद करनी चाहिए कि भारत पेरिस ओलम्पिक में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर न केवल खेलों की दुनिया में अपना जलवा दिखाएगा, बल्कि वर्ष 2036 में ओलम्पिक मेजबानी के लिए भी तैयार होगा।

– **नलिन खोईवाल,** इंदौर

मीडिया की जिम्मेदारी

दिल्ली से छपने वाले अखबारों में शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि किसी कोचिंग संस्थान का पूरे पेज का विज्ञापन न छपा हो। विडंबना है कि जैसे ही ये कोचिंग संस्थान विज्ञापनदाता हो जाते हैं, मीडिया का ध्यान इस बात से हट जाता है कि इनके भीतर कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। शायद बड़े विज्ञापन देने के कारण ये कोचिंग संस्थान मीडिया की जांच का विषय नहीं रह जाते। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम वीडियो बनाकर मीडिया संस्थान का नाम लेकर लिख रहे हैं कि वे इंटरव्यू शूट करने और दिखाने के लाखों रूपये लेते हैं। ऐसे में यदि किसी कोचिंग संस्थान के मालिक ने पैसे दे कर मीडिया के किसी हिस्से को इंटरव्यू दिया तो उसके लिए भी कोचिंग संस्थान कोई ख़बर का विषय नहीं है। मीडिया को भारी-भरकम विज्ञापन देकर प्रभावित किया जा सकता है। मीडिया में विज्ञापनों और खबरों के बीच द्वंद्व तो महात्मा गांधी के समय से ही शुरू हो गया था, जब मीडिया अपने उदीयमान समय में था। आज स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हो गई है। लेकिन तमाम वित्तीय दबावों के बावजूद मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह देश और समाज की विसंगतियां उजागर करता रहेगा।

–**भूपेंद्र सिंह,** दिल्ली

ट्रेन दुर्घटना

हावड़ा से मुंबई जा रही मेल एक्सप्रेस झारखण्ड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 20 बोगियां बेपटरी हो गई जिससे 2 यात्रियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल भी हो गए। हालांकि, रेलवे ने मृतक आश्रितों, गंभीर घायलों और मामूली घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक के बाद एक दुखद रेल दुर्घटनायें कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही दर्शाती हैं। यह जांच का विषय है कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। लेकिन इनसे रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हालांकि रेलवे वर्तमान समय में नई-नई ट्रेनें चला रही है और अनेक विकास कार्य भी रेलवे में चल रहे हैं। लेकिन तकनीकी या गैर तकनीकी कर्मचारियों की कमी भी दूर करना जरूरी है ताकि परिचालन में असुविधा व अड़चनें न उत्पन्न होने पायें। रेलवे ने तकनीकी उन्नयन से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, पर यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में तकनीक पर अति-निर्भरता हानिकारक हो सकती है। समय की मांग है कि रेलवे में सभी खाली पदों पर उपयुक्त कर्मचारियों की यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र भर्ती की जाए।

–**महेश नेनावा,** इंदौर

कर्नाटक का निर्णय

भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस की धारा 281 के तहत वाहनों की गति 120 किलोमीटर से अधिक होने पर खतरनाक ड्राइविंग मानी जाती है। इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ एक अगस्त से एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उचित और स्वागत योग्य है। यह निर्णय इसलिए भी उचित है क्योंकि इससे अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है और दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। आजकल बाइक भी ऐसी आ रही है जो पल भर में 160 की स्पीड पकड़ लेती है जो जानलेवा सिद्ध हो सकती है। कर्नाटक सरकार का यह निर्णय प्रशंसनीय है। दूसरे राज्यों को भी इस निर्णय का अनुकरण कर इसे अपने प्रदेशों में इसे लागू करना चाहिए। दोपहिया या चौपहिया वाहन चालकों को स्पीड का आनन्द उठाने का अवसर देने के लिए राज्य सरकारों को बाइक व कार रेसिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करने पर विचार करना चाहिए। वाहनों की गति पर लगाम निरपराध राहगीरों के लिए भी जरूरी है।

– **भगवानदास छारिया,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुरस्त रखें सभी व्यवस्थाएं: मंडलायुक्त

संवाददाता। गोंडा

देवीपाटन मण्डल की सभी नगर निकायों समस्याओं पर बुधवार को मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मण्डल के सभी अधिशासी अधिकारियों संग बैठक किया। जिसमें उन्होंने नगर निकायों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी जोन में तालाबों, पार्कों, सीवर, नालों, सड़कों, गलियों आदि की साफसफाई के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने सख्ती बरतते हुए कहा कि नगर निकायों के समस्त वार्डों में प्रत्येक दिन पर्याप्त साफ-सफाई व कूड़ा उठान की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित रहे। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाली प्लाटों, कूड़ाघरों एवं आसपास, तालाबों, स्कूलों, धर्म स्थलों, मठ-मंदिर आदि के आसपास जमा कूड़ों की विशेष सफाई अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि बरसात के बाद रुके हुये कार्य को प्रारंभ करने, राज्य वित्त आयोग में आए बजट से प्रस्ताव पास कर काम शुरू करने, गौ आश्रय स्थलों में साफ-सफाई, पेयजल, हरा चारा व भूसा की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

बैठक में आयुक्त ने कांवड़ यात्रा में चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था करने, आगामी कजरीतीज त्यौहार को लेकर समुचित तैयारी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कई अधिशासी अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी तलब किया। मंडलायुक्त में सभी ईओ को निर्देश दिए कि सावन में विभिन्न जगहों पर मेले आदि का आयोजन होता है। ऐसे सभी मेला स्थलों पर नियमित रूप से साफसफाई की जाए। वहां पर पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने दुखहरण नाथ मंदिर, स्वामी नारायण छपिया मंदिर सहित अन्य शिव मंदिर परिसर की नियमित साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

सैनिक बंधुओ की समस्याओं के निवारण के एडीएम ने दिये निर्देश

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। बैठक में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल बी0के0 शुक्ला द्वारा सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी एवं उपस्थित अधिकारी/पूर्व सैनिक का स्वागत किया तत्पश्चात् पिछली सैनिक बन्धु की बैठक को दोहराते हुए जिसमें पूर्व प्रार्थना पत्र, जमीनी विवाद, शस्त्र लाइसेन्स एवं केन्द्रिय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया गया कि आप लोगों के किसी भी प्रकार की समस्या एवं वेलफेयर से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल, उप प्रबन्धक जिला लीड बैंक अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला, सहायक अभियन्ता यूपीसिडको, प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी आदि मौजूद रहे।

ग्राम पंचायत अधिकारियों की मनमानी के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता। रायबरेली

रायबरेली में सरकारी राशन दुकान कोटा के चयन प्रक्रिया में महिला प्रत्याशी के साथ अधिकारियों द्वारा की गई मनमानी व धांधली को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए प्रदर्शन किया और ग्राम पंचायत अधिकारी मनमानी तरीके से चयन किए गए कोट को निरस्त कराए जाने की मांग की गई।

आपको बता दे कि बुधवार को समय रायबरेली जनपद के तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले सतांव ब्लॉक के ग्राम बरउवा गांव में सरकारी राशन की दुकान की चयन प्रक्रिया चल रही थी। जिसमें महिला प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी पत्नी दुर्गेश कुमार ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि साथ मीटिंग ग्राम पंचायत भवन में कराई गई और आखिरी मीटिंग ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के बाहर जूनियर हाई स्कूल में किया गया जो गलत है। वहीं आज मनमानी तरीके से कोट का चयन कर दिया गया जिसको लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने मतों के रिकाउंटिंग कराए जाने की मांग भी की लेकिन मौजूद खंड विकास अधिकारी व तहसीलदार ने महिला प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी की एक न सुनी जिसको लेकर प्रत्याशी के साथ ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है और दोबारा से मतदान कर कर निष्पक्ष तरीके से चयन किए जाने की मांग की गई है इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।

दामिनी व सचेत ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली से करें बचाव

अमेठी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अर्पित गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी आगामी दिनों के लिए भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की संभावित चेतावनी को देखते हुए सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनमानस से विभिन्न उपाय को अपनाने की सलाह दी गयी है। उन्होंने बताया कि सभी नागरिक अपने मोबाइल में दामिनी/सचेत ऐप डाउनलोड करने कर लें, इसका प्रयोग घर से बाहर निकलने या कहीं खुले स्थानों में जाने से पहले आकाशीय बिजली अथवा वर्षा होने की चेतावनी प्राप्त करने में किया जाता हैं, दामिनी ऐप के माध्यम से 30 मिनट पूर्व आपके क्षेत्र में बिजली गिरने की संभावना को दर्शाया जाता है व सचेत ऐप के द्वारा अपने क्षेत्र में वर्षा का पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दामिनी ऐप का उपयोग करके अपनी जान की रक्षा करने के साथ ही जागरुकता के द्वारा और लोगों की भी जान बचा सकते हैं, इसके अतिरिक्त आकाशीय बिजली गिरने के पूर्व शरीर के गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं जो कि आकाशीय बिजली गिरने का सूचक है तथा इसके अलावा इस समय धातु के सामानों का इस्तेमाल ना करें जो कि विद्युत के सुचालक है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि पानी से भरे हुए क्षेत्र तालाब, खेत आदि से दूर रहें, नल का इस्तेमाल ना करें, बिजली के खंभों से दूर रहे, यदि कहीं यात्रा कर रहे हो और तो उस अवस्था में कोई पक्का सुरक्षित स्थान न मिलने की दशा में जमीन पर दोनों एडी जोड़कर और हाथ को कान से दबाकर बैठ जाएं, जिससे आकाशीय बिजली से बचा जा सके एवं पेड़ के नीचे कतई न खड़े हो क्योंकि आकाशीय बिजली सर्वप्रथम ऊंचे बिल्डिंग एवं पेडों पर गिरती है तथा पक्का मकान सुरक्षित स्थान नियम का हमेशा पालन करने का प्रयास करें।

कॉलेज में टैबलेट पाकर बच्चों के खिले चेहरे

अमेठी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण मिशन के तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत श्री निषाद राज अखंडानंद पी जी कालेज किटियावा में टैबलेट का वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। टैबलेट का वितरण कॉलेज प्रबंधक शिव प्रसाद कश्यप की देखरेख में किया गया। छात्र छात्राओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु निःशुल्क टैबलेट वितरण किया गया। कॉलेज में एम ए उत्तीर्ण समस्त छात्र- छात्राओं को टेबलेट वितरण हुआ, कॉलेज के 53 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया, प्रदेश सरकार द्वारा नई तकनीक विकसित करने के लिए 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, तकनीकी सशक्तिकरण के अंतर्गत टैबलेट वितरित हुए

हाईकोर्ट ने पक्ष सुनकर अभियुक्त को दी जमानत

संतकबीरनगर। जनपद के ग्राम सियरा साथा के बालेंद्र कुमार ने अपनी अव्यस्क पुत्री की गुमसुदुगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद मे गत 08, मई, 2024 को दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना के पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376 एवं धारा 5 एवं 6 पास्को की बढोत्तरी की गयी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी कि गई अभियुक्त आकाश पाल का पक्ष अधिवक्ता प्रिंस श्रीवास्तव ने रखा। श्री श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष अपनी बहस मे कहा की पीड़ित ने अपने बयान मे कहा था की वो अभियुक्त से प्रेम करती है और उसी के साथ रहना चाहती है और अपनी सहमति से आकाश के साथ गयी थी। जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता ने किया न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत अभियुक्त आकाश पाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया अभियुक्त आकाश पाल गत 28 मई 2024 से जेल में बंद है।

डीएम-एसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र तंवर व पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारीद्वय द्वारा निरीक्षण के दौरान हास्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई, तत्पश्चात कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं/सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये, समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन पूर्ण/सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार संघ ने की बैठक

गौरीगंज, अमेठी। मंगलवार को पूर्व एजेण्डा के अनुसार प्रांतीय खंड लोनिवि कार्यालय प्रांगण में ठेकेदार संघ वैठक आहुत की गयी उक्त बैठक में निम्न विन्दुओं को समस्या के रूप में उठाया गया। बैठक में ठेकेदार के देयक का भुगतान समय से न किया जाना। ठेकेदार का किए गये कार्य के विरुद्ध समय से धन की मांग न किया जाना, ठेकेदार के पूर्व में किए गये कार्य के देयक से कराई गयी डिपाजिट को घाशि का भुगतान नहीं दिया जाना । ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण कर दिए जाने के उपरांत भी विभागीय कार्य पद्धति के कारण लगभग प्रत्येक अनुबंध में समय वृद्धि लेनी पड़ रही है जिससे अनावश्यक समय धन का अपव्यय हो रहा है। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अनावश्यक पत्राचार करके ठेकेदार के ऊपर मानसिक दबाव बनाना। उपरोक्त बिन्दुओं पर ठेकेदार द्वारा तय किया गया कि उक्त समस्या का समाधान अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कराया जाए अन्यथा की दशा में ठेकेदार आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे।

क्विक न्यूज

वकीलों ने ग्रामीणों संग महराजगंज उपकेंद्र का किया घेराव

महराजगंज, रायबरेली। लगातार हो रही विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से आजिज होकर अधिवक्ताओं तथा ग्रामीणों ने आज बुधवार को महराजगंज उपकेंद्र का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की एक्सईएन द्वारा समस्या का निराकरण एक हफ्ते के अंदर किए जाने के आश्वासन पर सभी शांत हुए। आज बुधवार की शाम चार बजे के करीब बिजली कटौती से परेशान होकर अधिवक्ता रणविजय सिंह, दीपू अवस्थी, शैलेन्द्र सिंह रणविजय सिंह उर्फ भोले, व राहुल मिश्रा चंदन पांडे अरविंद शुक्ला मुकेश सिंह आशीष सिंह अमरेंद कुमार दुर्गेश सिंह आयुष सिंह आदित्य सत्यम राघवेंद्र संतोष कमलेश सहित करीब दो दर्जन से अधिक लोगों ने महराजगंज उपकेंद्र का घेराव करते हुए नारेबाजी की तथा एक ज्ञापन एक्सईएन ओपी सिंह को सौंपा जिसमें कहा कि विभाग द्वारा लगातार अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे आम जनमानस त्रस्त हो चुका है, सभी ने मांग की कि यदि जल्द समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक्सईएन ओपी सिंह ने एक हफ्ते के अंदर हर हाल में समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया जिस पर सभी शांत हुए।

कांग्रेसियों ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका

लालगंज, रायबरेली। सांसद राहुल गांधी पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी चौराहा पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंककर नाराजगी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कामता प्रसाद गौड़ की अगुवाई में कार्यकर्ता गांधी चौराहा पर इकट्ठे हुए। भाजपा सांसद की अभद्र टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ताओं में मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग की। सरेनी ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। देश की जनता भी जातिवाद जनगणना कराना चाहती है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से संसद की मर्यादा भंग की गई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

संवाददाता। श्रावस्ती, भिनगा

जनपद के परिषदीय विद्यालयों को प्रत्येक प्रकार से सुव्यवस्थित किये जाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर विद्यालयों को व्यवस्थित किया जाना है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत यद्यपि जनपद की स्थिति ठीक है किन्तु प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग शौंचालय एवं फर्नीचर की जरूरत पूरी हो जाने पर विद्यालयों की स्थिति और भी अच्छी होगी तथा जनपद श्रावस्ती प्रदेश में प्रथम पायदान पर होगा। उक्त बातें जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि जनपद के 162 विद्यलयों मे किचन गार्डन की राशि भेजी गयी और इसके सदुपयोग के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं रूचि लेकर किचन गार्डन का निर्माण सुनिश्चित कराएं जिससे बच्चों को मध्यान्ह भोजन में ताजी सब्जियां आदि प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राय: विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि इस भीषण गर्मी में भी कुछ विद्यालयों में पंखे संचालित नहीं पाये गये जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वयं यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यालय में पंखा खराब स्थिति में न हो। निपुण भारत योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सिरसिया में ए0आर0पी0 के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है जो अक्षम्य है इस पर जिलाधिकारी ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी कि अगस्त माह में निर्धारित समय में विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। डायटमेन्टर के द्वारा भी अपने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया है, जिस हेतु डायट प्राचार्य के द्वारा समस्त मेन्टर को कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का अनुश्रवण कराये जाए का निर्देश दिया।

निर्देशित किया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बच्चों तथा अध्यापिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाये तथा खान एकेडमी की कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित करायी जायें। उन्होंने बीएसए को यह निर्देशित किया कि ऐसे अध्यापक जो विद्यालय में अनुपस्थित पाये जाते हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सम्पादित करें जिससे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों को लर्निंग आउटकम संतोष जनक हो सके।

डीएम ने की उद्योग बंधु समिति बैठक की अध्यक्षता

अयोध्या। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। उन्होंने विगत सम्पन्न समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी। इसके साथ ही जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र अयोध्या के तत्वावधान में संचालित निवेश मित्र पोर्टल की प्रगति पर तथा ओडीओपी, एमवाईएसवाई व पीएमईजीपी योजना पर जानकारी करते हुये निवेश मित्र पोर्टल पर अधिक से अधिक उद्यमिओं को जोड़ने तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला स्तरीय उद्योग समिति की बैठक में उद्योग बन्धुओं द्वारा लालबाग, फतेहगंज, पुलिस लाइन आदि उद्योग क्षेत्रों में जलभराव व खराब सड़कों की समस्या से अवगत कराया है जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र जलनिकासी व जलभराव की समस्या के निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास पुलिस ने किया विफल

उरई, जालौन। बुधवार को गांधी चबूतरा पर कोतवाली के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आवाहन पर शहर कांग्रेस कमेटी उरई एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों के तत्वाधान भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर सांसद द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) के विरुद्ध अशब्द (अभद्र टिप्पणी) कहे जाने को लेकर आज गांधी चबूतरा पर विरोध प्रदर्शन करते हुये केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंकने का असफल प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी कांग्रेसियों के हाथों से पुतला छीन ले गये इसके बाद कांग्रेस नेता सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा हमारे नेता राहुल गांधी अभद्र टिप्पणी करने वाले का यही अंजाम होगा हमारे देश की संसद मैं किसी की जाति पूंछकर देश के 80 परसेंट आबादी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासियों का अपमान देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाना दुर्भाग्य की बात देश इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा

14 सितंबर को आयोजित हो रही लोक अदालत में मामले नियत करायें

उरई, जालौन। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला जज राजीव सरन ने बताया कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर शनिवार को प्रात: 10 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव के दिशा-निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों, मुकदमा, श्रम वाद, विद्युत एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दण्ड वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत चौक बाउन्स के मामले नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।

प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल, टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

यातायात संबंधी चालानों को वेबसाइट के द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं। समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि लम्बित दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों, मुकदमों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक व्यक्ति, संबंधित पक्ष समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

सदन में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़के कांग्रेसजन

संवाददाता। जालौन, उरई

पूर्व केन्द्रीय मंत्री भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए प्रयोग किये शब्दों को लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है। कांग्रेसियों ने आज कोंच चौराहे पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन करने का प्रयास करते हुए अपना विरोध जताया। पुलिस ने कांग्रेसियों से पुतला छीन कर पुतला दहन नहीं करने दिया।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस मामले में अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों में खासी नाराजगी है। पार्टी के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष कमालद्दीन व जिला उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर के बयान की निंदा की गयी तथा उनके खिलाफनारेबाजी करते हुए मांफी की मांग करते हुए कोंच चौराहे पर पुतला जलाने का प्रयास किया।

पुलिस ने कांग्रेसियों के हाथ से पुतला छीन लिया तथा पुतला दहन नहीं होने दिया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष कमालद्दीन ने कहा कि संसद में किसी सांसद द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे संसद व हमारे देश की गरिमा प्रभावित हो। हमारे देश में अमन चौन आपसी भाई चारा बना रहे। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए।

कालपी में कांग्रेस नेताओं को कार्यालय में किया नजरबंद

कालपी, जालौन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद में अपशब्द कहे जाने व जातिसूचक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकना व विरोध प्रदर्शन करना सुनिश्चित हुआ था। पुतला फूंकने की भनक जैसे ही स्थानीय प्रशासन को हुई तो पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कालपी कांग्रेस कार्यलय में दस्तक दी। तथा विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर लिया।

बीडीओ ने बैठक में सचिवों व तकनीकी सहायकों को दिये दिशा निर्देश

कोंच, जालौन। खंड विकास कार्यालय में बैठक लेते हुए खंड विकास अधिकारी मानूलाल यादव ने ग्राम पंचायतों में गौशालाओं व्यवस्था,व आवास की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाँव में अन्ना जानवरों को गौशाला में भेजे जाने की व्यवस्था की जाये और गौशाला के अंदर भूसा चारा पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे। सरकारी आवासो के लिए उन्होंने कहा कि पात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाया जाये और आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाये। वृक्षारोपण को लेकर खंड विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीणों को पेड़ पौधे लगाने के प्रति प्रेरित करें। इसके अलावा अन्य छोटे बड़े विकास कार्यों की भी बैठक में समीक्षा की गयी। इस दौरान एडीओ पंचायत नरेश दुवे, एडीओ आईएसबी देवेंद्र निरंजन, एपीओ लोकेंद्र यादव, एडीओ एजी हरीश निरंजन, सचिव हेमन्त कुमार, हर्षित गुप्ता, पवन तिवारी, नरेंद्र पटेल, सूरजभान, अनुज गुप्ता, बसीम खान, पूनम राजपूत, शिल्पी राजपूत, कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रशान्त श्रीवास्तव, विपिन शाह आदि उपस्थित रहे।

सर्पदंश से किसान की मौत पर पत्नी को डीएम ने दी 3 लाख की चेक

जालौन, उरई। सर्पदंश से हुई किसान की मृत्यु पर कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत किसान की पत्नी को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता की चेक डीएम ने सौंपी है। तहसील क्षेत्र के ग्राम मडोरा निवासी किसान विजय सिंह 25 मई 2024 को अपने खेत पर गए थे। खेत पर काम करने के दौरान अचानक उनको सांप ने काट लिया था। परिजन जब तक किसान को सीएचसी लेकर पहुंचे तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मृतक की पत्नी कृषक दुर्घटना सहायता योजना गीता देवी ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था। जिसकी स्वीकृति के बाद कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना के तहत मृतक की पत्नी गीता देवी को जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने मंडी सचिव वीरेन्द्र कुमार की उपस्तिथि में तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता की चेक सौंपी। चेक पाकर गीता देवी ने डीएम को धन्यवाद दिया।

दरवाजा तोड़कर चोर ले गये नकदी व लाखों के जेवरात

जालौन, उरई। क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ग्राम पहाड़पुरा में चोर दरवाजे को तोड़ कर घर में घुस गये हैं तथा बक्से में रखे हजार रुपए नकद व सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गये हैं। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुरा निवासी रसीद पुत्र लतीफने बताया कि मंगलवार की रात वह घर पर अकेला था। माता-पिता कानपुर गये थे। रात करीब 1 बजे अज्ञात चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़ कर घर में घुस गये । चोरों ने घर में घुसकर रखे बक्से को उठा ले गये पड़ोस में खाली पड़े मकान में जाकर उसमें रखे 20 हजार नकद रूपए, सोने की मंचली लगभग 40 हजार कीमत, चांदी की 2 सेट तोड़िया, 2 बिछिया व अनजान में रखे आभूषण चुरा ले गये हैं। जब सुबह उसकी नींद खुली तो बक्सा गायब था तथा दरवाजा खुला दिखा। घर में चोरी की घटना की सूचना पीड़ित ने माता-पिता व पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की। जांच के दौरान घर से गायब बक्शा पड़ोस में खाली पड़े मकान में मिल गया है।

पालिका टीम ने घूमते गौवंशों को पकड़ कराया संरक्षित

जालौन, उरई। नगर पालिका द्वारा नगर की सड़कों पर विचरण कर रहे अन्ना जानवरों को पकड़ने का कार्य किया गया शुरु। एस आई देवेंद्र सिंह ने बनाई टीमें जो नगर की सड़कों पर अन्ना जानवरों को संरक्षित करेंगे। बुधवार को आधा सैकड़ा अन्ना जानवर पकड़कर गौशाला में कराये संरक्षित। नगर पालिका द्वारा अन्ना जानवरों के वितरण पर चलाया जा रहा है। बुधवार को एस आई देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम चलाई गयी। उक्त टीमों द्वारा तकरीबन आधा सैकड़ा जानवरों को पकड़ा गया जिन्हें गौशाला में संरक्षित कराया। नगर पालिका द्वारा मुनादी कराई गई थी कि नगर की सड़कों पर अन्ना जानवर पशुपालक ना छोड़े उनके जानवरों को पकड़ गौशाला में संरक्षित करा उनके खिलाफकड़ी कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी-एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

लखीमपुर खीरी। कारागार प्रशासन द्वारा बन्दियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओंए कारागार की साफसफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी गणेश प्रसाद साहा ने संयुक्त रुप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की।

डीएम.एसपी ने बंदी ग्रह में जाकर बंदियों का हालचाल जाना एवं खाने.पीने के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जेल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैरिकों में जाकर बंदियों से मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कारागार में साफसफाई व्यवस्था मिलने पर संतोष व्यक्त किया। निर्देश दिए कि इसी प्रकार प्रतिदिन जेल में साफसफाई बनाए रखी जाए।

डीएम.एसपी ने सभी बैरकों व बंदियों का गहन निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों में किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। जेल अधीक्षक की ओर से बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ की ओर से जेल की चेकिंग की जाती है। डीएम.एसपी ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहें। संवेदनशील बंदियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। समय.समय पर कारागार मे निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते रहें। कारागार अधीक्षक पीडी सलोनियाए जेलर हरिवंश कुमार पांडेय, डिप्टी जेलर धीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर, भोजराज सिंह, चिकित्सक डॉ शिवपूजन मौजूद रहे।

डीएम ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय का किया निरीक्षण, सफ सफाई के दिए निर्देश

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय अंतर्गत विभिन्न पटलों से संबंधित कार्यों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्थाए पत्रावलियों के रख.रखाव दुरुस्त रखने के निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान पटलों पर कार्य कर रहे अधिकारियोंए कर्मचारियों को निर्देशित किया की शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कार्य समय अंतर्गत पूर्ण किए जाएं। उन्होंने परियोजना निदेशक को पुरानी निष्प्रयोग वस्तुओं की नीलामी करने हेतु निर्देशित किया। इस मौके पर परियोजना निदेशक वीरेंद्र कुमार व कार्यालय संबंधित स्टाफ आदि उपस्थित रहे।

जनपद के दिव्यांग छात्र-छात्राएं निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति हेतु करें आनलाइन आवेदन

कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयए भारत सरकारए नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्रध्छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति संचालित है जिसका मुख्य उददेश्य आर्थिक रूप से पिछडे दिव्यांग छात्रध्छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तीकरण है। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांग छात्रध्छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना प्री.मैट्रिक छात्रवृत्तिए आरंभ करने की तिथि 30.06.2024 अंतिम तिथि 31.08.2024 है, इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति व उच्च श्रेणी शिक्षा 30.06.2024 से 31.10.2024 है। जनपद के दिव्यांग छात्रध्छात्राएं निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सीडीओ के अध्यक्षता में हुई जनपदीय खरीफ गोष्ठी, किसानों को दी लाभकारी जानकारी

● **वैज्ञानिकों को सुझाए बेहतर खेती के गुर, साझा की जानकारी**

लखीमपुर खीरी। बुधवार को कलेक्ट्रेट में सीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खरीफ गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को लाभकारी खेती करने के लिए उपयोगी जानकारी दी। गोष्ठी में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख बेहजम/नकहा/मोहम्मदी तथा जिला पंचायत सदस्य ने प्रतिभाग किया।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शासन. प्रशासन करते संकल्पित होकर काम कर रहा। इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानपरक योजनाओं के जरिए उन्हें समृद्ध बनाने के लिए नित नए कदम उठा रही है। उन्होंने जिले में स्थापित हाईटेक नर्सरी के उपयोग करने का अनुरोध कियाए जहां से किसान भाई अपनी सब्जी की खेती के लिए पौध कम कीमत पर तैयार करवा सकते हैं। साथ ही कृषक उत्पादक संगठनों से निर्यात की दृष्टि से उपयोगी औद्यानिक फसलों के उत्पादन का संस्करण पैकेजिंग आदि करके किसानों की आय बढ़ाने पर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीडीओ ने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि गोष्ठी में प्राप्त जानकारी को न केवल स्वयं अपनाएंगे व आसपास के अपने जानने वाले किसानों तक भी तकनीक को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उपस्थित किसानों को अन्न जैसे सावांए कोदो तथा रागी के मिनी किट भी वितरित किये गये। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का संचालन डीडी कृषि ने किया। कृषि वैज्ञानिक डॉ पीके बिसेन ने खरीफ की फसलों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। किसानों को फसल बीमाए प्राकृतिक खेती तथा आईपीएम ;समनवित नाशी जीव प्रबन्धनद्ध विधि से कीड़े, बीमारियों की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

चरित्र के शक में पति ने अपनी पत्नी का सिर काटकर पैदल थाने पहुंचा

बांदा। बांदा में सन 2000 में चरित्र के शक में पति ने अपनी पत्नी का सिर काटकर अपने हाथ में लेकर दिनदहाड़े बीच बाजार से पैदल चलते हुए ठाणे पहुंचा था इस पर पूरा बबेरू तहसील के लोग विचलित हो गए थे उसे आज बांदा सत्र न्यायालय के जिला जज ने फांसी की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार उर्फ मुन्नू परिहार व एडीजीसी उमाशंकर पाल ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को बबेरू थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार कस्बे के नेता नगर निवासी किन्नर यादव पुत्र दयाराम ने अपनी पत्नी विमला की फरसे से वार करते न सिर्फ हत्या कर दीए बल्कि उसकी कटी हुई गर्दन को हाथ में लेकर पैदल ही थाने पहुंच गया था।

मृतका के पिता रामशरण यादव निवासी अमलोहरा बिसंडा की तहरीर के आधार पर दामाद उसकी पुत्री पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था और इसी वजह से उसने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। बताते है कि हत्यारोपी किन्नर ने पड़ोसी युवक रविकांत शर्मा को भी खुरपे से वार करके घायल कर दिया था।

तत्कालीन थानाध्यक्ष जयश्याम शुक्ला ने मृतका के पिता की तहरीर पर धारा 302 व 324 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की गहन विवेचना की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय बहादुर सिंह परिहार और अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल की प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को जघन्य मानते हुए मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया। अदालत में अभियोजन की ओर से कुल दस गावाह पेश किए गए, वहीं आरोपी की तरफ से स्वयं समेत तीन गवाह प्रस्तुत हुए। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी किन्नर यादव को दोषी करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।

भारी पुलिस बल के बीच जेसीबी द्वारा तोड़ा गया अतिक्रमण, हुई कहासुनी

संवाददाता। बिंदकी (फतेहपुर)

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा गया अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कई बार कहा-सुनी भी हुई। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी तथा राजस्व विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार को नगर के ललौली रोड मोहल्ला स्थित मैनी कुआं के समीप भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को तोड़ा गया। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजस्व टीम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कई बार कहा सुनी और नोक झोंक हुई। बताते चलें कि एक सप्ताह पहले इसी स्थान पर अतिक्रमण हटाया गया था, बाकी अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। बुधवार को एक बार फिर अतिक्रमण को तोड़ने का काम किया गया।

इस मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता अरुण कुमार सक्सेना, सहायक अभियंता संतोष कुमार कनौजिया, अवध अभियंता अजीत सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, राजस्व निरीक्षक रघुराज सिंह, लेखपाल भान सिंह, लेखपाल अजीत उमराव, लेखपाल वीरेंद्र श्रीवास्तव तथा पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, कस्बा इंचार्ज नीरज कुशवाहा मौजूद रहे।

कार्यवाही: डीएम ने तीन भण्डारणकताओं पर ठोका 34 लाख का जुर्माना

लखीमपुर खीरी। जनपद खीरी में अवैध खनन, परिवहन पर अंकुश लगानेए प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के मार्गदर्शन में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने तीन भण्डारणकताओं पर 34 लाख का जुर्माना लगाया और कूटरचित मउउ11 मामले में पटटाधारक पर एफआईआर के निर्देश दिए। माह जुलाई 2024 में तहसील धौरहरा के शारदानगर और तहसील पलिया के भण्डारणकर्ताओं द्वारा स्वीकृत मानक के सापेक्ष अधिक मात्रा में साधारण बालू का भण्डारण पाया गया तथा सेठघाट रोड पर स्थित एक अवैध डम्प साण्बालू का पाया गया। उक्त तीनों भण्डारणकताओं से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर लगभग 34ण्00 लाख रूपये का अर्थदंड आरोपित किया गया और कूटरचित मउउ11 जारी किये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पटटा धारक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए।

क्विक न्यूज

डंपरो की आमने सामने भिंडत से चालक की मृत्यु दो जख्मी

मौदहा (हमीरपुर)। बीती रात छिरका गांव के पास दो डंपरों में हुई आमने.सामने भिड़ंत में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वाहनों का आवागमन ठप हो गया। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त डंपरों को राजमार्ग से हटवा घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मंगलवार की देर रात रामचरण पुत्र गोपाल निवासी जहानाबाद जनपद फतेहपुर अपने खलासी साथी रामचंद्र के साथ के साथ डंपर में गिट्टी लाद हमीरपुर की ओर आ रहा था तभी बिपरीत दिशा से आ रहे दूसरे डंपर की भिंडत हो गयी इस डंपर का चालक नईम (26) पुत्र सलीम निवासी घाटमपुर बताया कजाता है। डंपरो के टकराने से उनका मलवा सड़क में फैल गया जिससे जाम लगने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर जाकर चालक रामचरण व रामचंद्र को निकाल लहू लुहान हालत में सरकारी अस्पताल मौदहा में भर्ती कराया जबकि दूसरे डंपर के चालक नईम की मौके परही मौत हो गयी। इस राजमार्ग में डिवाइडर न होने के चलते आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में लोग असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिये भेज दिया है।

हत्या में वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

कानपुर देहात। अपराधियो व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 29ण07ण2024 को वादी द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0स0 192ध्2024 धारा 103;1द्धध्61;2द्ध;3द्ध भारतीय न्याय संहिता;बी0एन0एस0द्ध व धारा 3;2द्धट एससीध्एसटी एक्ट बनाम 04 नफर नामजद अभियुक्तगण शिवम उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र रामबहादुर पाल निवासी ग्राम जरिहा थाना मंगलपुरएविष्णु दयाल संखवार पुत्र स्व0 शंभू दयाल संखवार निवासी ग्राम फरीदपुर निटर्राएगुलाब संखवार उर्फ अमरजीत पुत्र रामऔतार संखवार निवासी ग्राम मनकापुर थाना मंगलपुरए पूजा देवी पत्नी स्व0 गुरूचरन निवासिनी ग्राम मनकापुर थाना मंगलपुर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 04 वांछित अभियुक्तगण को रेलवे स्टेशन झींझक रोड़ तिराहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

यमुना में डूबे युवक का मवईधाम के पास शव बरामद

फतेहपुर। कानपुर नगर के थाना सजेती गांव बहरौली निवासी अवधेश सचान का पुत्र कपिल सचान अपने कुछ साथियों के साथ मंगलवार की दोपहर यमुना में नहाने गया था। तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया। तेज बहाव के कारण वह बहता हुआ निकल गया। वहीं साथ में आए दोस्तों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। जिस पर मौके पर पुलिस व गोताखोरों ने उसे ढूढ़ने का प्रयास किया। देर रात चांदपुर थाने के मवई धाम के पास से गोताखोरों ने शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया। परिजनों में कोहराम मच गया।

ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के आधारपुर गांव निवासी छूरी का पुत्र सतरेन अपने साथी अंकुश पुत्र गंगाराम 18 वर्ष के साथ बाइक से अपनी बहन के यहां मुतौर गांव जा रहे थे। जैसे ही ये लोग सिधांव गांव के पास पहुंचे तभी आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए जिससे सतरेन की घटनास्थल पर मौत हो गई वहीं अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को तत्काल सरकारी एंबुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सक ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

काली नदी में कूदे अधेड़ का शव कुसुमखोर क्षेत्र में मिला

गुरसहायगंज (कन्नौज)। विगत दिन पूर्व किसी बात से आहत होकर अधेड़ ने रामाश्रम में स्थित काली नदी में कूद गया। नदी किनारे अधेड़ की साइकिल व कपड़े मिलने पर नदी में डूबने की आशंका से पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीण गोताखोरों ने खोजबीन शुरू कर दी थी। बुधवार की शाम 05 बजे अधेड का शव सदर थानाक्षेत्र की कुसुमखोर पुलिस चौकी क्षेत्र में मिला। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। ज्ञात हो कि बीते सोमवार की शाम 06 बजे क्षेत्र के ग्राम संगुरा स्थित रिश्तेदारी में रह रहे 45 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र राधेलाल किसी बात से आहत होकर साइकिल पर सवार होकर रामाश्रम में स्थित काली नदी के निकट साइकिल के करियर पर चप्पल व कपड़े रखकर काली नदी में कूद गया था।

बीआरसी पर एआरपी को महिला के भेष में आए हमलावर ने मारी गोली

फर्रुखाबाद। कमालगंज बीआरसी पर मौजूद आरपी के महिला के बेस में आए हमलावर ने पेट में गोली मार दी। जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई उन्हें शहर के एक निजी नर्सिंग होम में उपचार हेतु भर्ती किया गया। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम रूनी चुरसई निवासी विश्राम सिंह की कमालगंज क्षेत्र के नौगंवा में प्रधानाचार्य के पद पर तैंनाती है। वह एआरपी पद पर भी हैं। बुधवार को वह कमालगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मौजूद थे, इस दौरान बताया जा रहा है कि महिला के वेश में कोई हमलावर बीआरसी कार्यालय पहुंचा और उसने देखकर विश्राम सिंह राजपूत के पेट में गोली मार दी इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गएस उन्हें नाला मछरटटा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया स मौके पर पुलिस नें जाँच की। बीआरसी के सीसीटीवी खराब घटना के बाद मौके पर थाना पुलिस पंहुची, पुलिस नें सीसीटीवी को खंगालने का प्रयास किया।

16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग में प्रवेश दिया तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

● **आदेश नहीं माना तो एक लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी**

फतेहपुर। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में कोचिंग संचालकों पर एक लाख रुपये जुर्माना और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही होगी। डीआईओएस राकेश कुमार ने सभी कोचिंग संचालकों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

डीआईओएस ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद गाइड लाइन जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। अपराधिक व्यक्ति से नहीं ली जा सकती सेवाएं: कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

संस्थानों को करना होगा ब्यौरा उजागर: डीआईओएस ने बताया कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी। जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों (ट्यूटर्स) की योग्यता, पाठ्यक्रम-पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा। विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए।

पारदर्शी होना चाहिए शुल्क: निर्देशों में बताया गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि यदि छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए।

माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु करें आवेदन

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि ष्उ0प्र0 माटीकला बोर्डष् के अर्न्तगत ष्मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगारष् योजना संचालित की गयी है। जिसमें वर्ष.2024.25 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कार्यक्षेत्र उद्यम की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनुमन्य है। परियोजना का अधिकतम आकार.रू0 10.00 लाख तक है। पात्र उद्यमी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो एवं अभ्यर्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो।आवेदक द्वारा माटीकला बोर्ड के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जायेगा। आपेक्षित दस्तावेज आवेदक का फोटोग्राफए शैक्षिक व तकनीकि योग्यता सम्बन्धी प्रमाण.पत्र आधार कार्ड, जाति प्रमाण.पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि है। शैक्षिक व तकनीकि योग्यता अभ्यर्थी का साक्षर अनिवार्य हैए रू0. 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु लाभार्थी को कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं अभ्यर्थी को ऋण लेने से पूर्व माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त/माटीकला की परम्परागत जानकारी हो।

परियोजना की मंजूरी तकनीकि/आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार राष्ट्रीयकृत/ ग्रामीण बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जायेगीए जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिये होगी। वित्तीय स्रोत एवं सहायता प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूंजीगत ऋण धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन आनलाईन उपरान्त कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (बैंक ऑफ इण्डिया के प्रथम तल पर) चिटिकपुर चौराहा रनियां कानपुर देहात में 15.08.2024 तक जमा कर सकते हैं।

कई गांवों में घुसा पानी चेतावनी बिंदु पर पंहुची गंगा

संवाददाता। फर्रुखाबाद

गंगा नें एक बार फिर उफान मार दिया है। आज गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर पंहुच गया। जिससे कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अधिकारियों ने बाढ का जायजा लिया सगत दिन से गंगा का जलस्तर 5 सेंमी बढ़ गया।

गंगा 136.60 मीटर यानी चेतावनी बिंदु पर आ गयीं। गंगा में 99141 क्यूसेक पानी नरौरा बैराज से छोड़ा गया । राजेपुर गंगापार में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। सैकड़ो बीघा मक्का, तीली की फसल नष्ट हो गयी। जिन गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है उन गांव की वि ुत आपूर्ति बंद की गयी है।

थानाध्यक्ष रणविजय सिंह, एसडीओ सुरजीत कुमार गुप्ता, अवर अभियंता विद्युत विभाग हरिओम कुमार ने क्षेत्र के गांव तीस राम की मड़ैया, सबलपुर, कंचनपुर, चित्रकूट, अंबरपुर, पूर्वी गोटिया के आधा दर्जन गांवों में ज्यादा भ्रमण किया। गंगा का जल लगातार बड़ रहा है जिससे गंगा पार के ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ गयी हैं। गंगा के आसपास बसे लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुसने लगा है।

ऊगरपुर, सुंदरपुर, कछुआ गाढ़ा, लायलपुर, कुतुलूपुर, सबलपुर, जोगराजपुर, कुसुमापुर, आशा की मडैया, उदयपुर, तीसराम की मडैया, सैदापुर, करनपुर घाट, कुंडरी सारंगपुर आदि गांवों के पास पानी पहुंच गया है।

दो जगह कटा सम्पर्क मार्ग

तीस राम की मड़ैया का संपर्क मार्ग दो जगह बाढ़ में कटने से आवागमन बंद हो गया है गांव में आधा दर्जन लोग बुखार खुजली से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत

फर्रुखाबाद। कमालगंज थाना क्षेत्र में आज बुधवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक गृह स्वामिनी महिला की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के ग्राम श्रगीरामपुर निवासी वीरपाल की पत्नी गृहस्वामिनी फूलमती उम्र करीब 40 वर्ष आज बुधवार को अपने मकान की छत पर झोपड़ी में खाना बना रही थी कि दोपहर में बारिश के बीच तेज कड़क के साथ बिजली की गर्जना हुई और इसी दौरानअचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झोपड़ी से बाहर निकली गृह स्वामिनी महिला की मौत हो गई। इस महिला को समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सरकारी चिकित्सक डा. विकास कुमार ने उसे अमृत घोषित कर दिया। महिला के चार पुत्र और एक पुत्री है । महिला के पति का रो रो कर बुरा हाल है। इधर धटना की सूचना मिलते ही फर्रुखाबाद सदर के तहसीलदार श्री कनौजिया तथा पुलिस मौके पर पहुंची। शब का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फतेहगढ़ को भिजवाने की कार्रवाई की।

आठ परिषदीय विद्यालयों में केवल एक शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक चला रहे विद्यालय

● **रिपोर्ट में एक विद्यालय को एक साल में कई शिक्षक रंगाई पुताई का कर रहे है दावा,टीवी के स्थान पर खाली डिब्बा मिला चार्ज में,दर्जी की दुकान नही मगर ड्रेस सिलवाने का किया गया दावा**

संवाददाता। मौदहा (हमीरपुर)

कस्बे के आठ परिषदीय विद्यालयों में केवल एक शिक्षक नियुक्त है। जो सभी विद्यालयों का वित्तीय कार्य भी देख रहा है। सभी विद्यालय शिक्षा मित्र व अनुदेशक के भरोसे चल रहे है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में दस बच्चो में दो अध्यापक व तीन शिक्षक नियुक्त है। इस स्थिति में जमकर वित्तीय घोटाले हो रहे है। सबसे ज्यादा घोटाला व्दिालयों की मेंटीनेंस में बताया जाता है जिसकी सुगबुगाहट होना शुरु हो गयी है।

जानकारी के मुताबिक शासन की तरफ से परिषदीय विद्यालयो में विभिन्न मदो में लाखो रुपये की धनराशि आवंटित होती मगर इस धन का जमकर दुरुपयोग होती है इधर कुछ अध्यापकों ने दूसरे स्कूलों में जाकर चार्ज लिया है तो वित्तीय घोटाले सामने आने शुरु हो गये है। मौदहा नगर क्षेत्र में इस दौरान आठ प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक की तैनाती है जो नगर क्षेत्र के शंकुल प्रभारी का काम भी देखते हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश है कि हर हाल में एक शिक्षक तो विद्यालय में नियुक्त होना चाहिये इधर ज्यादातर शिक्षक अपने मूल स्थान पर पहुच गये जिससे स्थितिया बेहद खराब हो गयी है. शिक्षक मूल स्थान पर तो पहुच गये मगर अपना चार्ज नही छोडा है। ताकि उनके द्वारा कीगयी वित्तीय अनियमिताओ की जानकारी उजागर न हो सके।एक विद्यालय के अध्यापक द्वारा खरीदने के बाद खराब एलीडी टीवी छोड़ा गया था जो डब्बे के माडल और कम्पनी से मैच नहीं कर रही है इतना ही नहीं एक सरकारी विद्यालय के भवन को नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के द्वारा पुतवाने की बात सामने आ रही है जबकि चौधराना में एक ही कमरे में चल रहे तीन स्कूलों को एक ही शैक्षिक सत्र में सभी के प्रधानाचार्य ने रंगवाने और पुतवाने का काम किया है इतना ही नहीं आरटीआई के तहत मांगे गए आय व्यय के बिल

मौदहा का बीआरसी विद्यालय

बाउचरों में बीआरसी द्वारा बांदा के जिस टेलर से कुछ साल पहले ड्रेस सिलवाने के बिल की फोटो कापी भेजी गई है वह टेलर एक दशक पहले अपनी दूकान बंद कर सूरत की एक कम्पनी में रेडीमेड कपड़ों की सिलाई कर रहा है।इतना ही नहीं एक दशक पहले जो स्कूलों के खातों में पैसा पड़ा हुआ था उसे भी अध्यापकों ने निकाल कर ठिकाने लगा दिया है। जिसके चलते सम्पूर्ण चार्ज देने के बाद बड़े खुलासे का अनुमान है हालांकि विभाग इस मामले को बाहर आने देगा या कार्यवाही करेगा इस बात की उम्मीद कम है।इस सम्बंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी रामगोपाल वर्मा ने बताया कि सभी अध्यापकों को दो दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है और शुक्रवार दो बजे सभी को बुलाया गया है उनके आने के बाद ही चार्ज नहीं देने की वजह साफहो सकेगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

बीएसए ने कहा समायोजन की कार्यवाही शुरु की जा रही

हमीरपुर। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी(बीएसए) आलोक सिंह का कहना है कि शासन से समायोजन करने की कार्यवाही शुरुआत की जा रही है। आज इसी बात को लेकर बैठक हुई है। ट्रांसफर करना उनके अधिकार में नही है। शिक्षकों की वैसे ही कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय में कई ई शिक्षक है इस पर बीएसए का कहना है कि इसी मामले की समीक्षा की जा रही है। मगर फिर भी इस मामले में देखा जा रहा है।

क्या बोले सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला

हमीरपुर। इस मामले में सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि इस मामले को वह गंभीरता से जांच करायेगे,हालाकि ट्रांसफर पोस्टिंग अब सीधे शासन से होती है बीएसए के अधिकार क्षेत्र में कुछ नही रह गया है। फिर भी वह बीएसए से बात करके शिक्षकों की नियुक्ति करायी जायेगी।शिक्षकों की वैसे भी बहुत कमी है।

भाजपा विधायक ने गोवा में शराबबंदी की मांग की

भाषा। पणजी

गोवा विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक प्रेमेन्द्र शेट ने तटीय राज्य में शराबबंदी की मांग की जिससे उनकी ही पार्टी के कई सदस्य असहमत दिखे। सदन में मंगलवार को शेट ने कहा था, विकसित भारत और विकसित गोवा के लिए गोवा में शराब की खपत पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम राज्य में शराब का उत्पादन कर सकते हैं और इसे दूसरे राज्यों को निर्यात कर सकते हैं, लेकिन गोवा में इसकी खपत पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उत्तरी गोवा के माएम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्वाचित भाजपा विधायक ने अपनी मांग के पक्ष में दलील दी कि राज्य में शराब की बढ़ती खपत के कारण सड़कों और औद्योगिक इकाइयों में दुर्घटनाओं से लोगों की मौत होती है। हालांकि, सदन में उनकी पार्टी के विधायक ही इस मांग से सहमत नजर नहीं आए।

भाजपा की महिला विधायक डेलिलाह लोबो ने बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में आश्चर्य जताया कि क्या शेट चाहते हैं कि लोग अपने रेस्तरां व्यवसाय बंद कर दें। लोबो अपने पति माइकल लोबो (कैलंगुट विधायक) के साथ उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्र में होटलों की एक श्रृंखला की मालिकन हैं। उन्होंने सवाल किया, शराब भी एक कारण है जिसके कारण पर्यटक यहां आते हैं। हम क्या करें... क्या हमें रेस्तरां बंद कर देना चाहिए?

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक क्रूज सिल्वा ने कहा कि गोवा में शराब पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यहां सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन गोवा के लोग इसमें शामिल नहीं होते। यहां बहुत सारे रेस्तरां और अन्य व्यवसाय हैं जो शराब की बिक्री पर निर्भर हैं। शराब पर प्रतिबंध से रोजगार प्रभावित होगा। भाजपा विधायक संकल्प अमोनकर ने कहा कि वह शराब के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने राज्य में शराब के आदी लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में पहले भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था, लेकिन वह शेट के विचारों से सहमत नहीं हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के एक अन्य विधायक केदार नाइक ने कहा कि गोवा एक पर्यटन राज्य है और शराब पर्यटन उद्योग का एक हिस्सा है। कई स्थानीय लोगों का व्यवसाय राज्य में शराब बेचने संबंधी उद्योग पर निर्भर है।

लोगों को जबरन बेदखल करने और घरों के तोड़ने के मामले में आजम खान बरी

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अदालत ने यहां डूंगरपुर इलाके में लोगों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल करने और घरों को तोड़ने के पांच वर्ष पुराने मामले में सपा के नेता आजम खान को बुधवार को बरी कर दिया। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को उनके घरों से बेदखल किया और मकानों को ध्वस्त करने का काम किया। हालांकि अदालत से राहत मिलने के बावजूद खान सीतापुर जेल में ही रहेंगे। खान कई अन्य मुकदमों के सिलसिले में जेल में बंद हैं पीड़ित इदरीस नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसपर सांसद-विधायक अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान स्वास्थ खराब होने के कारण अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया, आजम खान और पांच अन्य को इस मामले में बरी कर दिया गया। खान के साथ-साथ ठेकेदार बरकत और चार अन्य को भी इस मामले में बरी किया गया है।

दंगों के बाद मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने वाले समूह के खिलाफ प्राथमिकी आदेश

पाटन (गुजरात)। गुजरात के पाटन जिले की एक अदालत ने पिछले साल जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक गांव में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किए जाने का कथित तौर पर आह्वान करने वाले लोगों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एच पी जोशी की अदालत ने हाल में एक आदेश में बलिसाना पुलिस थाने के उपनिरीक्षक को याचिकाकर्ता मकबूल हुसैन शेख की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि बलिसाना में कुछ लोगों ने 16 जुलाई, 2023 को सांप्रदायिक दंगे की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर स्थानीय लोगों को मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया।

उन्होंने याचिका में कहा, इस कदम से क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों के व्यवसाय और आजीविका प्रभावित हुई है और कुछ को तो यह स्थान छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। अदालत ने निर्देश दिया कि समूह पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा (153-बी) और दुश्मनी की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से अफवाह या आपत्तिजनक बयानों को प्रसारित या प्रकाशित करने के लिए धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया जाए।

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि घृणा फैलाने वाले भाषण से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसे प्राथमिकी में जोड़ने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि पुलिस ने गांव में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वालों के खिलाफ कार्वाई कथित तौर पर शुरू नहीं की। इससे पहले के आदेश में अदालत ने पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि कोई अपराध नहीं हुआ है। अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिप और प्रभावित व्यक्तियों के बयानों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 26 जुलाई को पारित आदेश में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

भाजपा में शामिल हो सकती हैं राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली बीजद नेता ममता मोहंता

नई दिल्ली। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाली बीजू जनता दल (बीजद) की नेता ममता मोहंता के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि ममता ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ममता मोहंता अप्रैल 2020 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थीं और वह महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य थीं। ममता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति की भी सदस्य थीं। ओडिशा विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत है और उनके इस्तीफे के बाद होने वाले उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का निर्वाचित होना लगभग तय है।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में विषम परिस्थितियों के बावजूद बचावकर्मी डटे हैं अपने मिशन में

वायनाड (केरल)। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में उफनती नदियों पर अस्थाई पुल बनाने तथा मलबों को हटाने में भारी मशीनों के लगे रहने के साथ ही बुधवार को बचाव अभियान जारी रहा। सैन्यकर्मियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों, राज्य आपात सेवा के कर्मियों, स्थानीय लोगों समेत बचाव कार्य में शामिल सरकारी एवं गैर सरकारी लोग इलाके में वर्षा जारी रहने एवं अन्य विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने मिशन में लगे हुए हैं। बुरी तरह प्रभावित गांवों में से एक, मुंडक्कई में, कटे हुए क्षेत्र से जुड़ने और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रस्सियों एवं सीढ़ियों की मदद से छोटे पुल बनाए गए।

उफनती नदियों के ऊपर बने अस्थाई और संकरे पुलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों समेत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था तो कई बार तनावपूर्ण क्षण सामने आए। कुछ स्थानों पर बचावकर्मियों ने लोगों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए मानव पुल बनाए। जोखिम भरे इलाकों में लोगों को लकड़ी के तख्त पर बिठा कर उफान पर आई नदी को पार कराया गया। चूंकि ज्यादातर मकान जर्मींदोज हो चुके हैं, ऐसे में बचावकर्मी छत तोड़कर रस्सी के सहारे घर में घुसे ताकि यह पता किया जा सके कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, लगातार हो रही वर्षा, फिसलनभरी जमीन, उफनती नदी बचाव मिशन की राह में चुनौतियां पेश कर रही हैं। कई बचाव एजेंसियों ने लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के मद्देनजर सुबह ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह मूसलाधार बारिश के कारण हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने मुंदक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा बस्तियों को प्रभावित किया।

न्यायालय ने सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा का जिक्र कर गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक कायम रखी

नई दिल्ली। फिल्म शोले के संवाद सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की समय पूर्व रिहाई पर रोक लगाने संबंधी अपने पहले के आदेश की पुष्टि की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के पांच अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए तीन जून के अपने आदेश को बरकरार रखा और अपीलों पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की। उच्च न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को 2006 की सजा माफी नीति के तहत गवली की समय पूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। हम कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं हैं। हमारे द्वारा दिए गए अंतरिम रोक संबंधी आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने दलील दी कि गवली के खिलाफ हत्या के लगभग 10 मामलों सहित 46 से अधिक मामले दर्ज हैं। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकील से पूछा कि क्या गवली ने पिछले पांच से आठ वर्षों में कुछ किया है ठाकरे ने जवाब दिया कि गैंगस्टर 17 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दोषियों को सजा में छूट के लिए कम से कम 40 साल की सजा काटनी होती है। यह 2015 की नीति के अनुसार है।

गवली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कहा कि मामले में अन्य सह-आरोपियों को जमानत दे दी गई है और बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा समयपूर्व रिहाई देने का निर्णय सही था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी सजा माफी नीति (2015 में) बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि गवली को 2009 में दोषी ठहराया गया था, इसलिए 2006 की नीति लागू होगी। यह नीति उम्र और शारीरिक दुर्बलता के आधार पर छूट की अनुमति देती है।

इस पर पीठ ने गवली की वकील से कहा, लेकिन मैडम आपको पता होना चाहिए कि हर कोई अरुण गवली नहीं होता है। शोले फिल्म में एक मशहूर संवाद है, जिसमें कहा जाता है कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा , ऐसा ही कुछ मामला यहां भी है। गवली की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि वह दिल और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहा है। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा 40 वर्षों तक लगातार धूम्रपान करने के कारण हुआ है।

रामकृष्णन ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, आप इस वजह से उसे अंदर नहीं रख सकते। उस पर धूम्रपान का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। सलाहकार बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि वह अपनी उम्र के हिसाब से कमजोर है, इसलिए 2006 की नीति लागू होगी क्योंकि उस समय उसे दोषी ठहराया गया था। वर्ष 2015 की बाद की नीति लागू नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय ने तीन जून को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के पांच अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी जिसने राज्य के अधिकारियों को गवली की समय पूर्व रिहाई के आवेदन पर 2006 की सजा माफी नीति के तहत विचार करने का आदेश दिया था उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गवली की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसमें उसने 10 जनवरी, 2006 की सजा माफी नीति के आधार पर राज्य सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था जो 31 अगस्त, 2012 को उसकी दोषसिद्धि की तारीख तक लागू थी।

सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार देने के लिए साझा मंशा होना पर्याप्त है: उच्च न्यायालय

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में अगर किसी एक आरोपी ने यौन कृत्य किया और बाकियों का ऐसा करने का इरादा था तो यह उन्हें अपराध में शामिल मानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस बारे में पर्याप्त सबूत होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर में 2015 में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने और उसके पुरुष मित्र पर हमला करने को लेकर चार लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी। दो दोषियों ने अपनी अपील में दावा किया कि उन्हें सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे महिला के यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपराध से पहले उनकी ऐसा करने की कोई मंशा भी नहीं थी।

न्यायामूर्ति जी. ए. सनप की एकल पीठ ने मंगलवार को उपलब्ध हुए चार जुलाई के आदेश में दोनों दोषियों की इन दलीलों को ठुकरा दिया और कहा कि उन्होंने उस समय पीड़िता के मित्र को पकड़ रखा था। पीठ ने कहा कि अगर दोनों ने पुरुष मित्र को पकड़ कर न रखा होता तो वह शोर मचाकर दो अन्य व्यक्तियों को पीड़िता के साथ घिनौनी हरकत करने से रोक सकता था। अदालत ने कहा, सामूहिक बलात्कार के मामले में अगर किसी एक आरोपी ने यौन कृत्य किया और बाकी आरोपी उसमें किसी तरह से शामिल थे तो यह उन्हें अपराध में शामिल मानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके पर्याप्त सबूत होने चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि दो दोषियों की हरकत ने बलात्कार के कृत्य में दो अन्य दोषियों की मदद की।

अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार देने और 20 साल जेल की सजा सुनाने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चारों दोषियों की अपील खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जून 2015 में पीड़िता और उसका पुरुष मित्र एक मंदिर गए थे और बाद में एक वन क्षेत्र में बैठे थे, तभी चार आरोपियों ने खुद को वन रक्षक बताते हुए उनसे पैसे मांगे। जब पीड़िता शौच के लिए गई तब दो आरोपियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जबकि बाकी दो ने उसके पुरुष मित्र को पकड़ रखा था। इलाके से गुजर रहे वन रक्षक ने महिला की चीख सुनी और मौके पर पहुंचे, तब चारों आरोपी फरार हो गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने चारों दोषियों के खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। पीठ ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य चारों आरोपियों के अपराध को साबित करते हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा के बंदरगाह पर चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया

पारादीप (ओडिशा)। ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने एक चीनी मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है। उच्च न्यायालय ने मौद्रिक विवाद पर जहाज को कब्जे में लेने के आदेश दिया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नौवहन संबंधी कानून के तहत, किसी भी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावों के क्रियान्वयन के लिए जहाज को कब्जे में लिया जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह आदेश जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद के बाद आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल की खेप भेजी थी। जहाज अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रुका रहेगा। माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि जहाज के मालिक ने उसे 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। पेश किए गए दस्तावेज और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सोमवार को जहाज को कब्जे में लेने का आदेश दिया।

नाइंसाफी के बावजूद हम राजग के साथ बने रहे : पारस

पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के साथ नाइंसाफी हुई लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ बने रहने का फैसला किया। बिहार में राजग के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पारस ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। पारस, पार्टी की एक बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन के बाद रालोजपा आस्तित्व में आई थी। पारस ने कहा हालांकि लोकसभा चुनाव में हमें बुरा लगा लेकिन हमने अपनी वफादारी नहीं बदली। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे समझेंगे और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमें उचित प्रतिनिधित्व देंगे।

भारत में पशुओं के लिए चारे की कमी : राजीव रंजन सिंह

नई दिल्ली। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत में पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति का संकट है। सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया देश में चारे की कमी है। आईसीएआर-भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) झांसी ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे और सूखे चारे की क्रमश: 11.24-32 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की कमी है। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार पशु चारे की कमी से अवगत है? सिंह ने बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग 2014-15 से चारा और चारा विकास पर एक उप मिशन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू करके राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को मदद दे रहा है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई झांसी-आईसीएआर) ने 25 राज्यों के लिए चारा संसाधन विकास योजना तैयार की है, ताकि राज्यों में उनके फसल पद्धति और पशुधन प्रजातियों के आधार पर चारे की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

एक अलग प्रश्न के उत्तर में, सिंह ने कहा कि देश में दूध का उत्पादन 2018-19 में 18.77 करोड़ टन से बढ़कर 2022-23 में 23.06 करोड़ टन हो गया है। देश में सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उप्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 53.08 फीसदी का योगदान करते हैं। सिंह ने कहा कि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। मंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन लगभग 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन है। हम घरेलू मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर हैं।

कांग्रेस की बंगाल इकाई में आसन्न बदलाव पर माकपा एवं तृणमूल की करीबी नजर

भाषा। कोलकाता

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई में आसन्न नेतृत्व परिवर्तन पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी करीब से नजर रख रही है, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तीनों दल विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं लेकिन कांग्रेस-वाम गठबंधन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों का विरोध करता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में पश्चिम बंगाल के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहे अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में राज्य इकाई के नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस साल 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस-वाम गठबंधन और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें तृणमूल ने राज्य की कुल 42 सीट में से 29 पर, भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की।

मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर से पांच बार के सांसद रहे चौधरी तृणमूल उम्मीदवार एवं क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार गए थे। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान गुप्त रखते हुए पीटीआई-भाषा को बताया, हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तृणमूल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन राज्य में अधीर रंजन चौधरी के विरोध के कारण गठबंधन नहीं हो सका। उन्होंने हम पर नियमित रूप से हमला करके राज्य में भाजपा के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की।

तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी इसी तरह की भावना प्रकट की। चौधरी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर माकपा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने पीटीआई-भाषा से कहा, अगला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, यह उनका आंतरिक मामला है। अधीर चौधरी ने वामदलों के साथ मिलकर बंगाल में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राज्य में तृणमूल एवं भाजपा दोनों का विरोध करने वालों में प्रमुख थे। हालांकि, वाम मोर्चा के एक अन्य नेता ने चिंता व्यक्त की कि यदि कांग्रेस बंगाल में तृणमूल के करीब जाती है, तो मौजूदा वाम-कांग्रेस गठबंधन खतरे में पड़ सकता है।

पेज 1 का शेष

शाह का ...

के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विजयन ने कहा, यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 91 लोगों का इलाज चल रहा है जबकि 240 लोग लापता हैं। मेरी सरकार ने जिले के 82 राहत शिविरों में 8107 लोगों को रखा है। मौसम विभाग ने बारिश या भूस्खलन को लेकर कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया था। मुंडक्कई में भूस्खलन के कुछ घंटों बाद मंगलवार सुबह 6 बजे जीएसआई द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया। भूस्खलन मंगलवार सुबह 2 बजे और 4.30 बजे हुआ। केंद्रीय जल आयोग, जो बाढ़ की चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, ने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि केंद्रीय एजेंसियों ने 48 घंटों की अवधि के लिए 404 मिमी बारिश का अनुमान लगाया था, लेकिन इस अवधि के दौरान क्षेत्र में 572 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूस्खलन चेतावनी प्रणाली जिले में होने वाले भूस्खलन के बारे में पूरी तरह से चुप है। केरल विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है और राज्य ने प्राप्त चेतावनियों और पूर्वानुमानों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं की थीं। इस बीच भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की सहायता से तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमें मुंडाक्कई और भूस्खलन और बारिश से तबाह हुए अन्य क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। प्रेस में जाने के समय, वायनाड जिले में भारी गिरावट का अनुभव हुआ और पर्यावरणविदों ने और अधिक भूस्खलन की संभावनाओं के बारे में चेतावनी दी। पर्यावरण कार्यकर्ता जॉन पेरुवंतनम ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आरोप कि केंद्रीय एजेंसियों ने समय पर चेतावनी जारी नहीं की, को चुटकी भर नमक के साथ लिया जाना चाहिए। जॉन ने कहा, हम सभी कई दिनों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों के बारे में पढ़ रहे थे लेकिन हुआ यह है कि राज्य प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुंडक्कली के पास चूरलमाला में एक बागान में काम करने वाले 40 साल से अधिक उम्र के दिखने वाले मजदूर जयन ने संवाददाताओं को बताया कि उसकी पत्नी के परिवार के 11 सदस्य लापता हैं। हमने मलप्पुरम जिले के नीलांबुर में चलियार नदी से बरामद एक बच्चे के शव की पहचान मेरे एक रिश्तेदार के रूप में की है। हमें अब तक केवल तीन शव मिले हैं और बाकी अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि चूरलमाला में अधिकांश घर भूस्खलन के कारण बाहर निकले पत्थरों के कारण ढह गए। मुख्यमंत्री ने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में नकद दान करने और इसे किसी अन्य एजेंसी को नहीं भेजने को कहा। उन्होंने लोगों से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी सामग्री नहीं भेजने को भी कहा। संसद में बुधवार को वायनाड भूस्खलन मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच वाकयुद्ध हुआ। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वायनाड का प्रतिनिधित्व कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भूस्खलन का मुद्दा कभी नहीं उठाया। उनकी टिप्पणी के कारण कांग्रेस सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड सांसद के रूप में, राहुल गांधी ने कई मौकों पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वायनाड का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया कि सूर्या बहस को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कांग्रेस नेता के बारे में झूठे दावे करने के लिए माफी मांगनी होगी। वेणुगोपाल ने कहा, सदन के रिकॉर्ड साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है।

कोचिंग सेंटरों...

मकान मालिकों द्वारा अत्यधिक किराये, आग की मंजूरी, नालों से गाद निकालने और छात्रों की अन्य तत्काल जरूरतों से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करेगी। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा, समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे-धीरे एक सुनियोजित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार करेगी।

ईरान...

के लिए तेहरान में था। उसने बताया कि हनिएह तेहरान में अपने आवास पर यहूदी हवाई हमले में मारा गया। हमास ने एक बयान में कहा, हमास फलस्तीन के महान लोगों और अरब तथा इस्लामिक देशों के लोगों तथा दुनियाभर के सभी आजाद लोगों के लिए भाई इस्माइल हनिएह को शहीद घोषित करता है। हमास के अधिकारियों ने अभी इस पर और कोई टिप्पणी नहीं की है। वेस्ट बैंक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हनिएह की हत्या की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य और खतरनाक घटनाक्रम बताया। हनिएह ने 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दी थी और कतर में निर्वासन में रह रहा था। गाजा में हमास का शीर्ष नेता एह्या सिनवार है, जिसने सात अक्टूबर को इजराइल पर हमले की साजिश रची थी। इस हमले में 1,200 लोग मारे गए थे और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अप्रैल में गाजा में इजराइल के हवाई हमले में हनिएह के तीन बेटे और चार पोते-पोती मारे गए थे। हनिएह की हत्या ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रशासन हमास और इजराइल को एक अस्थाई संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते पर राजी करने का प्रयास कर रहा है। अभी व्हाइट हाउस ने हनिएह की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम बगदाद में एक अड्डे पर मंगलवार रात को हुए हमले में कताइब हिजबुल्ला मिलिशिया के चार सदस्य मारे गए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज, ईरान समर्थित मिलिशिया का एक गठबंधन है। समूह ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है।

पूजा...

सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उसकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं/यूपीएससी के चयन से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। पैनल ने कहा है कि पूजा खेडकर प्रकरण के मद्देनजर, उसने 2009 और 2023 के बीच आईएएस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मंजूरी देने वाले 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी। इस विस्तृत अभ्यास के बाद, सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले को

आर्थिक वृद्धि, रोजगार के बीच संतुलन साधता है बजट, सभी वर्गों का ध्यान

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बजट में आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच बेहतर संतुलन स्थापित के साथ सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। विपक्ष संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर वास्तव में दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा , बजट में आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया गया है। यह आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ रोजगार बढ़ाने वाला है। सीतारमण ने कहा, बजट में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को 22.91 लाख करोड़ रुपए दिए गए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.49 लाख करोड़ रुपए अधिक हैं। बजट में केवल दो राज्यों का नाम होने और अन्य की अनदेखी करने को लेकर अलोचना पर वित्त मंत्री ने कहा, अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके लिए बजट में कोई आवंटन नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पीछे के बजट को देखा जाए तो संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने भी अपने कई बजट भाषण में सभी राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया था।

सीतारमण ने कहा, 2004-05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। वहीं 2009-10 के पूर्ण बजट में 28 राज्यों का नाम नहीं था। अन्य बजट भाषण में भी कई राज्यों का उल्लेख नहीं था। क्या उन राज्यों को पैसा नहीं मिला? केंद्रीय करों में कम हिस्सेदारी के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है और केंद्र सरकार उसका पूरी तरह से पालन कर रही है। उन्होंने कहा, यह साफ होना चाहिए कि राज्यों को राशि शुद्ध कर राजस्व के आधार पर दी जाती है न कि सकल कर राजस्व के आधार पर। उपकर, सब्सिडी और कर संग्रह लागत घटाकर शुद्ध कर राजस्व का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) करता है। सीतारमण ने कहा, इसके उलट राजग सरकार ने राज्यों का जो भी बकाया है, उसका भुगतान समय पर किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का पूंजीगत व्यय 43.82 लाख करोड़ रुपए रहा जो एक दशक पहले संप्रग शासन के दौरान 2004-05 से 2013-14 के बीच 13.19 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 11.11 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का निर्धारण किया गया है। यह पूंजीगत व्यय मद में अबतक का सर्वाधिक आवंटन है। यह वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 17 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट का मकसद भारत को विनिर्माण कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना भी है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष में इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 तक हम इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाएंगे।

उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इसके उलट इन सभी क्षेत्रों के लिए आवंटन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। सीतारमण ने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 8,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह शिक्षा पर आवंटन बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए किया गया है। सीतारमण ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा, यह सबको पता है कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की गलत नीतियों से मुद्रास्फीति 22 महीनों तक दहाई अंक के करीब चली गई थी और यह वैश्विक औसत से अधिक रही थी। लेकिन आज यह काफी हद तक नियंत्रण में है। यह राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हुई है। दैनिक नकदी प्रबंधन के लिए जे एंड के बैंक से हुंडी और ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था का पुराना चलन अब समाप्त हो गया है। पिछले चार साल के दौरान, जे एंड के बैंक में उल्लेखनीय बदलाव आया है। बैंक को 2019-20 में ।,139 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन 2023-24 में उसे ।,700 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वित्त मंत्री ने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार और युवा बनाए रखने में मदद करेगी और इसपर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। बजट चर्चा के दौरान चिदंबरम ने अग्निवीर योजना की आलोचना की और सरकार से इसे वापस लेने को कहा था। सीतारमण ने कहा कि यह योजना हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुधारात्मक कदम है। उन्होंने राज्यों में पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भ्रामक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आड़े हाथ लिया। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष की आलोचना पर सीतारमण ने कहा, इससे परिवारों के लिए कम लागत में चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित हुई है। निश्चित रूप से इससे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को नुकसान पहुंचा है। खासकर मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के लोगों को क्योंकि अब मेडिकल सीटें बेचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि एनईईटी लीक मामला सामने आने से पहले भी विशेष लॉबी एनईईटी के खिलाफ सक्रिय थी।

राज्यसभा में उठी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाए जाने की मांग

नई दिल्ली।(भाषा) राज्यसभा में बुधवार को संस्कृत की उपेक्षा पर चिंता प्रकट करते हुए इस प्राचीन भाषा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अनिवार्य विषय बनाने और विश्वविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा शोध के लिए विशेष अनुदान देने की मांग उठी।उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य दिनेश शर्मा ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से संस्कृत साहित्य के डिजिटल स्वरूप का प्रचार-प्रसार करने, संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स आरंभ करने और इस भाषा में नाटकों, गीत और संगीत कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा देने की भी गुजारिश की।संस्कृत भाषा को देश की सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय स्रोत करार देते हुए शर्मा ने कहा कि इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यहां तक कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे अनेक ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं।उन्होंने कहा कि इनका अध्ययन आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह सभी ग्रंथ पुरातन ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तथा इसमें निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है।

शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष में आदिकाल से ही संस्कृत बोलचाल की भाषा रही है और तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं।संस्कृत को अन्य सभी भाषाओं की जननी करार देते हुए भाजपा सदस्य ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों में इसकी उपेक्षा बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा का अध्ययन दिन प्रतिदिन प्रचलन से दूर होता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रति रुचि घटती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी युवा पीढ़ी अपने प्राचीन ज्ञान से वंचित हो रही है। शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के उन्नयन का उल्लेख प्रसन्नता का विषय है लेकिन वह इसकी उपेक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं।उन्होंने कहा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए और इस भाषा में शोध के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।उन्होंने देश में ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की मांग की जहां संस्कृत के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई हो। शर्मा ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें इसका व्यापक ज्ञान मिलेगा। उन्होंने कहा, संस्कृत साहित्य का डिजिटल रूप में अनुवाद और प्रसार किया जाए ताकि यह आसानी से उपलब्ध हो सके। संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार भी आयोजित किए जाने चाहिए। संस्कृत में नाटकों, कविताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि लोगों में संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ सके।

भारत स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है

नई दिल्ली। (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत स्वदेशी तकनीक से देश में बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है। वैष्णव ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तकनीकी रूप से बहुत जटिल है और इसे जापान की मदद से क्रियान्वित किया जा रहा है। पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद और मुंबई के बीच निर्माणाधीन है। वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन दो पश्चिमी शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें से 320 किलोमीटर हिस्से पर काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वाले हिस्से में काम धीमा हो गया था, लेकिन 2022 में भाजपा-शिवसेना-राकांपा की महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई और राज्य सरकार से सभी प्रासंगिक अनुमतियां मिल गई हैं। उन्होंने कहा, अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। मंत्री ने कहा कि समुद्र के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग का निर्माण चल रहा है, जो 21 किलोमीटर लंबी होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीक विदेशों से मिली थी, लेकिन अब देश में भी कई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रहे हैं।

नीट व्यवस्था कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी : सीतारमण

नई दिल्ली।(भाषा) मेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) व्यवस्था की विपक्ष द्वारा तीखी आलोचना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि यह प्रणाली कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। सीतारमण ने उच्च सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नीट को सबसे पहले 2010 में अधिसूचित किया गया था और तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं द्रमुक नेता जी सेल्वन के नेतृत्व में इसका कार्यान्वन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में ही पहली नीट परीक्षा हुई थी। सीतारमण ने कहा कि 2011 में जब तमिलनाडु में द्रमुक का शासन समाप्त हुआ, उस समय राज्य में केवल ।,945 मेडिकल सीटें थीं जो अब बढ़कर 10,425 हो गई हैं और इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में 8,480 सीटों की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नीट किसी के भी खिलाफ नहीं है लेकिन इससे कुछ निहित स्वार्थों को नुकसान हुआ है, खासकर मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि अब सीट बेचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि एक विशेष लॉबी नीट लीक मुद्दे के सामने आने से पहले ही इसके खिलाफ थी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की नीति युवाओं को अधिक सक्षम बनाना है। चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कुछ सवाल उठाए थे। वित्त मंत्री सीतारमण ने उन सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि 2006 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजीपी का चयन राज्य सरकार की ओर से विभाग के सबसे वरिष्ठ तीन सदस्यों में से से किया जाएगा जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की भी भूमिका होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है।

प्रधानमंत्री से मिले शिवकुमार, कर्नाटक के लिए और अधिक धन की मांग रखी

बेंगलुरु। कर्नाटक के उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की और राज्य में सिंचाई परियोजनाओं एवं बेंगलुरु के विकास के लिए अधिक धनराशि दिए जाने की मांग रखी। शिवकुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु का गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकास किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के उस अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया गया था लिहाजा हमने सुरंग परियोजना, सिग्नल-मुक्त गलियारे, बेंगलुरु में मुख्य सड़कों और वर्षा-जल निकासी नालियों के विकास के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अधिक धन की मांग की है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु राष्ट्रीय खजाने में दूसरा सबसे अधिक कर देने वाला शहर है लेकिन हाल के केंद्रीय बजट में इसे कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कर्नाटक को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, हेब्बल और नेलमंगला में फ्लाईओवर के लिए धन मिला था। उन्होंने इस मुलाकात पर कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में केवल एक गिफ्ट सिटी (गुजरात) ही स्थापित की जा सकती है। इसलिए, हमने बेंगलुरु में शुरू की जाने वाली कई बड़ी परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। हमने बेंगलुरु को बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर जोर दिया है क्योंकि लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा है। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए पिछले बजट में 5,300 करोड़ रुपए देने के बावजूद केंद्र द्वारा कोई धन जारी नहीं करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है।

भारत, वियतनाम मुक्त व्यापार समझौते की संभावना तलाशें: वियतनामी प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए बुधवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाएं तलाशने का अनुरोध किया। चिन्ह इस समय एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में कई मंत्री, उप मंत्री और व्यापार जगत के दिग्गज शामिल हैं। उन्होंने वियतनाम-भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपना द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए।उन्होंने उद्योग मंडल फिक्की की तरफ से आयोजित बिजनेस फोरम में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम वियतनाम और भारत के बीच एक उपयुक्त एफटीए के माध्यम से एक-दूसरे के उत्पादों तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाएं।

कोचिंग सेंटरों से विद्यार्थियों को बाहर लाना ही होगा

नई दिल्ली। (भाषा) स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि कोचिंग सेंटरों से विद्यार्थियों को बाहर लाना ही होगा और सबके सहयोग से इसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रधान ने कहा कि विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोचिंग संस्थानों की मदद लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान न हों और इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसकी मिसाल हैं। पूरक प्रश्नों के जवाब में प्रधान ने कहा कोचिंग सेंटर न हों, इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। अनेक राज्यों में पढ़ाई को लेकर बेहतर स्थान हैं। राजस्थान में सीकर ने बहुत ही बढ़िया काम अध्ययन में किया है। इसी तरह से मेहनत करनी होगी और सबका सहयोग लेकर हमें विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों से बाहर लाना होगा। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की संसद के प्रति जवाबदेही के बारे में प्रश्न पूछा जिसके जवाब में प्रधान ने कहा एनटीए की संसद के प्रति जवाबदेही के बारे में सवाल पूछा गया। इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी गई और मैं इससे संबंधित सवाल का संसद में जवाब दे रहा हूं, यही तो संसदीय जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि एक निकाय कई तरह की परीक्षाएं ले सके, इसके लिए एनटीए के बारे में सोचा गया। 2017 से शुरूआत हुई और 2018 में इसने आकार लिया। उन्होंने कहा कि छह साल में पांच करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दीं और अच्छे संस्थानों में उन्हें प्रवेश मिला। उन्होंने कहा कि ढाई सौ से अधिक परीक्षाएं हुईं। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समाज का एक वर्ग है क्योंकि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और सबकी इच्छा है कि वे आगे बढ़ें। शिक्षा आगे बढ़ने का माध्यम है। प्रधान ने कहा कि जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश में मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या 51,000 थी जो दस साल में बढ़ कर एक लाख दस हजार हो गई हैं।प्रधान ने कहा सरकार सभी तरह की जवाबदेही के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताती है। हमारी सरकार ज्यादातर जिलों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। राजद के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने जानना चाहा कि क्या एनटीए के कामकाज की निगरानी की कोई व्यवस्था है। प्रधान ने कहा कि एनटीए परीक्षा करवाती है और प्रश्नों के आकलन की एक व्यवस्था होती है और तय किया जाता है कि प्रश्न कैसे हों। यह आकलन समय-समय पर किया जाता है।

पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में चालीस हजार से अधिक लोगों की नियुक्ति की गई

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों पर 40,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की है। प्रधान ने कहा कि आईआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग से अनुभवी लोगों को लाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (पीओपी) प्रणाली शुरू की गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पीओपी आवश्यकता-आधारित होते हैं, न कि यह कोई स्थाई पद है। प्रधान ने कहा कि पीओपी शिक्षा में विशेषज्ञता और नए विचार लाएंगे। प्रधान ने कहा, पीओपी नई शिक्षा नीति के तहत एक प्रमुख सिफारिश है। अब आम सहमति है कि डिग्री के अलावा हमें योग्यता को भी महत्व देना होगा। शिक्षा को रोजगारपरक और उद्यमिता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए, उद्योग और शिक्षा के बीच संबंध आवश्यक है। मंत्री माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर रहे थे, जिन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने पीओपी के लिए 10 प्रतिशत शैक्षणिक पद आरक्षित किए हैं और क्या इससे उच्च संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कम हो जाएगा। ब्रिटास ने कहा कि लगभग 26 प्रतिशत शैक्षणिक पद और 46 प्रतिशत अन्य पद अभी रिक्त हैं और क्या इस तरह की पीओपी प्रणाली युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को प्रभावित करेगी। प्रधान ने कहा, हमने पिछले 4-5 वर्षों में रिक्त पदों पर 40,000 से अधिक लोगों को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय या कॉलेजों के किसी भी मौजूदा पद पर कब्जा नहीं करेगा। राकांपा सांसद फौजिया खान जानना चाहती थीं कि कितनी महिला प्रोफेसरों को पीओपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस पर प्रधान ने कहा कि यह विशेष संस्थानों की आवश्यकता, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है।

केंद्र ने राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से खनिजों पर रॉयल्टी वापस करने संबंधी याचिकाओं का विरोध किया

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में उस याचिका का विरोध किया जिसमें खनिज संपन्न राज्यों ने 1989 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर उसके द्वारा लगाई रॉयल्टी वापस करने का अनुरोध किया गया है। केंद्र ने कहा कि उसे राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रॉयल्टी वापस करने के लिए कहने वाले किसी भी आदेश के बहुआयामी प्रभाव होंगे।उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खदानों और खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का विधाई अधिकार है और खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से खनिज संपन्न राज्यों के राजस्व में भारी वृद्धि होगी। लेकिन इससे फैसले के क्रियान्वयन के संबंध में एक और विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ खनिज संपन्न राज्यों ने शीर्ष अदालत से इस फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया ताकि वे केंद्र से रॉयल्टी वापस मांग सकें। बहरहाल, केंद्र ने ऐसे किसी आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इसका बहुआयामी प्रभाव होगा।

वायनाड में भूस्खलन को लेकर तेजस्वी सूर्या की टिप्पणी के बाद लोस में विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली। (भाषा) लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने उस समय हंगामा किया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल के वायनाड में अतिक्रमण को लेकर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी परोक्ष रूप से निशाने पर लिया। सदन में नियम 197 के तहत प्राकृतिक आपदा पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सूर्या ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केरल में कई प्राकृतिक आपदाएं खासकर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं जिनमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई है।

उन्होंने सवाल किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने कहा कि राज्य के वन मंत्री ने केरल विधानसभा में कहा था कि अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि धार्मिक संगठनों का दबाव है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि वायनाड में गैरकानूनी अतिक्रमण का विषय जब कांग्रेस के एक सांसद ने उठाया तो उनका टिकट काट दिया गया। सूर्या ने कहा कि वायनाड से पांच साल तक सांसद रहे नेता ने वहां की प्राकृतिक आपदा को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई। इसके बाद विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजकर करीब 50 मिनट पर शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को इस दुखद घटना पर राजनीति करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस त्रासदी पर विपक्ष की तरफ से किसी ने राजनीति नहीं की, लेकिन सत्तापक्ष के सांसद से राजनीति की है...उन्होंने राहुल गांधी के बारे में सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने वायनाड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितनी बार आवाज उठाई है, इसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। वेणुगोपाल का कहना था, वायनाड, केरल और भारत के लोग राहुल गांधी को प्यार करते हैं। वह वायनाड से 3.6 लाख से अधिक मतों से जीते हैं। बिरला ने कहा कि सूर्या के भाषण में जो बात इस सदन और घटना की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगी उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इससे पहले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नित्यानंद राय ने कहा कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए 33 दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कई कदमों का उल्लेख किया और कहा कि 350 जिलों में आपदा के बचाव हेतु स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए योजना शुरू कर गई है और लगभग एक लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। राय का कहना था कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए नियमित रूप से मॉक अभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 23 जून, 2024 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में सभी केंद्रीय एजेंसियों की बैठक की गई, जिसमें सभी राज्यों को जरूरी मदद देने के लिए कहा गया है।

भारत में कई गुना बढ़ गई है रोहिंग्या घुसपैठ

गुवाहाटी। (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत में रोहिंग्या घुसपैठ काफी बढ़ गई है तथा जनसांख्यिकी में बदलाव आने का खतरा वास्तविक और गंभीर है। शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, रोहिंग्या लगातार भारत-बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल करके भारत में आ रहे हैं और कई राज्य जनसांख्यिकीय बदलाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम, भारत-बांग्लादेश सीमा के केवल एक हिस्से की पहरेदारी कर रहा है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र अभी भी खुला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकारें इन घुसपैठियों के प्रति नरम रुख अपना रही हैं और इसे रोकने के लिए कोई कार्वाई नहीं की है। शर्मा ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) ने बयान दिया था कि राज्य बांग्लादेश से आने वालों को शरण देगा, जिसका पड़ोसी देश की सरकार ने भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि असम

और त्रिपुरा सरकारों ने इस मामले में कड़े कदम उठाए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस ने कई मौकों पर कई रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, असम अब रोहिंग्या के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा, क्योंकि हम नरम नीति नहीं अपनाते। हमारी स्थिति पश्चिम बंगाल और झारखंड से बेहतर है। असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के सत्ता में आने के बाद से स्थिति खराब नहीं हुई है।

कमला हैरिस ही होंगी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पक्का कर लिया है, क्योंकि वह देश भर से पार्टी के प्रतिनिधियों से वर्चुअल रोल कॉल वोट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आधिकारिक समय सीमा समाप्त होने के बाद मंगलवार रात घोषणा की कि देश भर से 3,923 प्रतिनिधियों ने हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामांकन के लिए आवेदन दिए थे और उन्हें भाग लेने वाले 99 प्रतिशत प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हुआ।

डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) के अध्यक्ष जैमे हैरिसन और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन कमेटी (डीएनसीसी) की अध्यक्ष मिनियन मूर ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कोई भी अन्य उम्मीदवार मतपत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के संबंध में 300 प्रतिनिधि हस्ताक्षर की सीमा को पूरा नहीं कर सका। बयान में कहा गया कि वर्चुअल रोल कॉल पर वोटिंग एक अगस्त को शुरू होगी और पांच अगस्त को समाप्त होगी। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हैरिस आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन जाएंगी।

इस बीच, हैरिस ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहस के लिए चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें जो भी कहना है, वह उनके सामने कहें। जॉर्जिया के अटलांटा शहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हैरिस (59) ने कहा कि उनके दौड़ में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव की प्रकृति बदल गई है। हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा तब की जब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने 20 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के लिए दौड़ से हटने की घोषणा की।

हैरिस ने कहा, वक्त की चाल बदल रही है। ऐसे संकेत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसे महसूस कर रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, उन्होंने सितंबर में होने वाली बहस से खुद को अलग कर लिया, जिसके लिए उन्होंने पहले सहमति जताई थी।

उन्होंने उत्साहित भीड़ से कहा, डोनाल्ड, मुझे उम्मीद है कि आप बहस के मंच पर मुझसे मिलने के बारे में पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने कहिए। हैरिस की प्रचार टीम के अनुसार, महत्वपूर्ण चुनावी मैदान अटलांटा में उनकी रैली में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। हैरिस ने कहा, व्हाइट हाउस का रास्ता सीधे इसी राज्य से होकर जाता है और आप सभी ने 2020 में हमें जीतने में मदद की और हम 2024 में फिर से ऐसा करने जा रहे हैं।

वहीं, ट्रंप की प्रचार टीम ने महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों में एक नया विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खतरनाक रूप से उदार कमला हैरिस अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने में विफल रहीं। हालांकि हैरिस की प्रचार टीम ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।

ट्रंप की प्रचार टीम की वरिष्ठ सलाहकार डैनियल अल्वारेज ने कहा, कमला हैरिस की विफलता ने अमेरिका को कम सुरक्षित बना दिया है। प्रवासी अपराध बढ़ गए हैं, आतंकवादी देश की खुली सीमा से घुस आए हैं, मानव तस्करी हर राज्य को प्रभावित कर रही है। हैरिस खतरनाक रूप से उदार हैं और अमेरिकी इसकी कीमत चुका रहे हैं।

ट्रंप की प्रचार टीम ने कहा, ट्रंप ने हमारे देश के इतिहास में सबसे सुरक्षित सीमा बनाई। लेकिन कुछ ही वर्षों में कमला हैरिस ने लाखों अवैध अप्रवासियों के लिए दरवाजे खोल दिए। हैरिस की प्रचार टीम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, दशकों में सबसे कठिन सीमा समझौते को खत्म करने के बाद, ट्रंप अपने ट्रेडमार्क झूठ पर चल रहे हैं क्योंकि उनका अपना रिकॉर्ड और योजनाएं अलोकप्रिय रही हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को सूची में शामिल करने का स्वागत किया

जोहानिसबर्ग। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से जुड़े दक्षिण अफ्रीका के कई प्रतिष्ठित स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक , वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने का स्वागत किया है। यूनेस्को ने मंडेला से जुड़े 14 समेत अन्य स्थलों को मानव अधिकार , मुक्ति और सुलह : नेल्सन मंडेला विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। मंडेला ने दशकों तक श्वेत अल्पसंख्यक रंगभेद शासनकाल वाले दक्षिण अफ्रीका में 27 वर्ष तक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल की सजा काटी थी और इसके बाद वह देश के लोकतांत्रिक रूप से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 वें सत्र में यह घोषणा की गई। कार्यक्रम बुधवार को समाप्त हो रहा है। रामाफोसा के कार्यालय ने सोमवार को कहा , सामूहिक रूप से यह संपत्ति उन घटनाओं और विचारों को प्रदर्शित करती है , जो दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष के मूल के रूप में काम करती हैं , जो एक चौथाई सदी बाद भी मानवता को सुलह को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें कहा गया है , 14 घटक मानव अधिकारों , मुक्ति और सुलह की विजय में मजबूत स्मृतियों और विश्वासों का उदाहरण हैं। देश, इसके इतिहास और समृद्ध विरासत को दिए गए सम्मान के लिए यूनेस्को को धन्यवाद दिया गया है। इन स्थलों में प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स शामिल हैं , जहां मंडेला ने पहली बार कार्यालय संभाला था और जोहानिसबर्ग में कांस्टीट्यूशन हिल , दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय का मुख्यालय है , जो कभी कुख्यात फोर्ट जेल हुआ करता था। यहां मंडेला और उनसे पहले महात्मा गांधी दोनों को कैद किया गया था। यूनियन बिल्डिंग विश्व धरोहर सूची में शामिल क्रेमलिन, कासुबी टॉम्ब्स, ताज महल, वेटिकन और अन्य वैश्विक स्थलों में शामिल हो गई है। इन दो क्रमिक संपत्तियों के शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका की विश्व धरोहर स्थलों की सूची बढ़कर 12 हो गई है।

यूरोपीय संघ की मुद्रास्फीति जुलाई में 4.1 प्रतिशत हुई

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी)। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 20 देशों के समूह यूरोपीय संघ में जुलाई माह में मुद्रास्फीति बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। यूरोपीय सांख्यिकी इकाई यूरोस्टैट ने बुधवार को मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए। इसके पहले जून में मुद्रास्फीति 2.5 प्रतिशत पर थी। ईसीबी की जिस सेवा मुद्रास्फीति पर करीबी नजर रहती है, वह जुलाई में मामूली रूप से घटकर चार प्रतिशत पर आ गया।

भीड़ ने मस्जिद पर पत्थर फेंके 40 पुलिस अधिकारी घायल

लंदन। पूर्वी इंग्लैंड में चाकू हमले में मारी गईं तीन बच्चियों की स्मृति सभा के समय धुर-दक्षिणपंथी लोगों के समूह ने एक मस्जिद को निशाना बनाया और इस दौरान फैली अव्यवस्था में करीब 40 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस हिरासत में मौजूद 17 वर्षीय संदिग्ध की नस्ल और धर्म के बारे में सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसार हुआ, मंगलवार रात साउथपोर्ट में स्थित मस्जिद से पास दंगा भड़क गया। पुलिस ने कहा कि उसके 22 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं।

दंगाइयों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया, स्थानीय मस्जिद पर पत्थर फेंके, एक स्थानीय दुकान में तोड़फोड़ की और कूड़ेदानों में आग लगा दी। सोमवार को हार्ट स्ट्रीट में एक डांस स्टूडियो में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद घटनास्थल पर जाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने भीड़ की निंदा की। साउथपोर्ट के लोग कल उन पर हुए हमले के बाद से सदमे में हैं। हम उनका समर्थन और सम्मान करते हैं।

जिन लोगों ने स्मृति सभा के दौरान हिंसा और गुंडागर्दी की उन्होंने शोकाकुल लोगों का अपमान किया है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्वाई की जाएगी। चाकूबाजी में जान गंवाने वाली बच्चियों की पहचान एलिस डा सिल्वा एक्वियर (9), बेबी किंग (6) और एलसी डोट स्टेनकॉम्ब (7) के रूप में हुई है। घटना में आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इनमें से पांच लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मर्सीसाइड पुलिस ने कहा है कि वह फिलहाल इस घटना को आतंकवाद से संबंधित नहीं मान रही है। पुलिस के सहायक मुख्य कांस्टेबल एलेक्स गॉस ने कहा, 17 वर्षीय एक युवक की पहचान के बारे में बहुत सी अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

इजराइली हमले में मारे गए कमांडर का शव तलाश रहे : हिज्बुल्लाह

बेरूत। लेबनान के उग्रवादी समूह हिज्बुल्लाह ने कहा कि वह बेरूत में इजराइल के हवाई हमले में मारे गए अपने एक शीर्ष सैन्य कमांडर के शव की अभी भी तलाश कर रहा है। इजराइल द्वारा हिज्बुल्लाह कमांडर फौद शुकुर को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले के बाद यह ईरान समर्थित उग्रवादी समूह की पहली टिप्पणी है। शुकुर को निशाना बनाए जाने से एक दिन पहले हमास नेता इस्माइल हनिएह की तेहरान में एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। हिज्बुल्लाह ने हमास नेता की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की इजराइल ने बेरूत पर एक अप्रत्याशित हमले के बाद शुकुर को मार गिराने का दावा किया। उसका कहना है कि शुकुर इजराइल नियंत्रित गोलान हाइट्स के मजदल शम्स शहर में गत सप्ताहांत हुए रॉकेट हमले में शामिल था, 12 लोग मारे गए थे। नागरिक सुरक्षा कर्मी अभी भी उस इमारत के मलबे के नीचे शुकुर और अन्य लोगों के शव की तलाश कर रहे हैं।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन व इण्डोनेशिया के रक्षा मंत्री हाथ मिलाते हुए।

नासा ने अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह से टकराकर इसके इतिहास का पता लगाया

द कन्वरसेशन। पर्थ। नासा का डीएआरटी मिशन - दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण - मानवता का पहला वास्तविक दुनिया का ग्रह रक्षा मिशन था। सितंबर 2022 में, डीएआरटी अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर एक छोटे क्षुद्रग्रह के साथी चंद्रमौ से टकरा गया। इस टक्कर का लक्ष्य यह पता लगाना था कि अगर कोई इस तरह हमारी तरफ आ रहा हो तो क्या हम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्षुद्रग्रह के हमारी तरफ बढ़ने और इस तरह के टकराव के बाद बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने से, हमें यह भी बेहतर अंदाज़ा मिलेगा कि अगर ऐसा कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है तो हमें क्या होगा। नेचर कम्युनिकेशंस में आज प्रकाशित पांच नए अध्ययनों में डिडिमोस-डिमोर्फोस दोहरे क्षुद्रग्रह प्रणाली की उत्पत्ति को जानने के लिए डीएआरटी और उसके यात्रा मित्र लिसियाक्यूब च से भेजी गई छवियों का उपयोग किया गया है। उन्होंने उस डेटा को अन्य क्षुद्रग्रहों के संदर्भ में भी रखा है। क्षुद्रग्रह प्राकृतिक खतरा हैं: हमारा सौर मंडल ऐसे छोटे-छोटे क्षुद्रग्रहों के मलबे से भरा है जो कभी ग्रह नहीं बन पाए। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के करीब आते हैं उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (एनईओ) कहा जाता है। ए हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा करते हैं, लेकिन सबसे सुलभ भी हैं। इन प्राकृतिक खतरों से ग्रहों की रक्षा वास्तव में उनकी संरचना को जानने पर निर्भर करती है - न कि केवल वे किस चीज से बने हैं, बल्कि वे एक साथ कैसे रखे गए हैं। क्या वे ठोस वस्तुएं हैं जो मौका मिलने पर हमारे वायुमंडल में घुस जाएंगी, या वे मलबे के ढेर की तरह हैं, जिन्हें बमुश्किल एक साथ रखा जा सकता है? डिडिमोस क्षुद्रग्रह, और इसका छोटा चंद्रमा डिमोर्फोस, एक द्विआधारी क्षुद्रग्रह प्रणाली के रूप में जाना जाता है। वे डीएआरटी मिशन के लिए एकदम सही लक्ष्य थे, क्योंकि टकराव के प्रभावों को डिमोर्फोस की कक्षा में परिवर्तन में आसानी से मापा जा सकता था। वे पृथ्वी के भी करीब हैं, या कम से कम एनईओ हैं। और वे एक बहुत ही सामान्य प्रकार के क्षुद्रग्रह हैं जिन्हें हमने पहले अच्छी तरह से नहीं देखा था। यह भी सीखने का मौका मिला कि द्विआधारी क्षुद्रग्रह कैसे बनते हैं, यह सोने पर सुहागा था। बहुत सी द्विआधारी क्षुद्रग्रह प्रणालियों की खोज की गई है, लेकिन ग्रह वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि वे कैसे बनते हैं। नए अध्ययनों में से एक में, अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के ओलिवियर बार्नौइन के नेतृत्व में एक टीम ने सतह के खुरदरापन और क्रेटर रिकॉर्ड को देखकर सिस्टम की उम्र का अनुमान लगाने के लिए डीएआरटी और लिसियाक्यूब की छवियों का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि डिडिमोस लगभग एक करोड़ 25 लाख वर्ष पुराना है, जबकि इसका चंद्रमा डिमोर्फोस 300,000 साल से भी कम समय पहले बना था। यह भले बहुत बड़ा लगे, लेकिन यह अपेक्षा से बहुत छोटा है। पत्थरों का ढेर डिमोर्फोस भी कोई ठोस चट्टान नहीं है जैसा कि हम आम तौर पर कल्पना करते हैं। यह पत्थरों का एक मलबे का ढेर है जो मुश्किल से एक साथ बंधे हुए हैं। इसकी कम उम्र के साथ, यह दर्शाता है कि बड़े क्षुद्रग्रहों के टकराव के मद्देनजर इन मलबे के ढेर वाले क्षुद्रग्रहों की कई पीढ़ियाँ हो सकती हैं। सूरज की रोशनी वास्तव में क्षुद्रग्रहों जैसे छोटे पिंडों के घूमने का कारण बनती है। जैसे ही डिडिमोस एक लट्टू की तरह घूमने लगा, उसका आकार पिचक गया और बीच में उभर आया। यह बड़े टुकड़ों के मुख्य ढेर से लुढ़कने के लिए पर्याप्त था, कुछ के तो निशान भी छूट गए। इन टुकड़ों ने धीरे-धीरे डिडिमोस के चारों ओर मलबे का एक घेरा बना दिया। समय के साथ, जैसे-जैसे मलबा आपस में चिपकने लगा, इससे छोटे चंद्रमा डिमोर्फोस का निर्माण हुआ। अमेरिका में ऑबर्न विश्वविद्यालय के मौरिज़्यो पाजोला के नेतृत्व में एक अन्य अध्ययन में इसकी पुष्टि के लिए बोल्डर वितरण का उपयोग किया गया। टीम ने यह भी पाया कि मनुष्यों द्वारा देखे गए अन्य गैर-बाइनरी क्षुद्रग्रहों की तुलना में वहां काफी अधिक (पांच गुना तक) बड़े पत्थर थे। एक अन्य नए अध्ययन से हमें पता चलता है कि अब तक जितने भी क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष अभियानों (इटोकावा, रयुगु और बेन्नू) पर गए हैं, उन पर पत्थरों का आकार संभवत: एक ही तरह का था। लेकिन डिडिमोस प्रणाली पर बड़े पत्थरों की यह अधिकता बायनेरिज़ की एक अनूठी विशेषता हो सकती है। अंत में, एक अन्य पेपर से पता चलता है कि इस प्रकार के क्षुद्रग्रह में दरार पड़ने की संभावना अधिक होती है।

रूस की सेना ने रणनीतिक परमाणु हथियारों के साथ तीसरे दौर का अभ्यास शुरू

मास्को। रूस की सेना ने बुधवार को रणनीतिक परमाणु हथियारों के साथ तीसरे दौर का अभ्यास शुरू किया, जिसके जरिए वह पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहती है कि वे यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन घटाएं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास में मध्य और दक्षिणी सैन्य जिलों की इकाइयां भाग ले रही हैं जिनके पास छोटी दूरी की इस्कंदर मिसाइलें हैं। वे गोदाम से परमाणु हथियारों को निकालने तथा उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में तैनात करने का अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास में वायुसेना की इकाइयां भी हिस्सा लेंगी जो अपने लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करेंगी तथा गश्त उड़ान भरेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का इरादा लड़ाकू मिशन के लिए सैनिकों की तैयारियों को परखना है। रणनीतिक परमाणु हथियारों में बम, छोटी दूरी की मिसाइलों में लगाए जाने वाले परमाणु आयुध, गोलाबारूद आदि शामिल होते हैं और वे जंग के मैदान के लिए होते हैं।

बीबीसी के पूर्व एंकर ने बच्चों की अश्लील तस्वीरें साझा करने किया दोष स्वीकार

भाषा। लंदन

बीबीसी के पूर्व शीर्ष समाचार प्रस्तोता ह्यू एडवर्ड्स ने बच्चों की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के तीन मामलों में बुधवार को गुनाह कबूल किया। सेंट्रल लंदन में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 26 मिनट की सुनवाई के दौरान उन्होंने जिन अपराधों के लिए दोष कबूल किया, उनमें दिसंबर 2020 और अगस्त 2021 के बीच व्हाट्सएप पर साझा की गई तस्वीरें शामिल थीं। ए तस्वीरें एक व्यक्ति द्वारा साझा की गई थीं, जिसने शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्ड्स से संपर्क किया था।

एडवर्ड्स दो दशकों तक बीबीसी के रात्रिकालीन समाचार कार्यक्रमों में मुख्य एंकर रहे। उन्होंने 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक प्रसारक के कवरेज का नेतृत्व किया था। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तक उन्हें जमानत दी गई है। उन्हें अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने माना कि निलंबित सजा भी उचित हो सकती है।

एडवर्ड्स (62) मैसेजिंग सेवा पर एक वयस्क व्यक्ति के साथ ऑनलाइन चैट में शामिल थे, जिसने उन्हें 377 अश्लील तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें से 41 तस्वीरें बच्चों से संबंधित थीं। भेजी गई तस्वीरों में से सात तस्वीरें श्रेणी ए की थीं। ज्यादातर बच्चों की अनुमानित उम्र 13 से 15 साल के बीच थी, लेकिन एक की उम्र सात से नौ साल के बीच थी। एडवर्ड्स को अलग-अलग शिकायतों के चलते जुलाई 2023 में बीबीसी से निलंबित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया।

भारत में लड़ाकों को भर्ती करना चाहता है इस्लामिक स्टेट आईएल-के: संयुक्त राष्ट्र

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवंत-खोरासान (आईएसआईएल-के) भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद इस देश में स्थित अपने आकाओं के माध्यम से ऐसे लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले ही हमलों को अंजाम दे सकें। आईएसआईएल, अल-कायदा और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को यहां जारी की गई। इसमें कहा गया है कि सदस्य देशों ने चिंता जताई है कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाला आतंकवाद क्षेत्र में असुरक्षा का कारण बनेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद आईएसआईएल-के देश में अपने आकाओं के जरिए ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमलों को अंजाम दे सके और उसने उर्दू में हिंदू-मुस्लिम द्वेष को बढ़ाने वाली तथा भारत के संबंध में अपनी रणनीति को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि आईएसआईएल-के इस क्षेत्र में सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है, जो अफगानिस्तान से परे आतंक फैला रहा है, जबकि अल-कायदा रणनीतिक संयम बरतता है और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है।

रिपोर्ट के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी), तालिबान और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) के बीच समर्थन और सहयोग बढ़ा है। वे अफगानिस्तान में लड़ाकों और प्रशिक्षण शिविर साझा कर रहे हैं और तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टीजेपी) के बैनर तले अधिक घातक हमले कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है, अत: टीटीपी अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक पनाह देने वाले संगठन में तब्दील हो सकता है। मध्यम अवधि में, टीटीपी और एक्यूआईएस का संभावित विलय पाकिस्तान और अंतत: भारत, म्यांमा और बांग्लादेश के खिलाफ खतरा बढ़ा सकता है। कुछ सदस्य देशों ने अनुमान जताया है कि आईएसआईएल-के के लड़ाकों की संख्या 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गई है।

इजराइल की हिरासत में फलस्तीनी कर रहे उत्पीड़न व दुर्व्यवहार का सामना : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सात अक्टूबर के हमलों के बाद इजराइल के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को वाटरबोर्डिंग , अनिद्रा, करंट लगाए जाने समेत कई अन्य उत्पीड़न व दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। वाटरबोर्डिंग एक तरह की यातना होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे को कपड़े से ढककर पानी डाला जाता है, जिससे व्यक्ति को डूबने जैसा एहसास होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइली कारागार विभाग ने जून के अंत तक 9,400 से अधिक लोगों को हिरासत में रखा, जिनमें से कुछ को खुफिया जगह पर रखा गया है, जहां उन्हें वकीलों से मिलने या कानूनी अधिकारियों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा रही। पूर्व कैदियों और अन्य सूत्रों से बातचीत पर आधारित इस रिपोर्ट में हिरासत में लिए गए लोगों की चौंका देने वाली संख्या पर हैरानी जताई गई है, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने एक बयान में कहा, मेरे कार्यालय और अन्य संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों से कई भयावह कृत्यों का संकेत मिलता है, जैसे कैदियों को पानी डालकर प्रताड़ित करना, उन पर कुत्ते छोड़ना आदि। यह अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर हनन है। सात अक्टूबर को हमास के दक्षिण इजराइल पर अचानक हमले करने के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। हमास के हमलों में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक को बंधक बना लिया गया था।

भारत से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नया ब्रिटिश संसदीय समूह गठित

लंदन। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित ब्रिटिश संसद में एक नया सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी) गठित किया गया है। इस समूह के गठन का उद्देश्य व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। इस सप्ताह की शुरुआत में औपचारिक रूप से इस समूह का गठन किया गया था। इस समूह की सह-अध्यक्षता हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्रॉसबेंच पीयर करण बिलिमोरिया और नए ब्रिटिश सिख लेबर सांसद जीवुन संधेर द्वारा की जाएगी। बिलिमोरिया ने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि हम ब्रिटेन-भारत साझेदारी का जश्न उसी समय मना रहे हैं, जब हमने नई इंडिया एपीपीजी की शुरुआत की है, जिसकी सह-अध्यक्षता करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है।

पेरिस में असम राइफल के साथ कुत्ते पेरिस ओलम्पिक में तैनात किए गए हैं

चीन का जापान पर क्वॉड देशों के साथ मानहानिकारक हमलों का आरोप

बीजिंग। चीन ने जापान पर अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ताओं के दौरान उसके खिलाफ मानहानिकारक हमले करने का आरोप लगाया है। एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने एक दिन पहले जापान दूतावास में मिशन उप प्रमुख अकीरा योकोची के साथ बैठक के दौरान हालिया घटनाक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। लियू ने कहा कि चीन पर जापान के मानहानिकारक हमले दोनों देशों के बीच रणनीतिक व पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के उसके रुख के विपरीत हैं। जापान की राजधानी तोक्यो में हुई बैठक के दौरान जापानी विदेश और रक्षा मंत्रियों ने अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच यह बैठक हुई थी।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि चीन अपनी विदेश नीति के जरिए अपने फायदे के लिए वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देना चाहता है और इस तरह के व्यवहार से हिंद-प्रशांत क्षेत्र और इससे बाहर एक बड़ी सामरिक चुनौती उत्पन्न हुई है। अमेरिका-जापान के बीच वार्ता के बाद क्वॉड समूह में शामिल देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। जारी संयुक्त बयान में चीन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विवादित मुद्दों में सैन्य दखल बढ़ाने और दक्षिण चीन सागर व धमकी भरे युद्धाभ्यास के प्रति विरोध व्यक्त किया। चीन ने अमेरिका पर उसके (चीन के) बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का आरोप लगाया है। चीन जापान से उसके (चीन के) आंतरिक मामलों के बारे में गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी बंद करने का आग्रह करता है।

बोइंग को दूसरी तिमाही में 1.4 अरब डॉलर का घाटा नया सीईओ नियुक्त किया

शिकागो (अमेरिका)। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को दूसरी तिमाही में 1.4 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि रॉकवेल कॉलिन्स के पूर्व सीईओ 64 वर्षीय रॉबर्ट केली ऑर्टबर्ग अगले सप्ताह बोइंग के सीईओ के रूप में कामकाज संभालेंगे। बोइंग का घाटा काफी अधिक रहा है जबकि आमदनी वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कम रही है। राजस्व में एक साल पहले की तुलना में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है और इसके वाणिज्यिक-विमान कारोबार और रक्षा इकाई दोनों को नुकसान हुआ। निराशाजनक परिणाम बोइंग के लिए उथल-पुथल भरे समय में आए हैं। कंपनी ने मैक्स के संबंध में धोखाधड़ी के लिए दोषी होने की दलील पर सहमति व्यक्त की है। इनमें से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें 346 लोग मारे गए थे।

स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस फाइनल और सेन-सिंधू प्री क्वार्टरफाइनल में

भाषा। पेरिस

भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने बुधवार को यहां पेरिस ओलंपिक में पुरूषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया जबकि देश के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और मुक्केबाजी की स्पर्धाओं में अगले दौर में प्रवेश किया।

निशानेबाज कुसाले फाइनल में, ऐश्वर्य चूके : कुसाले ने जहां फाइनल के लिए क्वालीफाई किया वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर चूक गए। कुसाले क्वालीफाइंग दौर में 590 (38 एक्स) का स्कोर करके सातवें स्थान पर रहे। वहीं ऐश्वर्य प्रताप 589 (33 एक्स) का स्कोर करके 11वें स्थान पर रहे। शीर्ष आठ निशानेबाज ही फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं। कुसाले ने नीलिंग में 198 (99 और 99), प्रोन में 197 (98 और 99) और स्ट्रैंडिंग पोजिशन में 195 (98 और 97) स्कोर किया। वहीं ऐश्वर्य प्रताप ने नीलिंग में 197 (98 और 99), प्रोन में 199 (100 और 99) और स्ट्रैंडिंग पोजिशन में 193 (95 और 98) स्कोर किया। स्पर्धा का फाइनल बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। पिछले साल हांगझोउ एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप और अखिल श्योराण ने टीम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। कुसाले कोल्हापूर में तेजस्विनी सावंत के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। वह पिछले साल एशियाई खेलों में इस स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में चौथे स्थान पर रहे थे।

आत्मविश्वास से भरी मुक्केबाज लवलीना पदक जीतने से महज एक कदम दूर : तोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किलो) ने अपने पहले मुकाबले में नॉर्वे की सुन्निवा होफ्स्टाड को 5 . 0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। लवलीना ने तोक्यो में 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। वह लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने और भारतीय मुक्केबाजी में अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम करने से महज एक जीत दूर हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब उनका सामना चार अगस्त को शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लि कियान से होगा। इस मुकाबले में जीत से लवलीना का कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाएगा। प्रीति पवार को हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार देर रात प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की पैन अमेरिकन खेलों की चैंपियन और विश्व रजत पदक विजेता एनी मार्सेला एरियास को कड़ी चुनौती दी लेकिन इसके बावजूद उन्हें 2-3 के विभाजित फैसले से हार का सामना करना पड़ा।

सेन और सिंधू एकल प्री क्वार्टरफाइनल में : भारतीय बैडमिंटन के स्टार लक्ष्य सेन और पी वी सिंधू ने अपने अपने मुकाबले शानदार ढंग से जीतकर एकल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने एस्तोनिया की क्रिस्टीन कूबा को 33 मिनट तक चले एकतरफा मुकाबले में 21 . 5, 21 . 10 से हराया। रियो ओलंपिक में रजत और तोक्यो में कांस्य पदक जीतने वाली सिंधू दुनिया की नौवे नंबर की खिलाड़ी चीन की ही बिंगजियाओ से खेल सकती है जिसके खिलाफ वह 11 बार हारी और नौ बार जीती हैं। वहीं विश्व चैम्पियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता अलमोड़ा के तेईस वर्ष के लक्ष्य ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 50 मिनट में 21 . 18, 21 . 12 से मात दी। लक्ष्य का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में हमवतन एच एस प्रणय से हो सकता है जो आखिरी ग्रुप मैच में वियतनाम के ली डुक फाट से खेलेंगे। लक्ष्य ने इससे पहले क्रिस्टी को सिर्फ एक बार चार साल पहले बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में हराया था। दोनों के बीच ओलंपिक मुकाबले से पहले हुए पांच में से चार मुकाबले क्रिस्टी ने जीते थे।

अनुभवी तीरंदाज दीपिका प्री क्वार्टर फाइनल में : भारत की अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने लगातार दो मुकाबले जीतकर महिला व्यक्तिगत वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेश कर लिया। कुछ दिन हले भारतीय महिला तीरंदाजों की टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से हार गई थी जिसमें दीपिका के प्रदर्शन की काफी आलोचना हुई थी। दीपिका ने व्यक्तिगत वर्ग में पहले एस्तोनिया की रीना परनाट को शूटआफ में 6 . 5 से हराया। इसके बाद नीदरलैंड की क्विंटी रोफेन को 6 . 2 से मात दी। अब उनका सामना प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की मिशेले क्रोपेन से होगा।

टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला प्री क्वार्टर फाइनल में : श्रीजा अकुला ने सिंगापुर की जियान झेंग को 51 मिनट तक कड़े मुकाबले में 4 . 2 से हराकर टेबल टेनिस महिला एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अपने 26वें जन्मदिन पर श्रीजा ने 9 . 11, 12 . 10, 11 . 4, 11 . 5, 10. 12, 12 . 10 से जीत दर्ज की। श्रीजा का सामना अब चीन की नंबर एक खिलाड़ी सुन यिंगशा से होगा। इससे पहले मनिका बत्रा भी अंतिम 16 में जगह बना चुकी हैं। भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। घुड़सवारी में अनुष अग्रवाला व्यक्तिगत ड्रेसेज में पदक की दौड़ से बाहर हुए: भारत के अनुष अग्रवाला ओलंपिक घुड़सवारी के व्यक्तिगत ड्रेसेज में अपने ग्रुप में 66.444 अंक के साथ नौवें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से चूके।

अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे भारतीय एथलीट, नीरज चोपड़ा पर होगी निगाहें

पेरिस। भारत का 29 सदस्ईय दल पेरिस ओलंपिक खेलो मे गुरुवार से शुरू होने वाली एथलेटिक प्रतियोगिता मे जब अपना अभियान शुरू करेगा तो सभी की निगाह नीरज चोपड़ा पर टिकी रहेगी जो भाला फेंक मे अपने खिताब का बचाव करके भारतीय खेलो के इतिहास मे नया अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। चोपड़ा मामूली चोटो के कारण ओलंपिक से पहले अधिक प्रतियोगिताओ मे भाग नही ले पाए थे लेकिन इसके बावजूद उन्हे लगातार दूसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। चोपड़ा अगर आठ अगस्त को स्वर्ण पदक जीतने मे सफल रहते है तो वह भाला फेंक मे अपने खिताब का बचाव करने वाले दुनिया के पांचवे खिलाड़ी और लगातार दो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले एरिक लेमिंग (स्वीडनअ 1908 और 1912), जॉनी मायरा (फिन्नलैंडअ 1920 और 1924), जान ज़ेलेज़नी (चेक गणराज्यअ 1992, 1996 और 2000) और एंड्रियास थोरकिल्डसन (नॉर्वेअ 2004 और 2008) ही ऐसे खिलाड़ी है जिन्होने ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा मे अपने खिताब का बचाव किया। चोपड़ा ने इस साल केवल तीन प्रतियोगिताओ मे भाग लिया लेकिन यह 26 वर्षीय खिलाड़ी इसलिए स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार है क्योकि विश्व स्तर पर उनका कोई भी अन्य प्रतिद्वंदी इस सत्र मे असाधारण प्रदर्शन नही कर पाया है।इस भारतीय एथलीट ने मई मे दोहा डायमंड लीग मे हिस्सा लिया था जिसमे उन्होने 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था जो इस सत्र मे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। उन्होने इसके बाद एहतियात के तौर पर ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक से नाम वापस ले लिया, क्योकि वह अपनी जांघ की मांसपेशियो मे दर्द महसूस कर रहे थे। चोपड़ा, जिनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर है, ने 18 जून को फिन्नलैंड मे पावो नूरमी खेलो मे 85.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर मजबूत वापसी की। उन्होने पेरिस डायमंड लीग से बाहर होने का विकल्प चुना। उनके कोच ने बाद मे चोपड़ा की फिटनेस को लेकर चिंताओ को खारिज कर दिया।पिछले ओलंपिक खेलो के बाद चोपड़ा ने जिन 15 प्रतियोगिताओ मे भाग लिया उनमे से केवल दो बार उन्होने 85 मीटर से कम भाला फेंका।

ओलंपिक पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	8	6	2	16
जापान	७	2	4	13
फ्रांस	6	9	6	21
ऑस्ट्रेलिया	6	4	2	12
कोरिया	5	3	3	11
अमेरिका	4	11	12	27
ग्रेट ब्रिटेन	6	6	5	17
इटली	3	5	4	12
कनाडा	2	2	2	6
हांगकांग	2	0	1	3
भारत	0	0	2	2

पेरिस ओलंपिकः भारत का छठे दिन का कार्यक्रम

पेरिस।।भारत का पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को यहां छठे दिन का कार्यक्रम (भारतीय समयानुसार) इस प्रकार है।

गोल्फ: पुरुष व्यक्तिगत फाइनल: गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा - दोपहर 12.30 बजे

निशानेबाजी:पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (फाइनल): स्वप्निल कुसाले - दोपहर 1.00 बजे, महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (क्वालीफिकेशन): सिफत कौर सामरा और अंजुम मौदगिल - दोपहर 3.30 बजे

हॉकी: भारत बनाम बेल्जियम (ग्रुप चरण मैच): दोपहर 1.30 बजे

मुक्केबाजी: महिला फ्लाईवेट (प्री-क्वार्टरफाइनल): निकहत जरीन बनाम यू वू (चीन) - दोपहर 2.30 बजे

तीरंदाजी: पुरुष व्यक्तिगत (1132 एलिमिनेशन): प्रवीण जाधव बनाम काओ वेनचाओ (चीन) - दोपहर 2.31 बजे, पुरुष व्यक्तिगत (1116 एलिमिनेशन): दोपहर 3.10 बजे से

टेबल टेनिस: महिला एकल (क्वार्टर फाइनल): दोपहर 1.30 बजे से

नौकायन: पुरुष डिंगी रेस एक: विष्णु सरवनन : दोपहर 3.45 बजे

पुरुष डिंगी रेस 2: विष्णु सरवनन : रेस। के बाद

महिला डिंगी रेस एक: नेथ्रा कुमानन : शाम 7.05 बजे

महिला डिंगी रेस दो: नेथ्रा कुमानन - रेस। के बाद।

सात्विक-चिराग की जोड़ी के सामने क्वार्टर फाइनल में चिया-सोह की मजबूत चुनौती

पेरिस। भारतीय शटलर सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी गुरुवार को यहां पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में तोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलेशिया के आरोन चिया और सोह वूई यिक की चुनौती का सामना करेगे। सात्विक और चिराग की पूर्व विश्व नंबर एक जोड़ी अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप सी में शीर्ष स्थान हासिल किया। बुधवार शाम यहां ड्रा के बाद चिया और सोह के खिलाफ रखा गया है। मलेशियाई जोड़ी ग्रुप ए में चीन की विश्व नंबर एक लियांग वेई केंग और वांग चांग के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। मलेशियाई जोड़ी ग्रुप ए में चीन की विश्व नंबर एक लियांग वेई केंग और वांग चांग के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। चिया और सोह का एक समय सात्विक और चिराग के खिलाफ 8-0 का जबरदस्त रिकॉर्ड था, लेकिन भारत जोड़ी ने पिछले तीनों मैचों को जीतकर अपने रिकॉर्ड में सुधार किया। भातरीय जोड़ी अगर इस मुकाबले को जीतने में सफल रही तो उसके सामने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त लियांग एवं वांग की जोड़ी और इंडोनेशिया के फजर अल्फियान एवं मुहम्मद रियान अर्दियांतो के बीच खेले जाने वाले एक अन्य क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगी।अनुष अग्रवाला घुड़सवारी के व्यक्तिगत ड्रेसेज फाइनल में जगह बनाने में विफलपेरिस, 31 जुलाई (भाषा) भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला ओलंपिक में घुड़सवारी के व्यक्तिगत ड्रेसेज में बुधवार को यहां फाइनल में जगह बनाने में विफल रहे। अनुष अपने घोड़े सर कारमेलो के साथ अपने ग्रुप में कुल 66.444 अंक के साथ नौवें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में कुल 60 घुडसवार भाग ले रहे थे जिन्हें 10-10 के छह ग्रुप में बांटा गया था। फाइनल के लिए 18 घुड़सवारों ने क्वालीफाई किया जिसमें डेनमार्क की लॉड्रुप-डुफोर कैथरीन अपने घोड़े फ्रीस्टाइल के साथ 80.792 अंक के साथ शीर्ष पर रही। सिसोजेवा सैंड्रा अपने घोड़े मैक्सिमा बेला के साथ क्वालीफाई करने वाली आखिरी खिलाडी रही। पोलैंड की इस घुड़सवार ने 73.416 अंक बनाए। घुड़सवारी ड्रेसेज में पुरुष और महिला खिलाड़ी एक साथ प्रतिस्पर्धा करते है।

नोवाक जोकोविच क्वार्टरफाइनल में

पेरिस। सर्बिया के शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच ने बुधवार को यहां ओलंपिक खेलों की टेनिस स्पर्धा के पुरुष एकल में जर्मनी के डोमिनिक कोपफर पर 7-5, 6-3 की जीत से क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। जोकोविच ने इस तरह चौथी बार ओलंपिक एकल क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई और अब उनकी निगाहें अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने पर लगी होंगी क्योंकि यही पदक उनकी कैबिनेट में मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुका यह 37 वर्षीय खिलाड़ी बीजिंग 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुका है। इस दफा टेनिस मुकाबले रोलां गैरों में हो रहे हैं जहां जोकोविच तीन मेजर खिताब जीत चुके हैं। अब बृहस्पतिवार को उनका सामना स्टेफानोस सिटसिपास से होगा जिसे जोकोविच ने 2021 में कोर्ट फिलिप चार्टियर पर हुए फाइनल में हराया था। सिटसिपास ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज को 7-5, 6-। से हराया।

तूफान के कारण पेरिस में हाई-स्पीड ट्रेनों की सेवा बाधित, ओलंपिक के दौरान यात्री फंसे

पेरिस। स्थानीय तूफान ने पेरिस को देश के दक्षिण-पूर्व के साथ-साथ स्विट्जरलैंड से दोनों दिशाओं में जोड़ने वाली सभी हाई-स्पीड ट्रेन यातायात को बुधवार को बाधित कर दिया। फ्रांस की रेल कंपनी एसएनसीएफ ने कहा कि इससे ओलंपिक और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले वाले हजारों यात्री फंसे हुए हैं। एसएनसीएफ ने कहा कि रेल पटरियों पर पेड़ गिरने के कारण फ्रांस की राजधानी के गारे डे ल्योन ट्रेन स्टेशन से रवाना होने वाली और वहां पहुंचने वाली सभी हाई-स्पीड ट्रेनों की सेवाओं को रोकना पड़ा है। पेरिस के दक्षिण-पूर्व में बरगंडी में एक ट्रेन पेड़ से टकरा गई। नियमित गति वाली ट्रेन अलग-अलग ट्रैक का उपयोग करती हैं और उनकी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।एसएनसीएफ ने कहा कि अधिकारियों ने ट्रैक से बिजली काट दी और पेड़ को हटाने का काम शुरू हो चुका है। इस सेवा को शुरू करने में हालांकि अधिक समय लगेगा इस लिए स्टेशन से निकलने वाली सारी ट्रेनों को वापस बुला लिया गया है ताकि लोग यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन खोज सके। इससे पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले तोड़फोड़ के कारण फ्रांस की ट्रेन यातायात गंभीर रूप से बाधित हुई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाई-स्पीड ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई थीं। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी मेटियो फ्रांस ने बुधवार को देश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और हवा सहित स्थानीय रूप से मजबूत तूफान के खतरे के बारे में चेतावनी दी है। मेटियो फ्रांस ने देश के अधिकांश हिस्से में बुधवार को लगातार तीसरे दिन गर्मी की चेतावनी जारी की है जिसमें, पेरिस में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस (88 डिग्री फारेनहाइट) तक पहुंच गया।

सूर्या भाई ने श्रृंखला में गेंदबाजी के लिए तैयार रहने को कहा था: रिंकू सिंह

पालेकल।(भाषा) भारत के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में स्टार बनकर उभरे, लेकिन बल्लेबाजी में नहीं बल्कि गेंदबाज की भूमिका में। मेजबान टीम जब आठ विकेट पर 137 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की ओर बढ़ रही थी तब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद रिंकू को थमा दी तब प्रतिद्वंद्वी टीम को 12 गेंद पर नौ रन की जरूरत थी। इस 26 वर्षीय दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर ने हालांकि निराश नहीं किया। उन्होंने अपने एकमात्र ओवर में दो विकेट चटकाए। इसमें उन्होंने सिर्फ तीन रन दिए और कुसल परेरा और रमेश मेंडिस के विकेट लिए। फिर 20 ओवर के बाद स्कोर बराबर होने के कारण मैच सुपर ओवर में चला गया जिसमें भारत विजेता रहा। रिंकू ने बाद में स्वीकार किया कि सूर्या ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, मैंने घरेलू क्रिकेट में काफी विकेट लिए हैं और मैंने वनडे में भी एक विकेट लिया है। सूर्या ने मुझे श्रृंखला में गेंदबाजी के लिए तैयार रहने के लिए कहा था।

क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय हाकी टीम के सामने बेल्जियम की कठिन चुनौती

पेरिस। क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक के पूल बी के मैच में बृहस्पतिवार को मौजूदा चैम्पियन बेल्जियम के रूप पहली कठिन चुनौती का सामना करेगी तो उसे प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी। बेल्जियम पूल बी में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है जबकि भारत दो जीत और एक ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया दो जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना ने भी तीन मैचों में एक जीत , एक ड्रॉ और एक हार के साथ अंतिम आठ में जगह

बना ली है। न्यूजीलैंड और आयरलैंड लगातार तीन हार के साथ दौड़ से बाहर हो गए हैं। हर पूल से शीर्ष चार टीमें ही अंतिम आठ में पहुंचेंगी। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3 . 2 से हराया और फिर आखिरी मिनट में किए गए गोल की मदद से 2016 की चैम्पियन अर्जेंटीना को ड्रॉ पर रोका। आयरलैंड के खिलाफ भारत ने 2 . 0 से जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पहले दोनों मैचों में निर्णायक गोल दागे और फिर आयरलैंड के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक पर पहला और पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे मिडफील्डर मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने भी आयरलैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके कई मौके बनाए। मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय, गुरजंत सिंह और सुखजीत सिहं ने भी दबाव बनाए रखा। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे राइट बैक जरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं जिन्होंने अब तक काफी प्रभावी प्रदर्शन किया है। पहले दो मैचों में 19 पेनल्टी कॉर्नर गंवाने वाली भारतीय टीम के गोलकीपर पी आर श्रीजेश की तारीफ करनी होगी जिन्होंने कई गोल बचाए। बेल्जियम के बाद भारत को शुक्रवार को आस्ट्रेलिया से खेलना है।

धावकों को रेपेचेज दौर से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मिलेगा मौका

सेंट-डेनिस (फ्रांस) (एपी) ओलंपिक ट्रैक प्रतियोगिता में एक नए नियमों के कारण बाधा और फर्राटा दौड़ धावकों को शुरुआती चरण में पिछड़ने के बाद भी रेपेचेज दौर से इन खेलों में अगले दौर में आगे बढ़ने और ओलंपिक पदक जीतने का एक और मौका मिलेगा। इस ओलंपिक खेल में बाधा दौड़ स्पर्धाओं सहित 200 मीटर से 1500 मीटर तक की सभी व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में रेपेचेज राउंड शुरू किया जाएगा। अब प्रत्एक हीट में शीर्ष पर रहने वाले खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिलेगा जबकि अन्य खिलाड़ियों को रेपेचेज के जरिए यहां पहुंचने का मौका मिलेगा।ओलंपिक में भाग ले रहे कई खिलाड़ियों के लिए हालांकि यह पहला मौका होगा जब उन्हें रेपेचेज दौर से गुजरना पड़ेगा। ज्यादा खिलाडी इसका हिस्सा होने से बचते हुए अपनी हीट में शीर्ष पर रह कर क्वालीफाई करना चाहेंगे। कई खिलाडियों ने एथलेटिक्स में इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी है जो सही से इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी ओलंपिक ट्रायल में 100 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन मसाई रसेल ने कहा, यह एक तरह से मेकअप क्विज (दूसरे मौके) जैसा है। उन्होंने कहा, आप अगर पहले प्रयास में सही नहीं कर सके तो आपके पास एक और मौका होगा। यह वास्तव में अच्छा है क्योंकि रेस में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हालांकि इसका

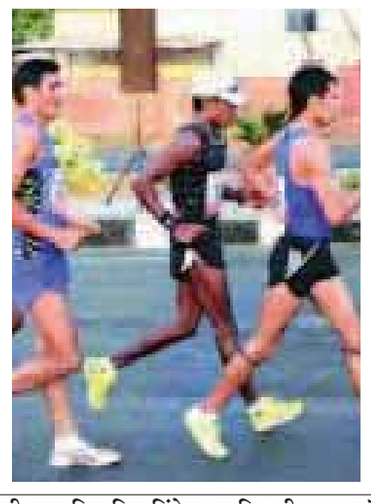

इस्तेमाल करने से बचना चाहूंगा। रेपेचेज को इस्तेमाल नौकायन, कुश्ती और मार्शल आर्ट में होता रहा है लेकिन अब इसका इस्तेमाल ट्रैक स्पर्धाओं में भी होगा। रेपेचेज एक फ्रांसीसी शब्द पर आधारित जिसका अर्थ है दूसरा मौका। इससे पहले अपनी-अपनी हीट में शीर्ष पर रहने के अलावा उन चुनिंदा धावकों को अगले दौर में क्वालीफाई करने का मौका मिलता था जो हीट विजेताओं के अलावा सबसे कम समय में रेस पूरी करते थे। इसमें कुछ हीट में दूसरे स्थान पर रहने वाले धावक आगे बढ़ने से चूक जाते थे। अब नियमों में बदलाव के बाद हर हीट में दूसरे स्थान पर रहने वाले धावक रेपेचेज दौर से सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहेंगे। जब 2022 में रेपेचेज नियम पारित किया गया था तब विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने इसे एक बदलाव कहा था जो इन आयोजनों को एथलीटों के लिए आगे बढ़ने को अधिक सरल बना देगा। इससे प्रशंसकों और प्रसारकों के लिए भी चीजें साफ होंगी। रेपेचेज दौर हालांकि खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि उन्हें एक अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।अमेरिकी 400 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी और पदक के प्रबल दावेदार राय बेंजामिन ने कहा, मैंने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। लेकिन, ईमानदारी से कहूं तो इतनी गर्मी में मैं इससे बचना चाहूंगा।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।